CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. VII, Third Session, 2020/1941 (Saka)
No. 3, Monday, February 03, 2020/ Magha 14, 1941 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 1 to 8, 10, 13 and 18	10-62
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 9, 11, 12, 14 to 17, 19 and 20	63-83
Unstarred Question Nos. 1 to 230	84-656

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 658-680

ASSENT TO BILLS 681

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

12th Report 682

MATTERS UNDER RULE 377 685-704

(i) Need to take remedial measures to tackle locust attack destroying crops in Rajasthan

Shri Nihal Chand Chauhan 685

(ii) Need to shift Krishi Vigyan Kendra in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan, to a suitable place in the constituency

Shrimati Jaskaur Meena 686

(iii) Need to develop Mohanpura Dam in Madhya Pradesh as a tourist place

Shri Rodmal Nagar 686

(iv) Need to include Kolar Parliamentary Constituency in Jal Shakti Abhiyan Project

Shri S. Muniswamy 687

(v) Regarding shortage of officers and staff in Union Territory of Ladakh

Shri Jamyang Tsering Namgyal 688

(vi) Need to ban organizations spreading terror in the country

Shri Tejasvi Surya 689

(vii) Need to develop historical Charkhari fort in Bundelkhand region of Uttar Pradesh

Kunwar Pushpendra Singh Chandel 690

(viii) Regarding disposal of E-waste

Shri Anurag Sharma 691

(ix) Need to increase annual cash withdrawal limit from banks for retail traders to Rs. 5 crore per year

Shri Mukesh Rajput 692

(x) Need to sanction funds for construction of railway line from Dehradun to Kalsi in Uttarakhand

Shrimati Mala Rajya Laxmi Shah 692

(xi) Need to restart Integrated Action Plan/Additional Central Assistance programme for Left Wing Extremism affected districts in the country

Shri Sushil Kumar Singh 693

(xii) Need to allocate Rajasthan its due share of water for Sidhmukh Nohar Irrigation Project

Shri Rahul Kaswan 694

(xiii) Need to ensure participation of members of Parliament in decision making process for utilisation of funds collected under District Mineral Foundation for development works in Chhattisgarh

Shri Mohan Mandavi 695

(xiv) Need to extend benefit of Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana to families found eligible in Jalgaon district, Maharashtra

Shrimati Raksha Nikhil Khadse 695

(xv) Regarding shortage of funds under MGNREGA

Sushri S. Jothimani 696

(xvi) Need to create post of clinical pharmacist for Pharm. D graduates

Shri Rajmohan Unnithan 697

(xvii) Regarding water problem of Tamil Nadu

Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian 698

(xviii) Need to increase pension amount under EPS 95

Shri Bellana Chandra Sekhar 699

(xix) Regarding Citizenship Amendment Act

Prof. Sougata Ray 699

(xx) Need to formulate uniform policy addressing construction restrictions and buffer zones around Defence establishments

Shri Rahul Ramesh Shewale 700

(xxi) Need to consider cultivation of betel leave as an agricultural activity and grant the status of 'farmer' to betel leave growers in Bihar

Shri Kaushlendra Kumar 701

(xxii) Need to amend rules for CAMPA Funds

Shri Bhartruhari Mahtab 702

(xxiii) Need to promote poultry Industry

Dr. G. Ranjith Reddy 703

(xxiv) Need to construct four lane road on National Highway - 31 alongwith a Express highway from Rajauli to Bakhtiyarpur in Nawada Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Chandan Singh 704

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS 705-729, 731-801

Shri Parvesh Sahib Singh Verma 705-719

Shri Ram Kripal Yadav 720-729

Shri P.K. Kunhalikutty 731-733

Texts of Amendments 734-747

Shri Gaurav Gogoi 748-753

Shri T.R. Baalu 754-760

Sushri Mahua Moitra 761-764

Shri M.V. Midhun Reddy 765-769

Shri Vinayak Bhaurao Raut	770-774
Shri Pinaki Misra	775-780
Shri Ritesh Pandey	781-783
Shri Jasbir Singh Gill	784-785
Shri Sunil Dattatray Tatkare	786-787
Shri Ajay Misra Teni	788-792
Shri S. Jagathrakshakan	793-795
Adv A.M. Ariff	796-799
Shri Malook Nagar	800-801

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

Amendments to Motion of Thanks on the President's Address	730

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	802
Member-wise Index to Unstarred Questions	803-806

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	807
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	808

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, February 03, 2020/Magha 14 , 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 1, श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे।

…(व्यवधान)

(Q. 1, 10 and 18)

SHRI T. R. BAALU: Sir, you may suspend the Question Hour and take up discussion on NRC….(*Interruptions*)

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे: अध्यक्ष महोदय, भविष्य में कौशल विकास योजना, रोजगार और स्वयं रोजगार निर्माण करने में एक अहम् भूमिका निभाएगा । आने वाली शिक्षण प्रणाली में किताबी ज्ञान के साथ तकनीकी ज्ञान की जरुरत होगी।…(व्यवधान) अगर हम स्कूल में आठवीं कक्षा से दसवीं कक्षा तक के सिलेबस में वोकेशनल सब्जेक्ट जोड़ करके कौशल विकास को कम्पलसरी करें तो वह निश्चित रूप में आगे चल कर स्टूडेंट्स को अपना कैरियर खुद बनाने में मदद करेगा ।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कौशल विकास मंत्रालय, एचआरडी मंत्रालय के साथ ऐसी कोई संयुक्त नीति बनाने जा रहा है?…(व्यवधान)

11.02 hrs

(*At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)*

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी, हम एचआरडी मंत्रालय से जुड़ कर 9 हजार विद्यालयों में कौशल विकास का कार्य कर रहे हैं।…(व्यवधान) पीएमकेवीवाई, पार्ट-1 के बाद पीएमकेवीवाई, पार्ट-2 मार्च तक पूरा हो

रहा है ।...(व्यवधान) हम आगे के कदम उठाने में इस सुझाव पर भी विचार करने वाले हैं और अभी माननीय निर्मला सीतारमण जी ने बजट में इसका संकेत दिया है कि एजुकेशनल संस्थाओं और कौशल विकास योजना दोनों साथ मिल कर आगे बढ़ेंगे ।...(व्यवधान) इस नाते, हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे ।...(व्यवधान)

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है । कौशल विकास योजना के माध्यम से हमें रोजगार निर्माण करने में मदद मिलती है ।...(व्यवधान) कुछ प्रशिक्षणार्थियों को प्लेसमेंट मिल जाती है, परन्तु अगर कोई प्रशिक्षणार्थी खुद का व्यापार करना चाहे तो उसे कर्ज लेने के लिए भटकना पड़ता है ।...(व्यवधान) महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि युवकों में कौशल विकास के साथ ही उन्हें स्वयं रोजगार के लिए जरुरी धन भी मुहैया कराया जा रहा है ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कौशल विकास योजना के माध्यम से प्रशिक्षण लिए हुए प्रशिक्षणार्थियों को 'मुद्रा', अन्य कोई वित्तीय संस्था या कर्ज देने वाली संस्था से निश्चित मदद मिले, क्या इसके लिए कोई प्रावधान करने का नियोजन है, ताकि वह युवक अपने रोजगार का निर्माण खुद कर सके?...(व्यवधान)

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे विभाग के अंतर्गत उद्यमशीलता विकसित करने के लिए 'नीसबड' नाम की संस्था है और उसके थ्रू हम लोनिंग में मदद करते हैं ।...(व्यवधान) पीएमकेके केन्द्रों को 'मुद्रा' लोन देने के लिए नोडल केन्द्र बनाया जा रहा है, ताकि मुद्रा लोन दे कर, रोजगार के अवसर बढ़ाने में, उद्यम लगाने में, उन कौशल प्राप्त युवकों को सहायता प्राप्त हो ।...(व्यवधान) इसकी व्यवस्था पीएमकेके को 'मुद्रा' लोन का नोडल केन्द्र बना कर किया जा रहा है ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न काल में चर्चा हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारे देश का नौजवान प्रशिक्षित हो, दक्ष हो, स्किल्ड हो, इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न काल में, जब महत्वपूपर्ण विषय पर चर्चा हो रही हो तो आप अपने-अपने स्थान पर विराजें। यह मेरा आपसे आग्रह है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इस प्रश्न के साथ प्रश्न संख्या 10 और 18 को भी क्लब किया जाता है।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा - उपस्थित नहीं ।

माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र और संविधान तब बचेगा, जब सदन में चर्चा होगी। लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो सदन में चर्चा करें और संविधान को बचाना है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करें।

…(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, National Council Vocational Training (NCVT) courses are run both by the Union Government, and to a certain extent State Governments also provide skill training which has already completed more than five years since 2015. …(*Interruptions*) What has come to light and which has also been reported in various newspapers is that adequate skilling is not being done. I would like to understand from the Minister whether proper monitoring is being done by the Union Government relating to the NCVT in the country. …(*Interruptions*)

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण है ।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इसकी पूरी निगरानी की जा रही है और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए पुराने सिस्टम के तहत जो एनसीवीटी था, उसे एक स्वायत्तशासी स्वरूप में एनसीवीईटी के नाम से नये सिरे से उसका सृजन किया जा रहा है ताकि हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग मिले और उसकी निगरानी हो ।...(व्यवधान) जहाँ लापरवाही हो रही है, वहाँ कार्रवाई भी की जा रही है। ...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : My second supplementary is this. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana is a very forward looking Yojana by the Government and this is a programme which is supposed to skill our youth mass who can be engaged not only in our country but can also go abroad for employment. ...(*Interruptions*). There are two phases of PMKVY and the second phase is going to be over in 2020. My question is whether the Government is considering having proper monitoring by the respective State Governments and the third phase of PMKVY is going to be implemented from 2021 onwards. ...(*Interruptions*).

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा कि पीएमकेवीवाई पार्ट-टू 31 मार्च, 2020 को पूर्ण हो रही है ।...(व्यवधान) लेकिन पीएमकेवीवाई पार्ट वन और टू के जो अनुभव हैं, उनके आधार पर राज्यों से चर्चा करके आगे के लिए कार्य-योजना बनाई जा रही है । वह अंतिम रूप में है ।...(व्यवधान) उस कार्य-योजना के साथ-साथ उसमें मॉनिटरिंग की भूमिका बढ़ाई जा रही है । इसके साथ ही, हमारे देश के नौजवान कौशल्य प्राप्त करके अन्य देशों में

जाएँ, इसके लिए भी हम लोगों ने पहल की है।...(व्यवधान) सिंगापुर, सऊदी अरब, यूएई, जापान और फिनलैंड के साथ एमओयू साइन किया गया है।...(व्यवधान) वहाँ भी नौजवान लोग जा रहे हैं और उनको कौशल्य विकास में अंतर्देशीय लाभ भी मिल रहा है।...(व्यवधान)

इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से सदन को एक और जानकारी देना चाहूंगा । हमने इसमें एक आरपीएल स्कीम लगाई है, जिसमें हम पहले से हुनर प्राप्त को सर्टिफाई करते हैं। ...(व्यवधान) उस सर्टिफिकेशन से जिस जगह वे काम करते हैं, उनका वेजेज़ बढ़ता है, उनका स्तर बढ़ता है और रोज़गार के और अवसर बनते हैं। ...(व्यवधान) हम भविष्य में पीएमकेवाई का जो अगला लूप लाएंगे, उसमें राज्य और केन्द्र सहभागिता बढ़ाने पर विचार करेंगे। ...(व्यवधान)

SHRI S.C. UDASI : Sir, I thank you for giving me this opportunity for raising this important supplementary. I appreciate hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi for giving this important mission to this country. I would like to put a supplementary to the hon. Minister through you, Sir. We have a lot of Industrial Parks and Industrial Zones in the country. वह सब प्रदेशों में है। ...(व्यवधान) क्या आप उसमें यह सुविधा देंगे? ...(व्यवधान) इन्डस्ट्रियल पार्क में एसडीसी बनाने की कोई रूप-रेखा आपकी नज़र में है? ...(व्यवधान) Have you given any direction to the State Governments to have these types of centres so that unskilled and semi-skilled labourers can be made skilled labourers? What action does the Government propose to take to create skilled workers? This is my specific question.

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: कौशल्य बढ़ाने की इन योजनाओं पर हम विचार कर रहे हैं। ...(व्यवधान) जहां तक इन्डस्ट्रियल पार्क्स बनाने की बात है, वह इन्डस्ट्री राज्य और केन्द्र का विषय है, लेकिन हम उसके लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के काम में गंभीरता से लगे हैं। ...(व्यवधान)

हम सदन को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इन्डस्ट्री 4.0 पर भी हमारा डिपार्टमेंट फोकस कर रहा है। ...(व्यवधान) हमने अब नई ट्रेनिंग्स शुरू कर दी हैं। ...(व्यवधान) ड्रोन टैक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस और क्लाउड कम्प्यूटिंग की ट्रेनिंग के भी हम आईटीआई में लॉन्ग-टर्म कोर्सेज़ तीन जगह शुरू कर चुके हैं। ...(व्यवधान) हम साथ में साइबर सिक्योरिटी और इस तरह की डेटा के इन सब कामों को कर के नई इन्डस्ट्री 4.0 के हिसाब से भी तैयारी कर रहे हैं। ...(व्यवधान) पार्क बनाने के काम में केन्द्र और संबंधित राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे और इम्प्लॉयमेंट-लेड ट्रेनिंग को हमारा डिपार्टमेंट प्राथमिकता के रूप में, टार्गेट के रूप में ले रहा है, जैसा माननीय सदस्य की अपेक्षा है। ...(व्यवधान) हम ट्रेनिंग में इन्डस्ट्री पार्टनर को ही विशेष महत्व देते हैं। हमने 37 सैक्टर स्किल काउंसिल्स बनाई हैं, जो इन्डस्ट्री लेड हैं। ...(व्यवधान) इसका उद्देश्य इन्डस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना और इन्डस्ट्री में उनकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कुशल कार्यबल उपलब्ध कराना है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री जगदम्बिका पाल जी ।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप प्रश्न संख्या 13 बोल दीजिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना प्रश्न पूछिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

(Q. 13)

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी से स्किल डेवलपमेंट और प्रधान मंत्री कौशल केन्द्र विकास केन्द्र पर प्रश्न पूछा गया है। ...(व्यवधान)

मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि अभी हमारी सरकार ने बजट में युवा कौशल के लिए तीन हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जिससे निश्चित तौर पर देश के युवा स्किल्ड और ट्रेन्ड होकर भविष्य में खुद एक जॉब प्रोवाइडर के रूप में बनेंगे। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने जिस तरीके से कई माननीय सदस्यों के सवालों पर जवाब दिया है, वह निश्चित तौर पर कई ऐसी स्कीम्ज़ शुरू कर रहे हैं, जिससे स्किल डेवलपमेंट के बाद जिन युवाओं को प्रशिक्षण मिलता है, उससे उनको एम्प्लॉयमेंट या प्लेसमेंट गारंटी की बात की जा रही है, लेकिन प्लेसमेंट कराने के बाद जो ड्रॉप-आउट की संख्या सामने आ रही है, उसके संबंध में कोई कार्य योजना बनाने की बात की जाएगी? ...(व्यवधान) निश्चित तौर पर पूरे देश में, हर जिलों में स्किल डेवलपमेंट या प्रधान मंत्री कौशल केन्द्र विकास केन्द्र की जो स्थापना की गई है, उस स्थापना, ट्रेनिंग के बाद जब उन्हें इन कौशल विकास केन्द्रों से जॉब या प्लेसमेंट मिल जाता है, लेकिन जब उन जगहों से उनकी जॉब छूट जाती है, जब वे ड्रॉप-आउट हो जाते हैं, उस संबंध में आप क्या कार्य करेंगे? ...(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी ने बड़ी चिंता व्यक्त की थी और सरकार ने भी की थी कि इस बजट में जो 112 जिले हैं, जो आकांक्षी जनपद हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके विकास के लिए, नॉर्थ-ईस्ट के विकास के लिए, आदिवासी, वनवासी के विकास के लिए हम विशेष कार्यक्रम चलाएंगे। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने स्वयं घोषणा की थी कि हम सिद्धार्थ नगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा सा रोजगार मेला लगाएंगे। उस दिशा में आप क्या कार्य करेंगे? ...(व्यवधान)

अगर शिक्षकों को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो जो शिक्षक विद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ाता है, जो निष्ठा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में कौन-कौन से कार्य किए जा रहे हैं, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। …(व्यवधान)

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: मैं डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से उत्तर देना चाहूंगा । जहां तक माननीय सदस्य**,** माननीय जगदम्बिका पाल जी ने दो-तीन बिंदू उठाए हैं । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम जब ट्रेनिंग प्रदान करते थे तो ट्रेनिंग में पहले प्लेसमेंट के बाद ही ट्रेनर को पूरे पैसे दिए जाते थे, वर्ना हम बीस परसेंट रोकते थे। पहले तीन महीने हम ट्रैकिंग करते थे। हमने अभी हाल में ट्रैकिंग पीरियड 6 महीने का कर दिया है। प्लेसमेंट के बाद हम 6 महीने ट्रैकिंग करेंगे।

जहां तक उन्होंने सिद्धार्थ नगर में रोजगार मेले की बात कही है, माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं, हम उस पर विचार करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सब फ्लोर के नेताओं ने निर्णय किया था कि हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नकाल, जिसमें सभी विषयों पर चर्चा होती है, उसको चलने देंगे। मेरा आपसे फिर आग्रह है कि हम उस निर्णय की पालना करें। आप सब अपनी-अपनी जगहों पर बैठें। शून्यकाल फिर आएगा, उस समय आप अपनी बात कहिएगा ।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर बैठें, सबको बैठाएं। जब शून्यकाल आएगा, तब लिस्ट में से बोलिएगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष जी, एक रिक्वेस्ट है। ...(व्यवधान) यह जो मोशन ऑफ थैंक्स है, उसमें सेव आर कॉन्सिटट्यूशन, सेव आर डेमोक्रेसी के सारे विषय आ जाएंगे। ...(व्यवधान) ये लोग सारे विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन-2 – श्रीमती जसकौर मीना ।

(Q. 2)

श्रीमती जसकौर मीना: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि एशियाई विकास बैंक के साथ क्या कोई समझौता हुआ है या नहीं? मुझे इसकी जानकारी चाहिए। ...(व्यवधान)

इसके साथ ही इन बैंकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को उन्नत करने के लिए कौन-कौन से ऐसे कदम उठाए गए हैं, जो किसानों के हित में हों? ...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक से आपने कौन-कौन से सैक्टर के लिए पैसे मांगे हैं और लोन लिया गया है? ...(व्यवधान)

मैं पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि ये सैक्टर स्पेसिफिक नहीं है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है । ...(व्यवधान) दूसरा, इसके लिए जब राज्य की सरकारें लोन अवेल करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की मांग करती हैं तो राज्य की सरकार की ओर से प्रपोज़ल आता है**,** जिसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से एग्ज़ामिन किया जाता है । ...(व्यवधान) जब उस प्रपोज़ल को एडीबी को भेजा जाता है, तब उसमें एक प्रिपरेशन-फेज़ होता है, जिसे एडीबी अप्रूव करता है और उसके बाद राज्य की सरकार या केन्द्र सरकार के बीच में लीगल एग्रीमेन्ट साइन होता है। ...(व्यवधान) इसमें भारत सरकार ने कोई पैन सैक्टर एग्रीमेन्ट अभी तक साइन नहीं किया है, लेकिन अलग-अलग सैक्टर्स में जो काम हो रहा है, वह मैं इस सदन में जरूर बताना चाहूंगा ...(व्यवधान)

अब तक कुल मिलाकर 13,548 मिलियन डॉलर्स के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एडीबी के माध्यम से चल रहे हैं। ...(व्यवधान) इनमें ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 5,933 मिलियन डॉलर्स हैं, एनर्जी के क्षेत्र में 3,378 मिलियन डॉलर्स हैं और अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में लगभग 2,277 मिलियन डॉलर्स हैं । ...(व्यवधान) एग्रीकल्चर, जिसके बारे में माननीय जसकौर मीना जी ने पूछा है, 846 मिलियन डॉलर्स

उसके लिए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए 803 मिलियन डॉलर्स हैं और फाइनेंस रिलेटेड 300 मिलियन डॉलर्स हैं। ...(व्यवधान) कुल मिलाकर 13,548 मिलियन डॉलर्स इस पर खर्च किए जा रहे हैं।

श्रीमती जसकौर मीना : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सप्लिमेंटरी प्रश्न है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आज राजस्थान में इतना अमरूद पैदा हो रहा है, उसके लिए कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं डाली गई है। ...(व्यवधान) प्रोसेसिंग यूनिट के बिना किसानों की फसल बर्बाद होती है, उनको बहुत कम दाम मिलते हैं। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या वहां प्रोसेसिंग यूनिट डालने के लिए किसानों को कोई वित्तीय सहायता प्राप्त है? ...(व्यवधान) यदि है, तो मुझे वह बताने की कृपा करें। ...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी इस दिशा में काम करती है। आपके लिए अलग-अलग प्रोजेक्ट्स अप्रूव करती है।...(व्यवधान) देश के अलग-अलग राज्यों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में चलने शुरू हुए हैं, जिससे किसानों की आय को भी बल मिलता है, बढ़ोत्तरी होती है और वैल्यू एडीशन भी होती है।...(व्यवधान) अगर राजस्थान की भी ऐसी मांग है तो संबंधित मंत्रालय के साथ वह भी रख दी जाएगी।

श्री निहाल चन्द चौहान: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहूंगा कि 1966 में एडीबी की स्थापना हुई थी। यह फिलीपींस में है।...(व्यवधान) इसके 67 देश सदस्य हैं। मैं आपके माध्यम से अपने प्रश्न के उत्तर में जानना चाहूंगा कि किसी विशेष क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कोई हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा और आपसे जानकारी भी चाहूंगा कि इस बैंक का केन्द्र के साथ किस-किस तरीके का एम.ओ.यू. साइन हुआ है?...(व्यवधान) क्या इस बैंक के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए गए समझौते में सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड संपर्क मैप बनाने के लिए कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले सदस्य के उत्तर में भी विशेष तौर पर कहा था कि ये सेक्टर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, ये प्रोजेक्ट्स स्पेसिफिक होते हैं। ...(व्यवधान) राज्य की सरकारें या केंद्र सरकार को जिन-जिन विशेष प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए प्रपोजल बनाकर देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनोमिक अफेयर्स उसका अध्ययन करता है, उस पर प्रजोजल बनकर जाते हैं, जिस पर एडीबी विचार करती है। ...(व्यवधान) उस पर वे पैसा मंजूर करते हैं और उसके बाद ये पैसा दिया जाता है। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि ये लोन क्यों लिए जाते हैं। चीपर इंट्रैस्ट रेट मिलता है, मल्टी लैट्रल बैंकों की एएए रेटिंग हैं और ये इंट्रोडक्शन ग्लोबल बैस्ट प्रैक्टिसेज के साथ है, इसलिए यह किया जाता है। लेटेस्ट तकनीक और टेक्नोलॉजी उपलब्ध होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग स्टाफ की होती है, बैटर प्रोजेक्ट इन फाइनेंसियल मैनेजमेंट होता है।...(व्यवधान) इसलिए अलग-अलग सैक्टर्स पर काम किया जाता है। जहां तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में अभी 4 बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें 220 मिलियन डॉलर का 3 जुलाई 2017 को राजस्थान स्टेट हाइवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसमें लगभग 220 मिलियन मंजूर किए गए थे। इसमें 156 मिलियन डिस्बर्स कर दिए गए हैं। दूसरा राजस्थान स्टेट हाइवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। इसमें 190 मिलियन अप्रूव हुए हैं। ...(व्यवधान) जयपुर मेट्रो रेल लाईन फेज बी के लिए 176 मिलियन डॉलर मंजूर किए हैं। राजस्थान अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट के लिए 250 मिलियन का लोन कंपोनेंट है। अगर आप देखें तो सड़कों से लेकर अर्बन डेवलपमेंट तक सब क्षेत्रों में अलग-अलग काम किया गया है।...(व्यवधान) अगर आप देश भर के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनके लिए मैंने पहले एक आंकड़ा दिया है कि 13.5 बिलियन डॉलर कुल 73 प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जा रहे हैं, जो अलग-अलग सेक्टर्स में हैं। ये एडीबी के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब्दुल खालेक जी, आप अपनी सीट पर जाइए, आपको महतवपूर्ण प्रश्न पूछना है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: लोकतंत्र तब ही बचेगा, जब आप अपनी सीट पर जाकर अपने इलाके के प्रश्न पूछेंगे।

(Q. 3)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR):

(a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

माननीय अध्यक्ष: हिबी ईडन जी, आपको संसद में नारे लगाने के लिए नहीं भेजा है, प्रश्न पूछने के लिए भेजा है। आप अपनी सीट पर जाकर प्रश्न पूछिए -

…(व्यवधान)

(Q. 4)

डॉ. निशिकांत दुबे : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय प्रधान मंत्री जी का जो सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, जिसको माननीय धर्मेन्द्र प्रधान जी ने इम्प्लीमेंट किया है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।...(व्यवधान) आज इस देश के लगभग 96-97 परसेंट लोगों को एल.पी.जी. का कनेक्शन मिल गया है। अभी सी.ए.जी. की रिपोर्ट आई है। उसने कई प्रश्न इस प्रोग्राम के ऊपर किए हैं। ये प्रश्न कहते हैं कि जो एक बार सिलेण्डर ले लेते हैं, उनमें केवल 3.21 ही दोबारा रीफिल होते हैं। ...(व्यवधान) एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सिलेण्डर देने के बाद गरीबों को हम वहां तक पहुंचा पाएंगे या नहीं, जिस मुद्दे के लिए यह प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया है?

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है और प्रश्न भी है कि जिस तरह से आपने लगभग 96-97 परसेंट हाउसहोल्ड्स में गैस सिलेण्डर पहुंचाए हैं, लेकिन जो पैसा प्रत्येक साल बच रहा है, क्या भारत सरकार का यह इरादा है कि उसी पैसे के आधार पर हम एक या दो सिलेण्डर प्रत्येक साल आम जनता को फ्री में पहुंचाएं, जिसके कारण यह उद्देश्य पूरा हो पाए? ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता मेरे मित्र हिबी ईडन अगर इस प्रश्न को पूछते तो सदन में और बढ़िया होता । मैं अभी भी अनुरोध करूंगा कि You go to your seat and ask a very pertinent question. I would be happy to answer your question. ...(व्यवधान)

माननीय सदस्य निशिकांत जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं तथ्य को थोड़ा राइट पर्स्पेक्टिव में रखना चाहूंगा। प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के 87 प्रतिशत लाभार्थियों ने 3.27 एक साल के अंदर रीफिलिंग लेना शुरू किया है। ...(व्यवधान) जो रेगुलर कस्टमर हैं, जिनको 13 करोड़ बनने में 60 साल लगे, उनका ऐवरेज 7 था । उस तुलना में गरीब लोगों को प्रधान मंत्री जी ने जो सिलेण्डर पहुंचाया, उज्जवला लाभार्थियों का औसत 3.27 प्रतिवर्ष है। बाकी सी.ए.जी. की टिप्पणी की बात है

तो सी.ए.जी. ने कुछ विषयों को सुधारने के लिए एक टिप्पणी दी थी। ...(व्यवधान) हमने उन सुधारों को राइट स्प्रिट में लेकर कंपनियों को जिम्मेदारी दी है। इस बीच में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और गैस कनेक्शन के कटने के कारण लगभग 65 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। उसी बचे हुए पैसे से हमने गरीब लोगों को 8 करोड़ एल.पी.जी. कनेक्शन मुफ्त में दिए हैं। ...(व्यवधान)

श्री भोला सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहूंगा कि देश के 8 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मुफ्त दिया गया है। ...(व्यवधान) जो कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उनको भी गैस कनेक्शन मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसे परिवार संज्ञान में आ रहे हैं कि जिनको अभी भी कनेक्शन देना बाकी है। क्या यह योजना आगे बढ़ाई जाएगी या कुछ और लोग इसके लिए इलिजिबल निकाले हैं? ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष जी, एल.पी.जी. पेनीट्रेशन लगभग 97 परसेंट हो गया है। अगर कुछ लोग बचे हुए हैं, जिनको एल.पी.जी. कनेक्शन देना है तो अभी उज्ज्वला योजना की समय सीमा समाप्त हुई है। अगर लोगों की मात्रा ज्यादा होगी तो शायद सरकार इस पर विचार कर सकती है।

(Q.5)

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH : Hon. Speaker, Sir, the State Governments are already facing financial constraints. While implementing the GST in 2017, the Union Government had assured to compensate the States, but now they are saying that they do not have the financial resources …(*Interruptions*)

Regarding Andhra Pradesh, from October, 2019 to November, 2019, there was a shortfall of Rs. 682 crore. The compensation has not yet been received by the Government of Andhra Pradesh …(*Interruptions*)

Similarly, from December, 2019 to January, 2020, shortfall to be worked out, will be due before 29th February, 2020 …(*Interruptions*)

The total shortfall from April, 2019 to November, 2019 was at Rs. 2,136 core, but the compensation received is only Rs. 1,454 crore. …(*Interruptions*)

Sir, I would like to ask the hon. Minister: how much does the Central Government owe to the Government of Andhra Pradesh for the SGST? When should the Government of Andhra Pradesh expect the payment of these funds?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, "वन नेशन, वन टैक्स" के तहत जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म भारत में हुआ है और आज तक के सबसे बड़े रिफार्म्स में से एक है …(व्यवधान) इसमें से अधिकतर निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं…(व्यवधान) और केवल लॉटरी वाला जो विषय था, उस पर वोटिंग करने की जरूरत पड़ी है…(व्यवधान) वह भी स्टेट स्पॉन्सर्ड और स्टेट रन लॉटरीज पर

जीएसटी लगेगा, यह एक अलग विषय है...(व्यवधान) इसके अलावा आज तक जितना कम्प्नसेशन देना चाहिए था, वह देते गए...(व्यवधान) और जो ड्यू भी है, उसके बारे में वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट तौर पर कहा है -

> "It is decided to transfer to the GST Compensation Fund balances due out of collection of the years 2016-17 and 2017-18, in two instalments. Hereinafter, transfers to the fund would be limited only to collection by way of GST compensation cess."

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH: Sir, my second supplementary is this. ...(*Interruptions*) At present, the tax payers and accountants are complaining about the failure of GSTN in providing proper network support for filing of returns. ...(*Interruptions*) What are the steps initiated to resolve the GST network issues? I would also like to know whether any steps towards establishment of State-wide servers is initiated? ...(*Interruptions*) What is the Government's view on the demand by All-India Insurance Employees Association for the withdrawal of GST from life insurance policies? ...(*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, जहां तक इंश्योरेंस की बात है, जीएसटी काउंसिल में इसका निर्णय किया जाता है...(व्यवधान) जहां तक जीएसटी नेटवर्क को और सुधारने की बात है...(व्यवधान) मैं आपके सुझाव को पॉजिटिव तरीके से लेता हूं और जो भी उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है...(व्यवधान) उसकी ओर जीएसटी काउंसिल लगातार प्रयास कर रही है...(व्यवधान)

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY: Thank you, Sir, for giving me this opportunity. ...(*Interruptions*) Keeping in view the econoic slowdown, the

requirement of increased compensation is there. …(*Interruptions*) Our Telangana State needs more financial support from the Central Government to take forward the development projects. …(*Interruptions*) I would like to know by when the Central Government will pay the GST compensation to the State of Telangana which is due from November, 2019 to January, 2020. …(*Interruptions*) What are the steps taken by the Government to remove the confusion and stabilise the GST system? …(*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, अगर आप पिछले तीन महीने को देखेंगे तो जीएसटी की कलेक्शन लगातार बढ़ी है...(व्यवधान) यह एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हुई है। 1 लाख 3 हजार करोड़ रुपये से लेकर 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये तक पहुंची है...(व्यवधान) इसके अलावा जो कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स है, इसको हम तीन इंस्टॉलमेंट्स में अप्रैल से जून तक 15 प्रतिशत देते हैं, जुलाई से जनवरी तक लगभग 50 परसेंट हम सात ईक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं...(व्यवधान) और चार इंस्टॉलमेंट्स में 35 परसेंट से फरवरी से मार्च तक का देते हैं...(व्यवधान) इनडायरेक्ट टैक्सेज को हम 14 ईक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं और आगे भी इसको जारी रखेंगे...(व्यवधान) 20 तारीख को अगर हमारे रिटर्न फाइल होकर टैक्स कलेक्शन वहां तक होती है तो सेम डे उसकी वापस कम्प्नसेशन भी दी जाती है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. टी. सुमति जी, क्या आप प्रश्न पूछना चाहती हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. आर. बालू, क्या आप बोलना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. टी. सुमति।

…(व्यवधान)

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN : Sir, this is a supplementary question regarding Question number 5. It is about the recent meeting of GST Council……(*Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : डॉ. टी. सुमति जी, क्या आप प्रश्न पूछना चाहती हैं?

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. आर. बालू जी। आप फिर मेरे पास आते हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : श्री मारगनी भरत ।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI MARGANI BHARAT : Hon. Speaker Sir, the Government of India is collecting a lot of taxes in the form of cess. I would like to know whether the taxes so collected are being distributed or not. If not, how can you justify the objective of cooperative federalism when the taxes are being collected in the form of cess? How can you justify it?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, जितने भी कंपनसेशन्स हैं, जो सेस कलेक्ट किया जाता है, उसमें से दिए जाते हैं और आगे भी जितना सेस कलेक्ट होगा, उसमें से दिया जाएगा।…(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। इसमें जो सवाल किया गया है, मंत्री जी ने उस सवाल का सही उत्तर नहीं दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का एक पाइंट बहुत ही स्पष्ट है कि जीएसटी और आईजीएसटी का amount pending for each State, at present.... (व्यवधान) उसके बारे में उत्तर में कुछ भी नहीं दिया गया है। उसका उत्तर नहीं दिया गया है।...(व्यवधान) हमारा जो पाइंट है, हमारे मुख्य मंत्री साहब ने सरकार को पत्र लिखा है और उसके बाद हम लोगों ने वित्त मंत्री जी के पास जाकर भी बात की है। हमारे राज्य में करीब-करीब 5,000 करोड़ रुपये के जीएसटी और आईजीएसटी के ईश्यूज़ पेंडिंग हैं।...(व्यवधान) पैसे को समय पर रिलीज़ नहीं करने की वजह से राज्य का विकास भी प्रभावित हो रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन आपने हम लोगों को अलाऊ किया था, जिसकी वजह से हाउस में लगभग 10 पार्टियों के नेताओं ने यह विषय उठाया था। उस समय यह वादा किया गया था कि जीएसटी और आईजीएसटी को तुरंत रिलीज़ किया जाएगा ।...(व्यवधान) अभी-भी जो सवाल है कि स्टेट का क्या-क्या पेंडिंग है, तो उसके बारे में नहीं बताया गया है। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि तेलंगाना राज्य के जीएसटी और आईजीएसटी के लगभग 5,000 करोड़ रुपयों के पेंडिंग अमाउंट को तुरंत रिलीज़ किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, इन्होंने डिमांड की है। लेकिन, मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि परसों ही वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि it is decided to transfer the GST Compensation fund balances out of the funds collected in the year 2016-17 and 2017-18 in two instalments. Hereinafter transfers to the fund would be limited only to collection by way of the GST compensation cess....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री चंद्र शेखर साहू जी ।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री चंद्र शेखर साहू : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। I want to know whether the GST compensation to the States has not been presented for the last four months to Odisha. It is Odisha specific. In the last four months, GST has not been paid. मैं मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप उसको थोड़ा क्लैरिफाई करें कि चार महीनों से जीएसटी का भुगतान क्यों नहीं किया गया है?…(व्यवधान) इसका क्या कारण है?...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अध्यक्ष जी, मैंने इसका उत्तर पहले भी दिया है। सभी माननीय सदस्यों के प्रश्न सेम ही हैं। मैंने यह भी कहा है कि जितनी भी कंपनसेशन्स हैं, उनको दो इन्स्टॉल्मेन्ट्स में दे दिया जाएगा।…(व्यवधान)

(Q. 6)

श्री भगवंत खुबा : अध्यक्ष महोदय, मैंने बैंकों में होने वाली धोखाधड़ियों के बारे में प्रश्न पूछा था, जिसके बारे में विस्तार से माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। ...(व्यवधान) इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। ...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि सौ करोड़ रुपये से ज्यादा होने वाला जो फ्रॉड है, उसके डिटेक्शन के समय कम से कम 55 महीने लग रहे हैं। ...(व्यवधान) यह मैं पूछना चाहता हूँ कि उसका जल्दी से जल्दी डिटेक्शन हो, उसके ऊपर कार्यवाही हो और आगे होने वाला फ्रॉड, धोखाधड़ी कम हो। ...(व्यवधान) इसके बारे में क्या कोई कार्रवाई आपने की है? ...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, आप देखेंगे कि यूपीए के समय से बैंकों की जो हालत थी, और जिस तरह से उस समय लोन देने का काम किया गया था, उससे एक काम तो बढ़ा। ...(व्यवधान) लोन का वितरण भी इन्होंने ज्यादा किया और फ्रॉड भी उस समय ज्यादा होने शुरू हो गए थे। ...(व्यवधान) जिसके कारण यह हुआ, उसका प्रभाव यह पड़ा कि उसमें एनपीए लगातार बढ़ते चले गए। ...(व्यवधान) जब हमारी सरकार आई तो उस समय के वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी ने एसेट क्वालिटी रिव्यू की शुरूआत की थी। ...(व्यवधान) जब बैंको की एसेट क्वॉलिटी रिव्यू की शुरूआत हुई तो बैंकों में जो एनपीए कारपेट के नीचे दबा कर रखे जाते थे, बाहर नहीं आने दिए जाते थे, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग, रीफाइनेंसिंग करने का अवसर उनको बार-बार दिया जाता था। ...(व्यवधान) मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने वैसा नहीं किया। ...(व्यवधान) हमने एसेट क्वालिटी रिव्यू कर के जितने भी एनपीए थे, उनको बाहर लाने का काम भी किया। ...(व्यवधान) जो 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के खाते हैं, ...(व्यवधान) अगर पहले फ्रॉड की श्रेणी में आता है तो उसकी जांच करवाने की बात कही। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने कहा कि अगर उसमें समय ज्यादा लगता है तो वह समय

कम करना चाहिए। …(व्यवधान) उसमें भी जो रीसेंट नोटिफिकेशन है कि सस्पेक्टिड फ्रॉड वाली श्रेणी में उसको लाया जाए, उससे भी फर्क पड़ेगा। …(व्यवधान) इसमें एनपीए अकाउंट्स, जैसा मैंने कहा कि 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की जांच होगी। …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष, आपको और सदन को यह जानकार प्रसन्नता होगी कि जो फ्रॉड की संख्या थी, अगर आप देखेंगे, पहले मैं एनपीएज़ की बात करूं तो एनपीए भी 8.96 लाख करोड़ रुपयों से कम हो कर 7.27 लाख करोड़ रुपये हुआ है। …(व्यवधान) पहले तो एनपीए में भी कमी आई है। …(व्यवधान) यह भी इसके कारण हुआ है, जो सरकार ने कदम उठाए हैं। …(व्यवधान) लगभग एक लाख 68 हजार 305 करोड़ रुपये के एनपीए में कमी आई है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष, जहां तक फ्रॉड्स की बात है, यह आंकड़ा भी बहुत अच्छा है, जिसको मैं सभा पटल पर रखना चाहूंगा और माननीय सदस्यों की जानकारी में लाना चाहूंगा कि लगभग एक लाख 68 हजार करोड़ रुपये के फ्रॉड्स, जो पहले के वर्षों के थे, डिटेक्ट किए गए हैं । इससे फ्राड्स में भारी गिरावट आई है, जो 2009 से 2014 में कुल ऋण के 0.58 पर्सेंट से कम हो कर चालू वर्ष में 0.08 पर्सेंट तक आए हैं। …(व्यवधान) यह अपने आप दिखाता है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, आरबीआई ने जो निर्देश दिए हैं, उससे फ्रॉड की श्रेणी में, पहले 50 करोड़ रुपये के जो अकाउंट्स हैं, उनको ले कर जैसे ही इसकी जांच शुरू होती है, इसमें भारी गिरावट फ्रॉड्स में आनी शुरू हो गई है। …(व्यवधान) मुझे लगता है कि इसका लाभ बैंकिंग सैक्टर में देखने को मिल रहा है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री हेमन्त पाटिल – उपस्थित नहीं ।

श्री मलूक नागर जी ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप जिन विषयों पर भी नारे लगा रहे हैं, उन सारे विषयों पर, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय आप चर्चा कर सकते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर आप इस लोकतंत्र के अंदर जनता की बात को उठाना चाहते हैं तो मैं पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर आपको दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: समय की कोई कमी नहीं रहेगी । आप पर्याप्त समय में बोलना। यह लोकतंत्र का मंदिर आप सबका है। यह संसद आप सबकी है। आपको जनता ने यहां पर अभिव्यक्ति के लिए भेजा है। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको अभिव्यक्ति की पूरी आजादी मिले।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसलिए मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ कि लोकतंत्र की मार्यादाओं को बनाए रखने के लिए, आप सभी माननीय सदस्य अपने-अपने आसन पर विराजें।

…(व्यवधान)

श्री मलूक नागर : मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि देश में जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं और जिनमें बिजनेसमैन अरेस्ट हुए हैं, क्या लोन करने वाले अधिकारी भी उतने ही अरेस्ट हुए हैं या वे कम हुए हैं?…(व्यवधान) अगर वे कम हैं, तो यह भेदभाव क्यों है? सरकार उन अधिकारियों को क्यों बचा रही है?…(व्यवधान) जो व्यापारी जेल जा रहे हैं, साथ में बैंक वाले भी उतने ही लोग जेल जाने चाहिए

।...(व्यवधान) मैं वित्त मंत्री जी से इनकी संख्या जानना चाहता हूँ। कृपया वे इसकी संख्या बताएं, बजाय इसके कि गोली मारने के लिए कहते हैं। इसकी संख्या बताएं।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, पहली बात तो मैं यह कहूँ, जहाँ तक बैंकों की बात है कि किस तरह से फ्रॉड्स में कमी आई है ।...(व्यवधान) पीएसबी में वर्ष 2014 में 4498 केसेस थे, जिसमें एमाउंट लगभग 34,722 करोड़ रुपये थी ऑन द डेट ऑफ ऑकरेंस के हिसाब से, उसमें भी कमी आकर 3962 नंबर्स हैं और उसमें मात्र 18893 करोड़ रुपये एमाउंट है ।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, अगर रिपोर्टिंग को भी देखा जाए तो वर्ष 2014-15 में 4639 नम्बर्स थे और एमाउंट 19455 करोड़ रुपये इन्वॉल्व थी।...(व्यवधान) इसमें भी रिपोर्टिंग बढ़ाई गई है, तो उसमें भी लगभग 6801 नम्बर्स में 71543 करोड़ रुपये हुआ है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि जैसे रिपोर्टिंग ज्यादा बढ़ी है, फ्रॉड्स में कमी आनी शुरू हुई है।...(व्यवधान) यही बड़ा कारण है कि 0.58 परसेंट से कम होकर 0.08 परसेंट पर आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ।...(व्यवधान) इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने जो कदम उठाए हैं, वे प्रशंसनीय भी हैं।...(व्यवधान) जहाँ तक व्यापारी अगर फ्रॉड करके जेल में जाता है तो देश के टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, उसके साथ कानून को जो निर्णय करना चाहिए, वह कानून करेगा, चाहे वे अधिकारी हों, चाहे व्यापारी हों।...(व्यवधान)

श्री विनायक भाउराव राऊत: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। महाराष्ट्र के पंजाब-महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से वहाँ के जो डिपोजिटर्स थे, उनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है।...(व्यवधान) मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि पीएमसी बैंक में फंसे हुए ग्राहकों को राहत देने के लिए केन्द्र सरकार इस सबंध में आगे क्या निर्णय लेने जा रहा है और इसके ऊपर कब तक निर्णय लेने की सम्भावना है? ...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। वे महाराष्ट्र से आते हैं और यह भली-भांति जानते हैं कि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, उनमें केन्द्र सरकार सीधा नहीं देती है।...(व्यवधान) वह राज्य का विषय भी है और राज्य में अब आपकी सरकार भी है। मुझे लगता है कि वहाँ आप भी उचित कदम उठाएँगे।...(व्यवधान) लेकिन जहाँ तक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की बात थी, पूर्व की सरकार के समय उसने उचित कदम उठाए और जिन लोगों की फ्रॉडमैन की भूमिका थी, उनको जेल में डालने का काम भी किया है और आगे के कदम भी वहाँ पर उठाए जाएँगे।...(व्यवधान) भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए भी जो एक्ट है, उसमें बदलाव लाने के प्रयास किए जाएँगे ताकि को-ऑपरेविटव बैंक्स और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, उनको भी किस तरह से स्वरूप से कम किया जाए।...(व्यवधान) लेकिन मैं यहाँ तक कहूँगा कि आरबीआई ने उसमें जो कदम उठाए हैं, वे भी एमाउंट को लगातार बढ़ाते चले गए।...(व्यवधान) अब तक जो स्थिति है, 78 प्रतिशत लोगों को उनका पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा और बाकियों के लिए जो प्रॉपर्टीज़ अटैच की गई हैं, उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, उनके लिए अगले कदम उठाए जाएँगे, ताकि बाकियों के पैसे वापस मिल सकें।...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, अभी जो बजट दिया है, उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि आगे के लिए जो एक लाख रुपया, जो बैंक के खाते के लिए लोगों की इंश्योरेंस होती थी, अब उस एक लाख की एमाउंट को पाँच गुना बढ़ा दिया गया है, उसको 5 लाख करने का काम किया है। इस सरकार ने वह कर दिया है, इसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह पूरे देश भर में बैंकों के साथ धोखाधड़ी हुई है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच में किन-किन राज्यों में किन-किन बैंकों के साथ कितनी राशि की धोखाधड़ी हुई है।...(व्यवधान) वैसे तो जो

पैसा लोगों के बचत खाते में जमा होता है, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, जो लोगों का पैसा लेकर गायब हो जाती हैं ।...(व्यवधान) ऐसा बंगाल में हुआ ।...(व्यवधान) इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर चिट-फंड कंपनियाँ गरीबों का पैसा लेकर गायब हुई हैं ।...(व्यवधान) इनकी पूरी तरह से तहकीकात होनी चाहिए ।...(व्यवधान) हालांकि हमारी सरकार ने ऐसा किया है ।...(व्यवधान) मैं जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 के बीच में कितने इस तरह के फ्रॉड्स हुए हैं? ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं।...(व्यवधान) इन्होंने गरीब व्यक्ति की चिंता व्यक्त की है कि किस तरह से कुछ राज्यों में कुछ लोगों ने चिट-फंड कंपनी के नाम पर अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट के नाम पर पैसा इकट्ठा किया ।...(व्यवधान) उन्होंने धांधलियाँ कीं, घोटाले किए ।...(व्यवधान) इसके लिए राज्यों की सरकारों के पास भी अधिकार हैं, उन्हें भी कदम उठाने चाहिए थे।...(व्यवधान) केन्द्र की सरकार ने उस पर कड़े कानून बनाए हैं।...(व्यवधान) अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर रेग्युलेशन हम लेकर आए।...(व्यवधान) चिट-फंड्स पर रेग्युलेशन हम लोग लेकर आए ।...(व्यवधान) इसमें भी राज्यों की सरकारों को अधिकार दिए गए हैं कि आप उन पर कड़ी कार्रवाई करें और पारदर्शिता लेकर आएं ।...(व्यवधान) जितने घोटाले उनमें हुए हैं, पश्चिम बंगाल से लेकर बाकी अन्य किसी भी राज्य की बात हो, उसकी जानकारी राज्यों से इकट्ठा करके माननीय सदस्य को दे दी जाएगी ।...(व्यवधान) बैंकों में भी जो-जो घोटाले हुए हैं, जो भी संबंधित जानकारी आप चाहोगे, सभी बैंकों से जितनी भी डिटेल्स आप चाहोगे, वह सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह: मंत्री जी, मैं वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच की बात कर रहा हूँ।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : वर्ष 2004 से वर्ष 2014 की बात माननीय सदस्य ने कही है ।...(व्यवधान) यह बात सही है कि उस समय दोनों हाथों के साथ लोन बांटे गए ।...(व्यवधान) यही कारण है कि उस समय 14 लाख करोड़ से बढ़ाकर, ...(व्यवधान) वर्ष 2008- 2014 तक 18 लाख करोड़ से 52 लाख करोड़ तक के कर्जे दे दिए गए ।...(व्यवधान) यानी कि आप कल्पना कीजिए कि केवल छः वर्षों के अंदर अगर 34 लाख करोड़ रुपया दे दिया गया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा ।...(व्यवधान) उसका प्रभाव यही पड़ा कि उसमें फ्रॉड ज्यादा बढ़ गए, रिपोर्टिंग कम थी, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई, ऐसेट क्वालिटी रिव्यू भी हमने शुरू किए, रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू किया, फ्रॉड में कमी आनी शुरू हुई है ।...(व्यवधान) यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रवि किशन जी, आप बहुत संक्षेप में अपना प्रश्न पूछिए ।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री रवि किशन : महोदय, मेरा प्रश्न पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ है ।...(व्यवधान) उसमें लोगों का करोड़ों-करोड़ रुपया फंसा है ।...(व्यवधान) उसमें मेरे भी पैसे अटके रहे ।...(व्यवधान) जब वहाँ हमारी सरकार थी, ...(व्यवधान) तो हम लोगों को...(व्यवधान) 6 महीने में 40 हजार रुपया मिलने लगा था ।...(व्यवधान) मेरी जिन्दगी भर की शूटिंग की कमाई उसमें थी ।...(व्यवधान) 40 हजार रुपया मुझे मिलने लगा ।...(व्यवधान) लेकिन जो नई सरकार आई है, उसके बाद से बैंक ने रेस्पांस करना बंद कर दिया है ।...(व्यवधान) मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन उन करोड़ों खाताधारकों के लिए पूछ रहा हूँ, जो महाराष्ट्र में हैं ।...(व्यवधान)

महोदय, मैं उनके लिए माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कैसे दोबारा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से हम लोगों को पैसे मिलेंगे ।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि यह विषय केन्द्र सरकार का नहीं है ।...(व्यवधान) अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसायटीज सेन्ट्रल कोऑपरेटिव एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होती हैं ।...(व्यवधान) इसके बारे में राज्य की सरकार को ज्यादा कदम उठाने चाहिए ।...(व्यवधान) यहाँ तक आरबीआई ने इसमें छूट दी, बैंक की लिमिट भी बढ़ाई थी कि कितना-कितना पैसा निकाल सकते हैं ।...(व्यवधान) 78 प्रतिशत लोगों को अपना पूरा पैसा वापस मिल जाएगा ।...(व्यवधान) जो बाकी लोग हैं,...(व्यवधान)अब तक के जो निर्णय हुए हैं ।...(व्यवधान) जो बाकी हैं, उसके लिए उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 7 और 8 को अटैच कर रहे हैं ।

क्वेश्चन नम्बर 7, श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे – उपस्थित नहीं ।

श्री पी. पी. चौधरी ।

(Q. 7 and 8)

श्री पी. पी. चौधरी: महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान) मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है।...(व्यवधान) प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय बहुत ही अच्छा काम कर रहा है।...(व्यवधान) मैं इसके बारे में दो पूरक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा।...(व्यवधान)

मैं पूछना चाहूंगा कि नीति आयोग द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के लिए जो इवैल्यूएशन स्टडी हुई है, उस स्टडी में गर्ल्स चाइल्ड के ड्रॉप-आउट के लिए कक्षा-8 के बाद बड़ा कंसर्न किया गया है और यह माना गया है कि चूंकि उनके हाइयर क्लासेज नहीं हैं, कक्षा-11 एवं 12 के लिए उनका आगे एक्सटेंशन नहीं है तो उसके लिए चाहे पैरेंट्स हों, प्रिंसिपल्स हों या टीचर्स हों, इन लोगों ने भी इसके लिए कहा है और कुछ राज्य सरकारों ने इसे किया है।...(व्यवधान) क्या केन्द्र सरकार, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में इनके एक्सटेंशन के लिए, जिसके बारे में नीति आयोग ने अपनी इवैल्यूएशन स्टडी में कहा है, क्या पूरे देश में ऐसे विद्यालयों में कक्षा-11 एवं कक्षा-12 की पढ़ाई के बारे में वह सोच रही है?...(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, हमारी सरकार बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत व्यापक स्तर पर तमाम कार्रवाई कर रही है।...(व्यवधान) समग्र शिक्षा के तहत प्राइमरी स्कूल से लेकर इन्टरमीडिएट तक के शैक्षणिक संस्थानों को बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से पोषित किया जा रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय चौधरी जी ने जिस बात को उठाया है, हमारे देश में दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा की दृष्टि से कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई है।...(व्यवधान) इन कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का बहुत अच्छा रिजल्ट है।...(व्यवधान)

श्रीमन्, मैं इस बात को कह रहा था कि जिस तरीके से हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है, जो कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय हैं, वहां दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाएँ हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और मुस्लिम बालिकाएँ बहुत बड़ी संख्या में हैं ।...(व्यवधान) पिछले पाँच वर्षों में बालिकाओं की शिक्षा में सुधार हुआ है ।...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने इस बात को पूछा है कि बहुत अच्छी तरह से चल रहे इन कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों को क्या और आगे बढ़ाया जाएगा ।...(व्यवधान)

श्रीमन्, हम उस पर विचार कर रहे हैं क्योंकि उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं ।...(व्यवधान) हमारे प्रधान मंत्री जी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, हमारी सरकार उसमें शत प्रतिशत रिजल्ट देने की पक्षधर है ।...(व्यवधान) इसलिए बालिका विद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।...(व्यवधान)

श्रीमन्, मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि समग्र शिक्षा के तहत हमारे 5,930 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय स्वीकृत हैं । कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की जो क्षमता है, उसमें हम 7,83,220 छात्राओं को शिक्षा दे रहे हैं ।...(व्यवधान) मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि जिस लक्ष्य के साथ इन कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई थी, अगर इसके पूरे आँकड़ों को देखा जाए तो इनमें 1,74,653 एस.सी. बालिकाएँ हैं, जो 28.25 प्रतिशत हैं ।...(व्यवधान) एस.टी. की 1,55,585 बालिकाएं हैं, जो 25.17 प्रतिशत हैं ।...(व्यवधान) ओ.बी.सी. बालिकाएँ 2,19,129 हैं, जो 35.45 प्रतिशत हैं ।...(व्यवधान) इनमें जो मुस्लिम बालिकाएँ हैं, वे 26,786 हैं । बी.पी.एल. श्रेणी की जो बालिकाएँ हैं, वे 6.79 प्रतिशत हैं ।...(व्यवधान) ये आँकड़े इस बात के साक्ष्य हैं कि हमारी सरकार बालिकाओं की शिक्षा के लिए पूरे तरीके से समर्पित है ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: असादुद्दीन ओवैसी जी को प्रश्न पूछना है, आप अपना जवाब संक्षिप्त करें ।

...(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो इन्हें आगे बढ़ाने के बारे में कहा है, तो इसकी जब आवश्यकता होगी, तब आवश्यकता के अनुसार इस पर विचार किया जाएगा ।...(व्यवधान)

12.00 hrs

श्री असादुद्दीन ओवैसी : सर, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं । ...(व्यवधान) मेरा उनसे यह क्वेश्चन है ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: पहले आप क्वेश्चन नंबर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : सर, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बोल दिया है। ...(व्यवधान) आपने मिला लिया है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, मैं आपके माध्यम से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ हैं । ...(व्यवधान) यह हुकूमत बच्चों पर जुलूम कर रही है ।...(व्यवधान) क्या यह जानते हैं कि एक बच्चे की आँख चली गई ।...(व्यवधान) बेटियों को मारा गया। इनको शर्म नहीं है ।...(व्यवधान) बच्चों को गोलियां मार रहे हैं ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं पुन: माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे अपने-अपने आसन पर विराजें । सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र के बाद शून्य काल शुरू होगा ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपने-अपने आसन पर विराजें ।

...(व्यवधान)

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

माननीय सदस्यगण, सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र के समय ऐसे बात नहीं करते हैं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप थोड़ी-बहुत ट्रेनिंग लीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप अपने-अपने आसन पर विराजें ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सचेतक जी, आप इनको थोड़ा समझाइए। एक बार सभी को अपने सीटों पर जाने दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर-2, श्री रमेश पोखरियाल जी ।

…(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक) : श्रीमन, मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 1704/17/20]

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STEEL (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, New Delhi, for the year 2018-2019, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, New Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT1705/17/20]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Oil Industry Development Board, New Delhi, for the year 2018-2019, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Oil Industry Development Board, New Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1706/17/20]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1707/17/20]

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) अधिसूचना संख्या एन-12/13/1/2016-पीएंडडी जो 27 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा संबद्ध चिकित्सालयों में अतिविशिष्ट उपचार के लिए निर्दिष्ट करने और ईएसआईसी द्वारा व्यय सीधे वहन करने के बारे में विनियम 96-ग को संशोधित किया गया है।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) संशोधन विनियम, 2018 जो 19 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-12/13/1/2016-पीएंडडी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) संशोधन विनियम, 2017 जो 7 जुलाई, 2017 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-12/13/1/2016-पीएंडडी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) संशोधन विनियम, 2019 जो 23 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एक्स-11/14/1/2019-पीएंडडी में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1708/17/20]

(4) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2019 जो 6 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 638(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2019 जो 26 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 599(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 1709/17/20]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखेः-

(एक) डॉ. अम्बेडकर इंस्टिटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़।

[Placed in Library, See No. LT1710/17/20]

(दो) इंस्टिटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, तिरूवनन्तपुरम।

[Placed in Library, See No. LT 1711/17/20]

(तीन) इंस्टिटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली ।

[Placed in Library, See No. LT 1712/17/20]

(चार) इंस्टिटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, लखनऊ ।

[Placed in Library, See No. LT 1713/17/20]

(पांच) इंस्टिटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, शिमला।

[Placed in Library, See No. LT 1714/17/20]

(छह) इंस्टिटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, मुंबई।

[Placed in Library, See No. LT 1715/17/20]

(सात) इंस्टिटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, अहमदाबाद।

[Placed in Library, See No. LT 1716/17/20]

(आठ) इंस्टिटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल।

[Placed in Library, See No. LT 1717/17/20]

(नौ) इंस्टिटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर।

[Placed in Library, See No. LT 1718/17/20]

(दस) इंस्टिटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन (सोसायटी), गुरदासपुर।

[Placed in Library, See No. LT 1719/17/20]

(ग्यारह) इंस्टिटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन (कलकत्ता) सोसायटी, कोलकाता ।

[Placed in Library, See No. LT 1720/17/20]

(बारह) इंस्टिटय़ूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, शिलांग ।

[Placed in Library, See No. LT 1721/17/20]

(तेरह) इंस्टिटय़ूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई।

[Placed in Library, See No. LT 1722/17/20]

(चौदह) इंस्टिटय़ूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, हाजीपुर।

[Placed in Library, See No. LT 1723/17/20]

(पन्द्रह) इंस्टिटय़ूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर।

[Placed in Library, See No. LT 1724/17/20]

(सोलह) इंस्टिटय़ूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी।

[Placed in Library, See No. LT 1725/17/20]

(सत्रह) इंस्टिटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर।

[Placed in Library, See No. LT 1726/17/20]

(अठारह) इंस्टिटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद।

[Placed in Library, See No. LT 1727/17/120]

(उन्नीस) इंस्टिटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर।

[Placed in Library, See No. LT 1728/17/20]

(बीस) इंस्टिटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, बंगलौर।

[Placed in Library, See No. LT 1729/17/20]

(इक्कीस) इंस्टिटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा ।

[Placed in Library, See No. LT 1730/17/20]

(बाईस) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा ।

(2) उपरोक्त संस्थानों के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1731/17/20]

(3) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1732/17/20]

(4) (एक) इंडियन क्यूलनेरी इंस्टिटय़ूट (तिरूपति एंड नोएडा), नोएडा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन क्यूलनेरी इंस्टिटय़ूट (तिरूपति एंड नोएडा), नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1733/17/20]

(5) (एक) भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1734/17/20]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY SHAMRAO DHOTRE): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Notification No. S. No. 307/Academic/2019 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 7th November, 2019, making amendments in the Statute 10(5) of the Act relating to the constitution of the Court of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya under sub-section (2) of Section 43 of the Central Universities Act, 2009.

[Placed in Library, See No. LT 1735/17/20]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Punjab, Bathinda, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Punjab, Bathinda, for the year 2018-2019, together with Audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Punjab, Bathinda, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1736/17/20]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Commission for Minority Educational Institutions, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Commission for Minority Educational Institutions, New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) Memorandum of Action Taken on the recommendations contained in the Annual Report of the National Commission for Minority Educational Institutions, New Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1737/17/20]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad (Sarva Shiksha Abhiyan), Panchkula, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad (Sarva Shiksha Abhiyan), Panchkula, for the year 2016-2017.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 1738/17/20]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the English and Foreign Languages University, Hyderabad, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the English and Foreign Languages University, Hyderabad, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the English and Foreign Languages University, Hyderabad, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1739/17/20]

(7) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Assam University, Silchar, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1740/17/20]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) by the Government of the All India Council for Technical Education, New Delhi, for the year 2018-2019, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Council for Technical Education, New Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1741/17/20]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Foundry and Forge Technology, Ranchi, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Foundry and Forge Technology, Ranchi, for the year 2017-2018.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 1742/17/20]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tripura Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Agartala, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tripura Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Agartala, for the year 2017-2018.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 1743/17/20]

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Manipur, Imphal, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Manipur, Imphal, for the year 2017-2018.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 1744/17/20]

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tezpur University, Tezpur, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tezpur University, Tezpur, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1745/17/20]

(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tripura Sarva Shiksha Abhiyan, Agartala, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tripura Sarva Shiksha Abhiyan, Agartala, for the year 2017-2018.

(17) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (16) above.

[Placed in Library, See No. LT 1746/17/20]

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Lucknow, for the years 2015-2016 to 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Lucknow, for the years 2015-2016 to 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology, Lucknow, for the years 2015-2016 to 2017-2018.

(19) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (18) above.

[Placed in Library, See No. LT 1747/17/20]

(20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the UT of Lakshadweep Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan and other Schemes, Kavaratti, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the UT of Lakshadweep Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan and other Schemes, Kavaratti, for the year 2017-2018.

(21) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (20) above.

[Placed in Library, See No. LT 1748/17/20]

(22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshadweep Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority, Kavaratti, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshadweep Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority, Kavaratti, for the year 2017-2018.

(23) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (22) above.

[Placed in Library, See No. LT 1749/17/20]

(24) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the State Project Office Rajiv Gandhi Shiksha Mission (Sarva Shiksha Abhiyan) Chhattisgarh, Raipur, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the State Project Office Rajiv Gandhi Shiksha Mission (Sarva Shiksha Abhiyan) Chhattisgarh, Raipur, for the year 2017-2018.

(25) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (24) above.

[Placed in Library, See No. LT 1750/17/20]

(26) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Berhampur, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research, Berhampur, for the year 2017-2018.

(27) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (26) above.

[Placed in Library, See No. LT 1751/17/20]

(28) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Orissa, Koraput, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Orissa, Koraput, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Orissa, Koraput, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1752/17/20]

(29) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Jabalpur, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts of the Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Jabalpur, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Jabalpur, for the year 2017-2018.

(30) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (29) above.

[Placed in Library, See No. LT 1753/17/20]

(31) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Visakhapatnam, Visakhapatnam, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Visakhapatnam, Visakhapatnam, for the year 2017-2018.

(32) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (31) above.

[Placed in Library, See No. LT 1754/17/20]

(33) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology, Malda, for the years 2011-2012 and 2013-2014 to 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology, Malda, for the years 2011-2012 and 2013-2014 to 2017-2018.

(34) Six statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (33) above.

[Placed in Library, See No. LT 1755/17/20]

(35) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, New Delhi, for the year 2018-2019, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, New Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1756/17/20]

(36) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Nagpur, Nagpur, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Nagpur, Nagpur, for the year 2017-2018.

(37) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (36) above.

[Placed in Library, See No. LT 1757/17/20]

(38) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur, for the year 2018-2019, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1758/17/20]

(39) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Association of Indian Universities, New Delhi, for the years 2013-2014 to 2015-2016.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Association of Indian Universities, New Delhi, for the years 2013-

2014 to 2015-2016, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Association of Indian Universities, New Delhi, for the years 2013-2014 to 2015-2016.

(40) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (39) above.

[Placed in Library, See No. LT 1759/17/20]

(41) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the State Project Office Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Chhattisgarh, Raipur, for the years 2014-2015 to 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the State Project Office Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Chhattisgarh, Raipur, for the years 2014-2015 to 2017-2018.

(42) Four statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (41) above.

[Placed in Library, See No. LT 1760/17/20]

(43) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Delhi, Delhi, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Delhi, Delhi, for the year 2017-2018.

(44) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (43) above.

[Placed in Library, See No. LT 1761/17/20]

(45) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Authority Punjab, S.A.S. Nagar, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Authority Punjab, S.A.S. Nagar, for the year 2017-2018.

(46) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (45) above.

[Placed in Library, See No. LT 1762/17/20]

(47) A copy of the All India Council for Technical Education (Categorization of Standalone Institutions for Grant of Graded Autonomy) Guidelines, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. AICTE/P&AP/SIS/2019 in Gazette of India dated 11th October, 2019 under sub-section (1) of Section 23 of the All India Council for Technical Education Act, 1987.

[Placed in Library, See No. LT 1763/17/20]

(48) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajasthan Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Jaipur, for the years 2016-2017 and 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajasthan Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Jaipur, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(49) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (48) above.

[Placed in Library, See No. LT 1764/17/20]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on Half yearly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget at the end of the first half of the Financial year 2019-2020 under sub-section (1) of Section 7 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 1765/17/20]

(2) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) under sub-section (8) of Section 10 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts, 1970 and 1980:-

(i) Report on the working and activities of the Allahabad Bank for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1766/17/20]

(ii) Report on the working and activities of the Bank of Maharashtra for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1767/17/20]

(iii) Report on the working and activities of the Central Bank of India for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1768/17/20]

(iv) Report on the working and activities of the Dena Bank for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1769/17/20]

(v) Report on the working and activities of the Indian Overseas Bank for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1770/17/20]

(vi) Report on the working and activities of the Punjab National Bank for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1771/17/20]

(vii) Report on the working and activities of the Union Bank of India for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1772/17/20]

(viii) Report on the working and activities of the UCO Bank for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1773/17/20]

(ix) Report on the working and activities of the Bank of Baroda for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1774/17/20]

(x) Report on the working and activities of the Canara Bank for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1775/17/20]

(xi) Report on the working and activities of the Corporation Bank of India for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1776/17/20]

(xii) Report on the working and activities of the Indian Bank for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1777/17/20]

(xiii) Report on the working and activities of the Oriental Bank of Commerce for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1778/17/20]

(xiv) Report on the working and activities of the Syndicate Bank for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1779/17/20]

(xv) Report on the working and activities of the United Bank of India for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1780/17/20]

(xvi) Report on the working and activities of the Vijaya Bank for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1781/17/20]

(xvii) Report on the working and activities of the Andhra Bank for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1782/17/20]

(xviii) Report on the working and activities of the Bank of India for the year 2018-2019, along with Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1783/17/20]

(xix) Report on the working and activities of the Punjab and Sind Bank for the year 2018-2019, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1784/17/20]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the India Infrastructure Finance Company Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the India Infrastructure Finance Company Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, along with Audited

Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1785/17/20]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2018-2019, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1786/17/20]

(5) A copy of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers)(Second Amendment) Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/27 in Gazette of India dated 29th July, 2019 under section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

[Placed in Library, See No. LT 1787/17/20]

(6) A copy the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (First Amendment) Regulations, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11 in Gazette of India

dated 2nd November, 2018 under Section 53 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 1788/17/20]

(8) A copy of the Institute of Actuaries of India (Transaction of Business at Meetings of Council) Amendment Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No. M-18013/01/2017-Ins.I(E) in Gazette of India dated 25th November, 2019 under Section 58 of the Actuaries Act, 2006.

[Placed in Library, See No. LT 1789/17/20]

(9) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working and activities of the State Bank of India, Mumbai, for the year 2018-2019, along with Audited Accounts under sub-section (4) of Section 40 of the State Bank of India Act, 1955 as amended by Banking Laws (Amendment) Act, 1985.

[Placed in Library, See No. LT 1790/17/20]

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Economic Growth, Delhi, for the year 2018-2019, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Economic Growth, Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1791/17/20]

(11) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 16 of 2019)(Compliance Audit)-(Defence Services) Army for the year ended March, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 1792/17/20]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 17 of 2019)(Compliance Audit)-(Department of Revenue-Customs) for the year ended March, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 1793/17/20]

(12) A copy of the Notification No. S.O.4308(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th November, 2019, regarding extension of the term and coverage of the Fifteenth Finance Commission and submission of

two reports by the Finance Commission under Article 280 of the Constitution read with Section 6 and 8 of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951.

[Placed in Library, See No. LT 1794/17/20]

(13) A copy of Notification No. G.S.R.980(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 31st December, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 11/2017-C.E. dated 30th June, 2017 under Section 38 of the Central Excise Act, 1944.

[Placed in Library, See No. LT 1795/17/20]

(14) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) G.S.R.764(E) published in Gazette of India dated 30th December, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in notifications mentioned therein.

(ii) G.S.R.765(E) published in Gazette of India dated 30th December, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 50/2017-Customs, dated 30th June, 2017.

(iii) G.S.R.766(E) published in Gazette of India dated 30th December, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 82/2017-Customs, dated 27th October, 2017.

(iv) G.S.R.767(E) published in Gazette of India dated 30th December, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in notifications mentioned therein.

(v) G.S.R.768(E) published in Gazette of India dated 30th December, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 53/2017-Customs, dated 30th June, 2017.

(vi) G.S.R.976(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 46/2011-Customs, dated 1st June, 2011.

(vii) G.S.R.977(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 53/2011-Customs, dated 1st July, 2011.

[Placed in Library, See No. LT 1796/17/20]

(15) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-

(i) G.S.R.905(E) published in Gazette of India dated 10th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to Impose anti-dumping duty on imports of Clear float glass originating in or exported from Pakistan, Saudi Arabia and UAE in pursuance of Final Findings of Designated Authority in sunset review of notification No. 48/2014-customs (ADD) dated 11.12.2014.

(ii) G.S.R.939(E) published in Gazette of India dated 19th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 35/2018-Customs (ADD) dated 9th July, 2018 levying definitive anti-dumping duty on import of “High Tenacity Polyester Yarn (HPTY)” ORIGINATING FROM China PR for a period of five years. The amendment seeking to amend Sr. No. 5 of the duty table to change the name of the exporter “Oriental Textile (Holding) Ltd.” to “Oriental Industries (Suzhou) Ltd”.

(iii) G.S.R.769(E) published in Gazette of India dated 30th December, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendment in the notifications, mentioned therein, .

(iv) G.S.R.18(E) published in Gazette of India dated 8th January, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to levy

countervailing duty on 'continuous Cast Copper Wire Rods' originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam, for a period of five years based on the Final Findings, dated 05.11.2019, of Directorate General of Trade Remedies.

[Placed in Library, See No. LT 1797/17/20]

(16) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 166 of the Central Goods and Service Tax Act, 2017:-

(i) G.S.R.907(E) published in Gazette of India dated 12th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing of return in FORM GSTR-1 for registered persons in Jammu and Kashmir having aggregate turnover more than 1.5 crore rupees for the months of July, 2019 to September, 2019.

(ii) G.S.R.908(E) published in Gazette of India dated 12th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing of return in FORM GSTR-1 for registered persons in Jammu and Kashmir having aggregate turnover more than 1.5 crore rupees for the month of October, 2019.

(iii) G.S.R.909(E) published in Gazette of India dated 12th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing of return in FORM GSTR-7 for registered persons in Jammu and Kashmir for the months of July, 2019 to October, 2019.

(iv) G.S.R.910(E) published in Gazette of India dated 12th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing of return in FORM GSTR-3B for registered persons in Jammu and Kashmir for the months of July, 2019 to September, 2019.

(v) G.S.R.911(E) published in Gazette of India dated 12th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing of return in FORM GSTR-3B for registered persons in Jammu and Kashmir for the month of October, 2019.

(vi) The Central Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.924(E) in Gazette of India dated 13th December, 2019, together with an explanatory memorandum.

(vii) G.S.R.925(E) published in Gazette of India dated 13th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to notify the common portal for the purpose of e-invoice.

(viii) G.S.R.926(E) published in Gazette of India dated 13th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to notify the class of registered person required to issue e-invoice.

(ix) G.S.R.927(E) published in Gazette of India dated 13th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to give effect to the provisions of rule 46 of the CGST Rules, 2017.

(x) G.S.R.928(E) published in Gazette of India dated 13th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to notify the class of registered person required to issue invoice having QR Code.

(xi) G.S.R.943(E) published in Gazette of India dated 23rd December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the last date for filing of FORM GSTR-3B for the month of November, 2019 by three days from 20.12.2019 till 23.12.2019.

(xii) G.S.R.953(E) published in Gazette of India dated 26th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to waive late fees for non- filing of FORM GSTR-1 from July, 2017 to November, 2019.

(xiii) The Central Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.954(E) in Gazette of India dated 26th December, 2019, together with an explanatory memorandum.

(xiv) G.S.R.955(E) published in Gazette of India dated 26th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing of return in FORM GSTR-1 for registered persons in Assam, Manipur or Tripura having aggregate turnover more than 1.5 crore rupees for the month of November, 2019.

(xv) G.S.R.956(E) published in Gazette of India dated 26th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing of return in FORM GSTR-3B for registered persons in Assam, Manipur, Meghalaya or Tripura for the month of November, 2019.

(xvi) G.S.R.957(E) published in Gazette of India dated 26th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to extend the due date for furnishing of return in FORM GSTR-7 for registered persons in Assam, Manipur or Tripura for the month of November, 2019.

(xvii) G.S.R.2(E) published in Gazette of India dated 1st January, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to bring into

force certain provisions of the Finance (No. 2) Act, 2019 to amend the CGST Act, 2017.

(xviii) The Central Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.4(E) published in Gazette of India dated 1st January, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to make amendment (2020) to CGST Rules.

(xix) G.S.R.5(E) published in Gazette of India dated 1st January, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to amend the notification No. 62/2019-CT dated 26.11.2019 to amend the transition plan for the UTs of J&K and Ladakh.

(xx) G.S.R.26(E) published in Gazette of India dated 10th January, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to extend the one-time amnesty scheme to file all FORM GSTR-1 from July 2017 to November, 2019 till 17th January, 2020.

(xxi) The Central Goods and Services Tax (Ninth Removal of Difficulties) Order, 2019 published in Notification No. S.O.4340(E) published in Gazette of India dated 3rd December, 2019, together with an explanatory memorandum.

(xxii) The Central Goods and Services Tax (Tenth Removal of Difficulties) Order, 2019 published in Notification No. S.O.4642(E) published in

Gazette of India dated 26th December, 2019, together with an explanatory memorandum.

(xxiii) G.S.R.761(E) published in Gazette of India dated 30th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to further amend notification No. 01/2017-Central Tax (Rate), to rationalize the rate of GST on Woven and Non-woven Bags and sacks to polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods (HS Code 3923/6305) including Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC) as per recommendations of the GST Council in its 38th Meeting.

(xxiv) G.S.R.970(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 12/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017 so as to exempt upfront amount payable for long term lease of industrial/ financial infrastructure plots by an entity having 20% or more ownership of Government as recommended by goods and Services Tax Council in its 38th meeting held on 18th December, 2019.

(xxv) G.S.R.971(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 13/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017 so as to make scope of the entry prescribing reverse charge mechanism

on renting of motor vehicle by a non-body corporate to a body corporate clear.

[Placed in Library, See No. LT 1798/17/20]

(17) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 24 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017:-

(i) G.S.R.762(E) published in Gazette of India dated 30th December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to further amend notification No. 01/2017- Integrated Tax (Rate), to rationalize the rate of GST on Woven and Non-Woven Bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods (HS Code 3923/6305) including Flexible Intermediate Bulk containers (FIBC) as per recommendations of the GST Council in its 38th Meeting.

(ii) G.S.R.972(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 9/2017-Integrated Tax (Rate) dated 28.06.2017 so as to exempt upfront amount payable for long term lease of industrial/ financial infrastructure plots by an entity having 20% or more ownership of government as recommended by Goods and Services Tax Council in its 38th meeting held on 18th December, 2019.

(iii) G.S.R.973(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 10/2017-Integrated Tax (Rate) dated 28.06.2017 so as to make scope of the entry prescribing reverse charge mechanism on renting of motor vehicle by a non-body corporate to a body corporate clear.

(iv) G.S.R.3(E) published in Gazette of India dated 1st January, 2020, together with an explanatory memorandum seeking to bring into force certain provisions of the Finance (No. 2) Act, 2019 to amend the IGST Act, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 1799/17/20]

(18) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 24 of the Union Territory Goods and Service Tax Act, 2017:-

(i) G.S.R.763(E) published in Gazette of India dated 30th Decembe, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to further amend notification No. 01/2017- Union Territory Tax (Rate), to rationalize the rate of GST on Woven and Non-Woven Bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods (HS Code 3923/6305) including Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC) as per recommendations of the GST Council in its 38th Meeting.

(ii) G.S.R.974(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 12/2017- Union Territory Tax (Rate), dated 28.06.2017 so as to exempt upfront amount payable for long term lease of industrial/ financial infrastructure plots by an entity having 20% or more ownership of Government as recommended by Goods and Services Tax Council in its 38th meeting held on 18th December, 2019.

(iii) G.S.R.975(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2019, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No. 13/2017- Union Territory Tax (Rate), dated 28.06.2017 so as to make scope of the entry prescribing reverse charge mechanism on renting of motor vehicle by a non-body corporate to a body corporate clear.

[Placed in Library, See No. LT 1800/17/20]

12.02 ½ hrs

ASSENT TO BILLS*

SECRETARY GENERAL: Sir, I lay on the Table the following three Bills passed by the Houses of Parliament during the Second Session of Seventeenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 19th November, 2019:-

1. The National Institute of Design (Amendment) Bill, 2019;
2. The Taxation Laws (Amendment) Bill, 2019; and
3. The Appropriation (No.3) Bill, 2019.

I also lay on the Table one copy each, duly authenticated by the Secretary General, Rajya Sabha, of following 12 Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:

1. The Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019
2. The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019
3. The Chit Funds (Amendment) Bill, 2019
4. The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Bill, 2019
5. The Special Protection Group (Amendment) Bill, 2019

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 1801/17/20.

6. The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Bill,
7. The National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019
8. The Citizenship (Amendment) Bill, 2019
9. The Arms (Amendment) Bill, 2019
10. The Recycling of Ships Bill, 2019
11. The International Financial Services Centres Authority Bill, 2019
12. The Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Bill, 2019.

12.03 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

12th Report

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I beg to present the Twelfth Report of the Business Advisory Committee.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आप सब से आग्रह कर रहा हूं कि अपनी-अपनी सीट पर विराजें। शून्य काल सबसे अधिक अविलंब लोक महत्व का विषय है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यदि आप 'सेव इंडिया' करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बुलाता हूं।

श्री के. मुरलीधरन जी, क्या आप बोलना चाहते हैं? आप 'सेव इंडिया' लेकर बैठे हैं। क्या आप बोलना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुरलीधरन जी, क्या आप बोलना चाहते हैं? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप बड़े विषय पर बोलो। आपने महत्वपूर्ण विषय दिया है। आपको अपनी सीट पर जाकर अपने महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहिए। आपने बोलने के लिए 'कोरोना बीमारी' विषय दिया है।

माननीय सदस्यगण, आप लोकतंत्र में चुनकर आते हैं। मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूं कि आप अपनी सीट पर विराजें ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रो. रामशंकर – उपस्थित नहीं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री सुशील कुमार सिंह ।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के विकास का एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं ।…(व्यवधान) महोदय, जगदीशपुर से हल्दिया गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है जिसके माध्यम से खाना बनाने वाली गैस को घरों की रसोई तक पहुंचाया जाएगा ।…(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि 27 फरवरी, 2019 को एक कार्यक्रम का शिलान्यास हुआ ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री सुशील कुमार सिंह: इसमें तेल मंत्रालय के अधिकारियों ने जनता के सामने यह आश्वासन दिया कि डेढ़ साल के अंदर, 18 महीने के अंदर औरंगाबाद जिला मुख्यालय शहर में हर घर की रसोई तक पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचा दी जाएगी ।…(व्यवधान) लेकिन जब इस काम में देर हुई, तो मैंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पत्र लिखा ।…(व्यवधान) गेल की तरफ से जो मुझे जवाब दिया गया है, उसमें यह जवाब है कि उन लोगों ने इसका ठेका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को दे दिया है ।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, नागरिक कानून संशोधन आने के बाद सारे हिंदुस्तान में संविधान बचाने के लिए हमारे हिंदुस्तान की आम जनता, आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं ।…(व्यवधान) यह कोई अन्याय नहीं है ।…(व्यवधान) ये हाथ में हिंदुस्तान का संविधान, राष्ट्रीय

ध्वज और राष्ट्रीय गान हाथ में लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।...(व्यवधान) इसके ऊपर गोली चलाई जाती है।...(व्यवधान) बेरहमी से हिंदुस्तान के आम लोगों का खून किया जाता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जुगल किशोर शर्मा ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप पहले सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र जम्मू की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, यह सरकार गोली से आम लोगों की बोली बंद नहीं करा सकती। यह नकली हिंदू है। यह असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू होने से ...(व्यवधान) गोली से नहीं खून किया जाता।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सीएए के विषय पर इस संसद के अंदर रात को 12 बजे तक लंबी चर्चा हो चुकी है। आप सभी माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं और जिस पर सदन में एक बार चर्चा हो जाए, उस पर दोबारा चर्चा नहीं की जाती है।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): मैं फिर से निवेदन करता हूं। I appeal to the hon. Members that they can raise any issue during the discussion on the Motion of Thanks on the President's Address ...(*Interruptions*). आप चर्चा करिए।...(व्यवधान) आप चर्चा चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं।...(व्यवधान) Do you

want discussion or not? …(*Interruptions*) You can discuss. …(*Interruptions*) Sir, I am requesting you to allow the discussion. I am requesting you to let the discussion go on. …(*Interruptions*)

श्री जुगल किशोर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे बहुत ही गम्भीर मुद्दे पर बोलने के लिए यहां मौका दिया है।…(व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र जम्मू शहर की ओर ले जाना चाहता हूं। जम्मू शहर विकासशील शहरों की श्रेणी में आ रहा है।…(व्यवधान) वहां पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है और गाड़ियों का आना-जाना भी ज्यादा हो गया है।…(व्यवधान) वहां पर मेट्रो रेल बिछाने का जो प्रोजेक्ट है, वह बना हुआ है।…(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मेट्रो रेल का काम पूरा हो।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री रितेश पाण्डेय, श्री मलूक नागर और श्री गिरीश चन्द्र को श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सभा की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए भोजन अवकाश के लिए स्थगित की जाती है।

12.09 hrs

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Thirty Minutes past Thirteen of the Clock.

13.32 hrs

The Lok Sabha reassembled after lunch at Thirty-Two Minutes past Thirteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए । जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई थी, जो माननीय सदस्य सभा पटल रखने के इच्छुक हैं, वे बीस मिनट के भीतर 377 के मामले सभा पटल पर रख दें।

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to take remedial measures to tackle locust attack destroying crops in Rajasthan.

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): राजस्थान प्रदेश के लगभग 12 जिलों में पिछले काफी समय से टिड्डियों के द्वारा मचाई जा रही तबाही की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जोकि अब तक प्रदेश की करीब 30 लाख बीघा फसलें चट कर चुकी हैं। इन टिड्डियों का विशाल दल मेरे संसदीय क्षेत्र जिला श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ भी पहुंच चुका है और अगर अभी भी इन पर काबू नहीं पाया गया तो, ये पंजाब व हरियाणा की तरफ भी रूख कर सकती हैं और वहां की फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकती है।

मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जायें।

(ii) Need to shift Krishi Vigyan Kendra in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan, to a suitable place in the constituency

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा, राजस्थान में कृषि विज्ञान केन्द्र खेड़ला खुर्द, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान में अनुपजाऊ जगह पर स्थापित है। इसके आस पास के क्षेत्र के दृष्टिकोण से अधिक सम्पन्न नहीं है जिस वजह से इस केन्द्र का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है।

किसान सम्पन्न होगा तो देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। किसान अन्नदाता ही देश के विकास की भी धुरी है । हमारी सरकार किसानों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझकर निरंतर प्रयास/काम कर रही है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि इस कृषि विज्ञान केन्द्र को इस जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह उपजाऊ जमीन के आस पास स्थापित किया जाए।

(iii) Need to develop Mohanpura dam in Madhya Pradesh as a tourist place

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): मालवा की पहचान मालव माटी गहन गंभीर, डग-डग रोटी, पगपग नीर को चरितार्थ करता मोहनपुरा डैम पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने से क्षेत्र के लाखों लोगों को पर्यटन सुविधा के साथ रोजगार के असीम अवसर प्राप्त होंगे।

(iv) Need to include Kolar Parliamentary Constituency in Jal Shakti Abhiyan Project

SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR): Good percentage of Kolar Lok sabha constituency in Karnataka is agricultural lands. Due to the absence of less rain and water resources, Kolar is facing drought. As a result most of the agricultural lands are useless and the farmers can't make a fruitful harvest. In several areas of Kolar, people are facing drinking water problems also. If there is Jal Shakti Abayan in Kolar, the area can overcome drought and drinking water problems. Jal shakti Abayan can protect the water resources and can collect the water for future usages. For solving drinking water problems, supply water in affected areas and ensure necessary steps for the same. Some interventions are needed there to overcome drought like KC Valley Projects, large number of check dams, Multi - Arch dams, water conservation, water harvesting structures, but interventions alone can't overcome drought.

So I kindly request the Government to please include Kolar Lok Sabha Constituency in "Jal Shakti Abhiayan Project".

(v) Regarding shortage of officers and staff in Union Territory of Ladakh

SHRI JAMYANG TSERING NAMGYAL (LADAKH) : People of Ladakh are very thankful to this Government for making Ladakh a Union Territory. The acute shortage of officers and staff is one of the main problems for the smooth functioning of the UT and the developmental activities that need to be carried out in a very limited working season. No new post has been created except the Advisor till date. There are only two secretaries looking after 30 departments. About 5600 out of 19878 posts are laying vacant.

Thus, I strongly urge the Government to pay special attention to recruit staff by framing the required recruitment rules and process it on fast track basis by taking Ladakh Autonomous Hill Development Councils into confidence and create new posts and recruitment for the same on priority basis.

(vi) Need to ban organizations spreading terror in the country

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Activists of the Social Democratic Party of India (SDPI) and the Popular Front of India (PH) have been apprehended by the Bengaluru Police over an attempt to murder RSS worker on December 22. He was returning home after attending a rally in support of the CAA 2019 in Bengaluru, where I too addressed the crowd.

The radicals, six of whom are in the custody of the police, had planned to assassinate leaders at the rally. They then targeted an innocent Karyakarta due to the police vigil at the rally.

The organisation has a history of spreading terror and its activists are behind murders of several innocent swayamsevaks working for the country. ED has also found financial links between PFI and violent protests in Uttar Pradesh. PFI is being investigated under the PMLA.

I request the Government to ban these organisations and do a thorough investigation of their activities.

(vii) Need to develop historical Charkhari Fort in Bundelkhand region of Uttar Pradesh

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): बुंदेलखण्ड का इतिहास आत्मा गौरव, त्याग और संघर्षों का इतिहास है। इसके गवाह इस क्षेत्र में विभिन स्थानों पर बने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण किलें है। इन किलों का प्रयोग इस क्षेत्र में पर्यटन विकास के रूप में किया जा सकता है। चरखारी पर्यटन की दृष्टि से बेहद रमणीक स्थल है। वर्षा ऋतु एंव इसके उपरांत यहाँ प्राकृतिक सौन्दर्य देखने लायक होता है और यह बुंदेलखंड के कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यदि चरखारी किले को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए तो बहुत कम लागत में पर्यटन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े बुंदेलखंड में रोजगार के नवीन अवसर पैदा होंगे । जहां भारत सहित पूरी दुनिया में ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित एवम पर्यटन से संबद्ध करने के प्रयास किए जा रहे हैं वही चरखारी के किले का प्रयोग सरकारी कार्यालय भवन के रूप में किया जा रहा है। पूर्व में भी ब्रिटिश काल में छावनी बने किलों को ऐतिहासिक धरोहरों का दर्जा दे कर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास हुये हैं।

मैं इस आलोक में भारत सरकार से यह मांग करता हूँ कि चरखारी किले का पूरा हिस्सा पर्यटन के लिए खोलना संभव न हो तो किले के कुछ हिस्से को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने के प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जाने चाहिए ।

(viii) Regarding disposal of E-waste

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI) : With the advent of the Electronic/ Digital era, Computers and Mobiles are, in particular, the most sought after items in every household in India. Resultant is production of huge quantity of Electronic-Waste in our eco-system. Needless to say, the Air, water, soil and our entire surrounding is full of E-waste now having its hazardous impact on public health and environment, as a whole.

As it known, the Government have laid down certain regulations in the form of E-Waste Management and Handling Rules but given the enormity of the problem, it has very limited impact on the creators of e-waste in the country. A data shows that almost 95% of such waste is handled/recycled by illegal Kabadiwalas and thus, the process is fraught with disastrous impact on the lives of Millions of citizens particularly, kids, pregnant ladies and elderly persons.

I would like to urge upon the Government to infuse more money into the establishments for recycling of E.-waste in the country, the Management of E-waste requires to be more professional and as per existing norms. The Government should strictly give a message to the world that in no condition, their e-waste would be permitted to be dumped in the Indian Territory. The Government may think of setting up a separate authority to look into the issues relating to E-Waste so that technological progress may be kept in sync with the health concerns of citizens.

(ix) Need to increase annual cash withdrawal limit from banks for retail traders to Rs. 5 crore per year

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): देश के खुदरा व्यापारियों एवं आढ़तियों की नकदी निकासी की समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देश में जो खुदरा व्यापारी हैं जिनका व्यापार सीधे-सीधे छोटे-छोटे किसानों, छोटे कुटीर उद्योगों के उत्पादनकर्ताओं से सीधे-सीधे जुड़ा है ऐसे व्यापारियों की नकद निकासी की सीमा प्रति वर्ष एक करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये करने का कष्ट करें । जब हम क्षेत्र भ्रमण पर जाते हैं तो छोटे-छोटे व्यापारी,आढ़ती और किसान इस समस्या से अवगत कराते हैं। वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं ।

व्यापारी और किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अतः देश की यशस्वी वित्त मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि देश के व्यापारियों और किसान, मजदूर के हित को ध्यान में रखते हुए नकद निकासी की सीमा प्रतिवर्ष एक करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये करने की कृपा करें ।

(x) Need to sanction funds for construction of railway line from Dehradun to Kalsi in Uttarakhand

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के देहरादून जिले की ओर दिलाना चाहती हूँ। मुरादाबाद मंडल के अन्तर्गत देहरादून से कालसी तक रेल लाईन बिछाने का सर्वे दो बार हो चुका है। जिसमें कोई भी टेक्नीकल फॉल्ट नहीं है। लेकिन अभी तक देहरादून से कालसी तक रेल लाईन बिछाने के लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। यह क्षेत्र पछुवादून-प्रवादून जौनसार बावर क्षेत्र में आता है और इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको अपने घर आने-जाने में भारी असुविधा होती है। इसके साथ ही साथ कालसी शिलालेख पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है एवं व्यापारिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। रेल लाईन न होने के कारण यहां के व्यापारियों तथा यहाँ आने-जाने वाले पर्यटकों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।, देहरादून से कालसी तक रेल लाईन की मांग बहुत पुरानी है और समय-समय पर मुरादाबाद मंडल के देहरादून रेलवे स्टेशन से कालसी तक रेल लाईन बिछाने की मांग होती रही है।

मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि मुरादाबाद मंडल के देहरादून रेलवे स्टेशन से कालसी तक रेल लाईन बिछाने के लिए तत्काल वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। क्षेत्र जनता आपकी आभारी रहेगी ।

(xi) Need to restart Integrated Action Plan/Additional Central Assistance programme for Left Wing Extremism affected districts in the country

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : देश के वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित प्रान्तों के करीब 82 जिलों में भारत सरकार के द्वारा विकास की योजना समेकित कार्य योजना (आईएपी) चलायी गई थी जिसका नाम बदलकर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) किया गया। इन योजनाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये आवंटित होते थे और इसके अंतर्गत बिहार के 11 जिले थे जिसमे औरंगाबाद और गया जिले शामिल थे। पूर्व में जनप्रतिनिधियों के सुझावों और अनुशंसाओं पर जिला में गठित समिति द्वारा LWE क्षेत्रों में विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती थी ।

यद्यपि आईपीए/एसीए योजना के तहत विकास योजनाओं के चयन हेतु गठित समिति में किसी भी जनप्रतिनिधि/विधायक को शामिल नहीं किया गया है। पूर्व में जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर कुछ कार्य होते थे जिससे LWE प्रभावित क्षेत्रों में विकास की किरणें पहुंचाकर नक्सल समस्या का नियंत्रण अथवा समाधान में बड़ी भूमिका निभाई जाती थी।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि समेकित कार्ययोजना/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना को पुन: प्रारम्भ किया जाये।

(xii) Need to allocate Rajasthan its due share of water for Sidhmukh Nohar Irrigation Project

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : पंजाब - हरियाणा एवं राजस्थान के जल समझोंते एवं भारत सरकार के निर्णय 1981 के अनुसार सिधमुख नोहर सिंचाई प्रणाली हेतु 0.47 एम. ए.एफ़. पानी देना निर्धारित किया गया था, जिसमें से 0.30 एम. ए.एफ़. पानी ही राजस्थान को साउथ घगर एवं झंडेवाला वितरिका से उपलब्ध है एवम शेष 0.17 एम. ए.एफ़. पानी एक्स नागल राजस्थान को नागल से भाखड़ा मेन लाइन के माधयम से राजस्थान सरकार के संसाधनो से उपलबध करवाया जाना था। उक्त भारत सरकार का निर्णय अनुबंध 1981 के अनुसार सभी सदस्य राज्यो के लिए बाध्य है। दिनांक 23.07.2007 को केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुनिशचित किया कि पंजाब ने बी. एम. एल. की सम्पूर्ण क्षमता सुनिशचित करने हेतु समस्त कार्य पूर्ण कर लिए है। भाखडा विकास प्रबंधन निगम द्वारा उकत प्रकरण भारत सरकार को निर्णय हेतु प्रेषित कर दिया गया है जो कि आवश्यक नहीं था । पानी पंजाब द्वारा समझोते के आधार पर राजस्थान को आबंटित किया गया है। हरियाणा का इस पानी से संबंध नहीं है। राजस्थान सरकार के बार-बार आग्रह के बाद भी हरियाणा के कारण हमें आबंटित शेष 0.17 एम. ए.एफ़. पानी नहीं मिल रहा है। सिधमुख, नोहर सिंचाई हेतु 0.47 एम. ए.एफ़. पानी आबंटित किया गया, इस पानी के हिसाब से नहर, वितरिका आदि का निर्माण किया गया है, लेकिन शेष बचा हुआ पानी नहीं मिलने के कारण इस क्षेत्र के किसानो में भारी रोष है, वे आंदोलित है। सरकार के समक्ष कानून व्यवस्था बनाये रखना मुश्किल हो रहा है। राजस्थान ने वर्ष 2009 में ही सिधमुख नोहर परियोजना पूर्ण कर ली है एवं परियोजना के सिंचित क्षेत्र की सिंचाई हेतु पूर्ण क्षमता विकसित कर ली है। वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के पास विचारधीन है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकरण का शीघ्र निस्तारण हेत् उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करे एवम बी. बी. एम. बी.को राजस्थान के हिस्से का 0.17 एम. ए.एफ़. पानी एक्स नांगल को देने के लिए निर्देशित करे।

मेरा सरकार से आग्रह है कि रावी व्यास के आधिक्य पानी से 0.17 एम. ए.एफ़. पानी (एक्स नांगल) राजस्थान को हरियाणा -राजस्थान सीमा पर आबंटित किया जाये।

(xiii) Need to ensure participation of Members of Parliament in decision making process for utilisation of funds collected under District Mineral Foundation for development works in Chhattisgarh.

श्री मोहन मण्डावी (कांकेर): खनिज न्यास निधि (D. M. F.) खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिये होता है, G.D.M.F. मे छतीसगढ़ के पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सांसदो की भूमिका इस मद से क्षेत्र विकास हेतु महत्वपूर्ण रहती थी । छतीसगढ़ मे डी एम एफ़ मे सांसद की भूमिका से पृथक किया गया है। कोरबा और बस्तर के माननीय सांसद को डी एम एफ़ फंड का सदस्य रखा है। शेष सांसदो को इस मद से पृथक रखा गया है।

इस बात का उल्लेख भी आवश्यक है, इस फंड का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों मे न होकर अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। डी. एम. एफ़. फंड मे सांसद की भूमिका नहीं रहने से इस मद का दुरुपयोग होना संभावित है।

अत: उक्त विषय को लेकर सरकार के संज्ञान मे लाते हुए नियमत: उचित कार्यवाही की पुरजोर मांग करता हूँ।

(xiv) Need to extend benefit of Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana to families found eligible in Jalgaon district, Maharashtra

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर) : मेरे जलगाँव जिले में PM आवास योजना के तहत क्लासिफिकेशन केटेगरी नियम से आबंटन होने से एक ब्लाक (तहसील) लेवल के गाँव में केटेगरी (ABC) से आवास का आबंटन का काम चल रहा एवं जारी है, उस पूरे ब्लाक में लाभार्थी लाभांवित नहीं होते तब तक उस ब्लाक के दूसरे गाँव में PMGAY दूसरी लिस्ट के केटेगरी D के नए लाभार्थियों जिन्होंने गत ४ से ५ वर्ष तक PMGAY आवास मिलने हेतु एप्लीकेशन किये हुए हैं तथा वंचित रहे हैं क्योकि यह गाँव जिस ब्लाक में पड़ता है उस ब्लाक में कुछ गाँव ऐसे हैं जिनको अभी तक पहले चरण के बने हुए लिस्ट के लाभार्थिओं को अभी तक आवास का आबंटन नहीं हुआ है ऐसे स्थिति पूरे महाराष्ट्र राज्य में अपितु सारे देश में हो सकती है, मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि जिस गाँव के सारे लाभार्थियों की लिस्ट के सारे लाभार्थियों को आवास का आबंटन हुआ है ऐसे सभी गाँव में दूसरे सर्वेक्षण में eligible केटेगरी D एप्लीकेशन के लाभार्थियों की लिस्ट के तहत आवास आबंटित करने का सुझाव या अनुमोदन दे जिससे जल्द से जल्द PMGAY आवास स्कीम का लाभ वंचित परिवार लाभार्थियों तक समय में पहुँच सके।

(xv) Regarding shortage of funds under MGNREGA

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): The people in the rural areas of Tamil Nadu and across the country are facing lots of problems due to more than 6 months delay in payment of wages under MGNREGA. There is severe fund shortage under MGNREGA in the States. Payment to MGNREGA workers has been stopped for the last six months and people are suffering.

I urge the Central Government to provide adequate funds for MGNREGA wages to the state governments at the earliest.

The Government must take immediate steps to help the daily wage workers whose livelihood is at stake. People in many areas of my parliamentary constituency of Karur and other parts of Tamil Nadu are still awaiting their hard earned wages for many months. There is fund shortage under MGNREGA in other states as well. The Government must release more funds under MGNREGA at the earliest.

(xvi) Need to create post of clinical pharmacist for Pharm. D graduates

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): I would like to invite the kind attention of the Government of India towards the sorry plight of the Pharm.D (Doctor of Pharmacy) graduates in India. The Course demands study for six-seven years with exorbitant fees. But after its completion, Pharm.D graduates have no job in the Government sector. This course was introduced in 2008 by Pharmacy Council of India (PCI). But the Government did not create a cadre for the post of 'Clinical Pharmacist'. They look for job opportunities in the private sector where they are offered starting salaries of mere Rs.15,000-16000 and they have to compete with the B.Pharm or M.Pharm graduates There are 233 colleges approved by the PCI to run the Pharm.D programme. They have produced an overall of 20,000 graduates, and approximately 9,000 are graduating each year.

So necessary steps should be taken to create the post of Clinical Pharmacist for Pham.D graduates in Government sector immediately.

(xvii) Regarding water problem of Tamil Nadu

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Tamil Nadu has been one of the most consistent and productive States contributing substantially to the Central Exchequer. Unfortunately, the people of Tamil Nadu are suffering a lot due to the step motherly treatment by the Centre and lackadaisical approach of the State Government. When it comes to fulfill the water needs of the people, especially the farmers both the centre and state are awfully short and inadequate.

Tamil Nadu is always starving for water and perennially been water deficit State with the annual per capita availability of water being 860 cubic meters only, as against the national average of 1869 cubic meters. It is unfortunate that the Government of Tamil Nadu at present has made no proper scientific innovative efforts in this regard but indiscreetly tapped almost all of its surface water resources. The ground water resources are most exploited and fast depleting. In several places, the ground water is not available even at 1000 feet. In this scenario, Tamil Nadu has to look for sources beyond its frontiers to meet the water needs of its growing population. Therefore, there is an urgent need to find alternate sources to meet the water needs of Tamil Nadu. The only solution to water starved Tamil Nadu is to transfer water from Godavari to Cauvery.

Though Tamil Nadu has addressed the National Water Development Agency on 4.9.2019 to divert 200 TMC ft. of water at the Tamil Nadu border to

meet the growing drinking water needs of Tamil Nadu and to stabilize the area under irrigation by linking Godavari -Cauvery, it has not led to desired result.

I urge the Union Government to take necessary steps to provide 200 TMC ft. of water from Godavari, by coordinating with the riparian states of Godavari and to finalize the preparation of Detailed Project Report of Godavari – Cauvery link and financial sanction be accorded quickly, so that the water needs of Tamil Nadu are fulfilled at the earliest.

(xviii) Need to increase pension amount under EPS 95

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): In my parliamentary district Vizianagaram, there are so many industries like Jute Mills, Granite Factories, Sugar Factories etc. Thousands of labourers are working and dependent on these industries. As per the information received from all pensioners and retired pensioners Association that only Rs. 1,000 to Rs. 2,500 is being given as pension to pensioners of EPS-95. The request is to increase pension from Rs 2500 to Rs 9000 and DA to pensioners.

I request the Hon'ble Minister to look into this very important issue.

(xix) Regarding Citizenship Amendment Act

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Since the passing of Citizenship Amendment Bill, there has been spontaneous protests all over the country. Protestors have spoken out against the unconstitutional nature of the bill which has touched upon the secular character of the Constitution. Women, students in particular are leading the agitations without party banner. The women have been protesting at Shaheen Bagh in Delhi during winter cold and also in different places of the country. Students of Jamia Millia Islamia, JNU, AMU etc., have been in the fore front of the movement. Four state assemblies, namely Kerala, Punjab, West Bengal and Rajasthan have passed resolutions calling for scrapping of the bill. There have been human chains in protest all over the country and human chain in Kerala has been 600 kilometer long. In view of these protests, I urge upon the Government of India, not to stand on prestige and take steps to scrap the Act.

(xx) Need to formulate uniform policy addressing construction restrictions and buffer zones around Defence establishments

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): It has been over two years since the Bombay High Court directed the Defence Ministry to formulate a uniform set of rules/policy addressing the construction restrictions and buffer zones around Defence establishments in the country. But unfortunately, the Ministry has so far not come up with any such rules/policy. As the redevelopment projects are stuck, dilapidated buildings can't be fixed until the Ministry comes out with a policy that would streamline the approval mechanism. I do understand the national security considerations that the military and the government have mentioned in the past, however, that shouldn't stop the government from developing a framework. Here, the argument is not regarding undermining national security but about addressing essential redevelopment projects that are not seeing the light of the day, and are just getting stuck in the Ministry's bureaucratic structure. Thus, I would sincerely urge the Hon'ble Defence Minister to take up this matter with utmost urgency.

(xxi) Need to consider cultivation of betel leave as an agricultural activity and grant the status of 'farmer' to betel leave growers in Bihar

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): बिहार में पान की खेती करने वाले लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर है। इसका मुख्य कारण है कि पान की खेती से जुड़े लोगों को माली का दर्जा दिया गया है, जबकि वो भी खेतिहर किसान हैं। उन्हें भी किसान का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे किसी भी विपरीत स्थिति में किसानों को जो सहायता मिलती है, वो सहायता पान की खेती करने वाले किसानों को भी मिले।

मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा के दो प्रखंड इस्लामपुर एवं राजगीर में मगही पान की जो खेती होती है। वह पान अपने मिठास के लिए काफी मशहूर है। दक्षिण बिहार में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं नालंदा के कई बड़े इलाकों में मगही पान की खेती होती है।

बिहार सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में पान अनुसंधान केन्द्र भी खोला गया है। मेरे गृह क्षेत्र इस्लामपुर में भी पान अनुसंधान केन्द्र तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी द्वारा खोला गया था, जिसका लाभ स्थानीय पान की खेती से जुड़े लोगों को मिल रहा है। वहाँ यह केन्द्र किसानों को उन्नत खेती एवं मौसम की जानकारी देने के लिए बनाया गया है, किन्तु पूर्णरूपेण वैज्ञानिक की नियुक्ति नहीं होने के कारण अभी आधा-अधूरा ही कार्य कर पा रहा है और बिहार के अन्य जिले जैसे समस्तीपुर, दरभगा, मधुबनी में भी देशला पान की अच्छी खेती होती है और बिहार से पान के पत्ते की सप्लाई बंगाल, ओड़ीशा एवं उत्तर प्रदेश में किया जाता है।

पान की खेती बहुत ही कच्ची खेती है। इसमें थोड़ा शीतलहर चलने, ओला गिरने एवं कुहासों से पूरी तरह से खेती चौपट हो जाती है। मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से इसकी खोती पर विपरीत असर पड़ता है।

उक्त परिस्थिति में इन्हें सहायता प्रदान करने की जरूरत है। बिहार सरकार समय-समय पर पान की खेती करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करती है, किन्तु राज्य के पास अपने सीमित आर्थिक संसाधन हैं। अगर पान की खेती से जुड़े लाखों लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, तो केन्द्र सरकार को उन्हें किसान का दर्जा देना ही होगा, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। वरना ये लोग समाज में हमेशा पिछड़ते ही चले जायेंगे।

अतः मैं माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि बिहार में पान की खेती से जुड़े लाखों लोगों को किसान का दर्जा अविलम्ब दिया जाए।

(xxii) Need to amend rules for CAMPA Funds

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Frequent death of elephants due to electrocution, both deliberate and accidental has become a major concern for the Government over the last 5 to 6 years. The number of deaths has been increasing year after year. To curb the occurrence of such deaths, Odisha Government has undertaken various initiatives such as rectification of sagging lines, coupling of poles, use of insulated conductors and spikes and fencing of sub-stations etc.

In spite of such initiatives, it hasn't been possible to keep the death of elephants in check. State Government also could not take up full-fledged step resulting in unsafe environment for elephants. DISCOMs have made a requisition of Rs. 550 crores for implementation of Phase-IV of the said scheme.

I urge upon the Government to take necessary steps to amend the rules for CAMPA Funds for strengthening electrical infrastructure in elephant movement areas to avoid death of elephants due to electrocution in Odisha.

(xxiii) Need to promote poultry Industry

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): With more than Rs. 1 lakh crore contribution to GDP and consistent annual growth at 10%, Indian poultry industry, including maize and soyabean, is providing more than 20 lakh direct and nearly 50 lakh indirect employment opportunities. Secondly, India is second largest producer of eggs and third largest producer of chicken.

When poultry industry is performing well and providing employment opportunities, there were reports in media that Government of India is going to reduce customs duty on American Chicken from 100% to 30%. It was also reported in a section of media that hon. PM assured US President, during his Howdy-Modi event that he would bring down Customs Duty on poultry to 30%.

Poultry industry is a part of agri-allied activity providing employment throughout the year in rural areas. If import duty is reduced, it will break the backbone of poultry, maize and soyabean farmers because poultry is the main consumer of maize and soya.

On the one hand, hon. Prime Minister is motivating farmers to move towards non-crop activities like poultry and other livestock to double the income and reduce pressure on land and irrigation, but on the other, if Customs Duty is

reduced, it will be like a bolt from the blue on poultry farmers and the entire sector would be ruined. In view of the above, I request GOI not to bring down Customs Duty on American chicken from the present 100%. Otherwise, it will destroy lakhs and lakhs of poultry farmers and result in collapse of entire poultry industry.

(xxiv) Need to construct four lane road on National Highway - 31 alongwith Express highway from Rajauli to Bakhtiyarpur in Nawada Parliamentary Constituency, Bihar

श्री चंदन सिंह (नवादा) : मेरे संसदीय क्षेत्र नवादा (बिहार) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 31, राजौली से बख्तियारपुर तक की स्थिति काफी खराब है। यह सड़क गुवाहाटी (आसाम) से बरही (हजारीबाग, झारखंड), नवादा, बिहारशरीफ़ और बख्तियारपुर का महत्वपूर्ण लिंक है। राजौली से बख्तियारपुर की जर्जर हालत को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा उक्त सड़क खंड को दो लेन से चार लेन में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया था एवं इस खंड को तीन पैकेज से विभाजित कर निर्माण किया जाना है। इस संबंध में, मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि विगत कई वर्षों से नवादा की आम जनता फोर लेन सड़क पर यात्रा करने का सपना देख रही है, लेकिन यह सपना कब पूरा होगा, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तक यह योजना सिर्फ फाइलों में ही नज़र आ रही है। राजमार्ग 31 फोर लेन के साथ ही एक्सप्रेसवे होने से पर्यटकों का अधिक समय यात्रा करने में नहीं बीतेगा एवं इसके साथ ही साथ कृषि व पर्यटन के बूते बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना देख रही सरकार को इसके निर्माण से काफी मदद मिलेगी। कृषि उत्पादन को अन्य प्रदेशों में भेजने में भी काफी आसानी होगी जिसका सर्वाधिक लाभ किसानों व व्यवसायियों को होगा। किसानों के समृद्ध होते ही राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वहीं पर्यटकों का ठहराव नालंदा, राजगीर, बोधगया व पावापुरी के साथ नवादा में हो सकेगा ।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 31, राजौली से बख्तियारपुर तक अविलम्ब फोर लेन के साथ-साथ एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया जाए।

13.32 ½ hrs

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं, उनको बोलने का अधिकार है, उनको अभिव्यक्ति करने का अधिकार है । आपको भी आपके समय में पर्याप्त समय और अवसर दिया जाएगा ।

…(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2020 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत अभारी हैं। "

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप गलत परंपरा मत डालिए। सदन के अंदर बाहर कही हुई बात को इंगित करना या उठाना ठीक नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सदन में गलत परंपरा शुरू नहीं कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं संसद के संयुक्त सत्र में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...(व्यवधान) मैं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं और सदन से भी कहना चाहता हूं कि सदन के सभी सदस्य राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपना समर्थन आज की कार्यवाही में व्यक्त करें। यशस्वी जनसेवक प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय सदस्य धन्यवाद दे रहे हैं। माननीय सदस्य आप अपनी-अपनी सीट पर विराजें।

...(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष महोदय, देश की 130 करोड़ जनता, मेरे लोक सभा क्षेत्र व पूरी दिल्ली की जनता, जिन्होंने एक बार पुन: विश्वास करके अपनी आवाज बनाकर यहां भेजा है। ...(व्यवधान) जिन्होंने हमारी सरकार पर पुन: विश्वास करके हमें नए जनादेश के साथ जनता की सेवा करने का मौका दिया।

इससे पहले कि मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी बात रखूं, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हमें बहुत ही गर्व है कि भारत के पास ऐसे महामहिम राष्ट्रपति हैं, जो दिन-रात जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। ...(व्यवधान) उन्होंने कुछ ही घंटे में निर्भया के कातिलों की दया याचिका ठुकरा दी। चाहे वह गुनाहगारों की दया याचिका का मामला हो, चाहे देश के लिए अति

महत्वपूर्ण आदेश लाने का मामला हो, उन्होंने जल्द से जल्द फैसले लेकर देश के जरूरी कामों को गति प्रदान की है। …(व्यवधान)

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के बारे में भी कहना चाहता हूं, जब वर्ष 2014 में यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पहली बार संसद में प्रवेश किया था तो सबसे पहले संसद के आगे अपना शीश झुकाया। जब वे दूसरे कार्यकाल में वर्ष 2019 में आए तो संविधान के आगे अपना शीश झुकाकर बताया कि देश हित सर्वोपरि है। …(व्यवधान)

13.35 hrs

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury , Kodikunnil Suresh and some other hon. Members left the House.)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके बारे में भी कहना चाहता हूं कि आपने नए कार्यकाल के पहले दो सत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पहले सत्र में 134 प्रतिशत कार्यवाही रही और दूसरे सत्र में 111 प्रतिशत तक कार्यवाही रही। आपने प्रश्नों में भी कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। आपने संसद को पेपरलैस बनाने से लेकर पहली बार जो सांसद चुनकर आए हैं, उनको मौका दिया, मैं समझता हूं कि यह भी बहुत गौरव की बात है। यह दिखाता है कि आने वाले समय में संसद कितना काम करने वाली है, देशहित में क्या-क्या फैसले लेने वाली है।

मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी है कि संसद में अब तक के कार्यकाल में इस बार सबसे अधिक महिलाओं की संख्या रही है, जो कि 78 है। मैं सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूं कि यह संख्या आने वाले कार्यकाल में और भी बढ़े। मैं प्रथम फुलटाइम फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन जी को भी बहुत बधाई देता हूं कि वह इस बार जन-जन का बजट लेकर आई हैं। उन्होंने इनकम टैक्स में

लोगों को इतनी राहत दी है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों में खुशी की लहर है। इस बजट में मैंने खास बात देखी जो केवल एक महिला ही सोच सकती है, गृहिणी ही सोच सकती है कि उन्होंने बजट के तीन भाग में से एक भाग को केयरिंग सोसाइटी का नाम दिया। इस दर्द को केवल एक महिला, एक गृहिणी ही समझ सकती है जो घर को चलाती है और आज वह देश में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो देश को चला रही हैं। हमने अभी चीन के वुहान में एक आपदा कोरोना वायरस देखी है। मुझे आज खुशी है और मैं पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को याद करता हूं, जिन्होंने केवल ट्वीट पर हजारों भारतीयों की सहायता की। अब हमारे देश ने 654 भारतीयों को वुहान से लाकर सेवा करने का बीड़ा उठाया है। इसमें न केवल भारतीय हैं, बल्कि सात मालदीव देश के भी लोग हैं।

मैंने आज अपने भाषण के पहले ही समाचार में पढ़ा कि कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अस्पताल गई हैं। मैं अपनी तरफ से और संसद के सभी सदस्यों की तरफ से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत गौरव है कि हमने इस देश में जन्म लिया। ऋषि-मुनियों ने कहा है कि भारत में जन्म लेना बहुत ही सौभाग्य की बात है। यह देश मानवता की सबसे पुरानी संस्कृति, सिन्धु व सरस्वती सभ्यता का है। यह देश भगवान श्रीराम का है। यह देश गौतम बुद्ध, गुरु नानक जी, अशोक और समुद्रगुप्त जैसे महान चक्रवर्ती सम्राटों का है । यह देश कौटिल्य, याज्ञवल्क्य और शंकराचार्य जैसे बुद्धिजीवियों का है। यह देश शिवाजी, महाराणा प्रताप, बिरसा मुंडे जैसे वीर योद्धाओं का है। यह देश लक्ष्मीबाई, सावित्री देवी, सावित्रीबाई, निवेदिता और गार्गी जैसी वीर नारी शक्तियों का है । यह देश गांधी, भगत सिंह, डॉ.अम्बेडकर, सुभाष चन्द्र बोस, असफाक उल्ला जैसे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का है। इस भारत देश की प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी है। मगर, हमारी अद्भुत संस्कृति हमारी भाषाएं, हमारा पोशाक, हमारा संगीत, हमारे नृत्य, हमारी कलाएं, हमारा

भूगोल और हमारी जैविक विविधताएं भारत देश को विश्व में अद्वितीय बनाती है। पिछले कार्यकाल में वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक मोदी जी की सरकार में इस देश में मजबूत नींव रखने का काम हुआ और इन पांच सालों में, वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक हमारे देश में एक मजबूत इमारत रखी जाएगी, जिसका आधार और मूलमंत्र होगा 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास'। ये नौजवानों की सदी होगी। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे नौजवान वाला देश है। आने वाले तीन दशकों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी एवं मजबूत आर्थिक शक्ति बनेगा। इसके लिए हमारी सरकार हर संभव कदम उठा रही है। मैं बताना चाहता हूं कि आज विपक्ष, जो इतना छोटा-सा सिकुड़ गया है, इनकी सोच और हमारी सोच में क्या फर्क होता है। हमारी सोच होती है 'काल करे सो आज कर, आज करे सो अब और अब करना है तो चालू कर' और इनकी सोच थी 'आज करे सो कल कर, कल करे सो परसो, इतनी जल्दी क्या है जब पड़े हैं वर्षों'। सारा विपक्ष यह सोचता था कि जब ये ब्लॉक से, एक ताल्लुका से, कार्पोरेशन से, विधान सभा से संसद तक एक परिवार की हुकूमत चल रही है तो इनको क्या जरूरत है देश की समस्याएं सुलझाने की, बहुत समय पड़ा है। ये देश के लोग अपने-आप को इनकी जागीर समझते थे। मगर, हमारे देश के 130 करोड़ लोगों ने यह बताया है कि यह देश किसी की जागीर नहीं है। यह देश हमारे शहीदों के सपनों को पूरा करेगा। ये लोग समस्याएं पैदा करते रहे। इन्होंने धारा 370 की समस्या पैदा की, हमने उसको खत्म किया। इन्होंने आर्टिकल 35 ए की समस्या पैदा की, हमने उसको खत्म किया। ये समस्याएं पैदा करते हैं, हम उनको खत्म करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि कोई और भी समस्या हो तो बता दीजिए, इन पांच सालों में खत्म कर देंगे। मगर, एक समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है। वह समस्या बड़ी हो गई है। वह समस्या आंख मारती है। उस समस्या का हमारे पास, हमारी सरकार के पास समाधान नहीं है।

अध्यक्ष जी, मैं किसान और फौजी परिवार से आता हूं। मेरे ताऊ जी फौजी थे। उन्होंने 1971 के युद्ध में टैंक चलाया था। मेरे पिता डॉ.साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्य मंत्री रहे और मुख्य मंत्री

बनने से पहले दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलेज में शिक्षक थे। जब उन्होंने मुख्य मंत्री की कुर्सी छोड़ी तो अगले ही दिन उन्होंने अपने कॉलेज में दोबारा शिक्षक का पद ग्रहण किया । मैंने अपने पिताजी और मेरी पार्टी के सभी राजनीतिक महानुभावों से सीखा है कि इंसान की सहजता और सरलता ही उसका चरित्र होता है। ये लोग हमें आजकल संविधान पढ़ा रहे हैं। ये लोग हमें दिखा रहे हैं कि संविधान क्या है। हमारा प्रिएम्बल कहता है- "We, the people of India." हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है। संविधान हमें कहता है कि इस देश के लोग और इस देश के लोगों का जनादेश सर्वोपरि है।

हमने इसी विपक्ष को देखा है कि जब इनकी सरकार थी तो इन्हीं के नेता अपने ऑर्डिनेंस की कॉपियां सरेआम चौक पर फाड़ा करते थे। तब इनका संविधान कहां पर चला गया था। जब सन् 1984 में सिक्खों को मारा जा रहा था, उनका कत्लेआम किया जा रहा था तो यह संविधान कहां पर था। आज ये हमें संविधान की भाषा पढ़ा रहे हैं। शायद इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा। इस संविधान पर कांस्टिट्यूट असेंबली के हर एक सदस्य के साइन थे। उसमें इनके नेता नहेरू जी के भी साइन थे। उसमें सरदार पटेल जी के भी साइन थे। उसमें आपकी पार्टी के भी नेता थे और उसमें सरदार पटेल जी के भी साइन थे। उसमें डॉ. अम्बेडकर जी के भी साइन थे। मैं उस संविधान की कॉपी लेकर आया हूं जो उसकी ऑरिजनल कॉपी है। मैं आज इस सदन को यह दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे देश में भगवान श्री राम जी को एक धर्म के साथ जोड़ दिया है। हमारे देश में श्री राम का नाम लेने से इनको लगता था कि हम कम्युनल हो गए। ये हमें सैक्युलर कम्युनल का पाठ पढ़ाने लग गए थे। मैं संविधान की ऑरिजनल कॉपी दिखाना चाहता हूं, जिसमें नेहरू जी ने इस चित्र को बाद में निकाल दिया था। यह वह संविधान की कॉपी है, जिसमें पाठ 3 में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण का चित्र है। इसको डॉ. अम्बेडकर जी ने पास किया था। इसको उस पूरी कांस्टिट्यूट असेंबली ने पास किया था। क्या आज यह संविधान भी कम्युनल हो गया है? क्या आप

इसको भी कम्युनल कहेंगे? इसके बाद पाठ 4 में डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया है, उसमें श्री कृष्ण और अर्जुन जी, जो उनको गीता का पाठ दे रहे हैं, उनका चित्र दिया गया है। इस चित्र को भी आप लोगों ने इस संविधान से निकाल दिया। इसके बाद मैं पाठ 8 में दिखाना चाहता हूं कि हमारे संकट मोचन हनुमान जी का चित्र यहां पर दिया गया है। क्या यह संविधान भी कम्युनल हो गया है, जो संविधान समानता की बात करता है। इस देश में 55 साल तक जो सरकार चली, जब वह विकास की बात करती थी तो उसमें कश्मीर नहीं होता था। जब वह विकास के बारे में योजना बनाती थी तो नार्थ ईस्ट को छोड़ देती थी। नक्सलवाद पैदा होता था। आतंकवाद पैदा होता था। यह नक्सलवाद और आतंकवाद की जड़ें आपकी सरकार के समय से देश में पसरी हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के नौजवान इसे देखें और समझें कि ये चित्र उस समय के महापुरुषों ने इस संविधान में क्यों डाले? ये चित्र किसी धर्म को प्रतीत नहीं करते हैं। भगवान श्री राम मानवता का संदेश देते हैं। भगवान श्री राम हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे आदर्शों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। हमारी जब से सरकार बनी है, तब से इनको इतना दुख हो रहा है। जिसके मन में भी होता है वह हमारे प्रधान मंत्री जी को कुछ भी बोल देता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन इन्होंने हमारे प्रधान मंत्री जी को अपशब्द न बोले हों। ये हमारे प्रधान मंत्री जी को देशद्रोही बोलते हैं। इन्होंने हमारे प्रधान मंत्री जी को ... * भी बोला। ऐसे-ऐसे घिनौने इल्ज़ाम आपने हमारे प्रधान मंत्री जी के ऊपर लगाए हैं।

> सवाल जहर का नहीं था, वह तो मैं पी गया।
> तकलीफ लोगों को तब हुई, जब मैं फिर भी जी गया।

* Not recorded

आपको यह तकलीफ होती है कि हम इतना अपशब्द बोलते हैं। इतनी गालियां देते हैं फिर भी हमें देश की जनता 303 सीटें दे देती हैं। इसलिए आपको तकलीफ होती है। चलो मान लिया कि हम बुरे हैं मगर हमारी 303 सीट आई हैं तो आप कितने बुरे हैं। कांग्रेस के पास तो केवल 52 सीटें आई हैं। हम 303 में इतने बुरे हैं तो फिर 52 में कांग्रेस कितनी बुरी है।

जब हम 303 सीटों में इतने बुरे हो गए तो 22 सीटों में टीएमसी कितनी बुरी है और एक सीट में आम आदमी पार्टी कितनी बुरी है? हमारे देश के लोग अपशब्द बोल रहे हैं और आज पूरी दुनिया हमारे देश के प्रधान मंत्री को सम्मान दे रही है, उनको हाइएस्ट सिविलियन एवार्ड दे रही है। यूनाइटेड नेशन्स ने, बिल गेट्स ने, रशिया ने, साउथ कोरिया ने और यहां तक कि मुस्लिम देशों ने भी हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को हाइएस्ट सिविलियन एवार्ड दिया है - सउदी अरब ने दिया, बहरीन ने दिया, यूएई ने दिया और हमारे देश के लोग हमारे प्रधान मंत्री जी को अपशब्द बोल रहे हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि हम विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, क्या हमारी मति मारी गई है? क्या हमारी मति मारी गई है कि हम ऐसे विपक्ष को खत्म कर दें, जहां राहुल जी हमारे स्टार प्रचारक हैं? आज वह दिल्ली में प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनको बहुत मिस कर रहे हैं। हम ऐसे विपक्ष को कभी खत्म नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम भाईचारा खत्म कर रहे हैं। हमारे आने के बाद सपा-बसपा एक हो गईं, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद कांग्रेस-शिवसेना एक हो गईं, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद कांग्रेस-आम आदमी पार्टी ने एक होकर दिल्ली में सरकार बनाई, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद ममता जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री, दोनों भाई-बहन आपस में मिल गए, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। हमारे आने के बाद ममता जी और वामपन्थी स्टेज पर हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इतना भाईचारा बढ़ रहा है। जो लोग कल तक एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, जो कल तक एक-दूसरे की शक्ल देखना पसन्द नहीं करते थे, आज वे बीस-

बीस, तीस-तीस लोग मंच पर ऐसे हाथ पकड़ रहे हैं, सारे इकट्ठे हो गए मोदी जी के लिए। मगर इस देश की जनता सर्वोपरि है, इस देश का जनादेश सर्वोपरि है, उन्होंने आपको 2019 के चुनाव में जवाब दे दिया।

मेरा पूरे देश से प्रश्न है और इस सदन से भी प्रश्न है कि क्या हमने अपनी आजादी के मोल को चुकाया? क्या हमने हमारे शहीदों के सपनों का भारत बनाया? आजादी के 70 सालों में कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, आरोप लगते रहे कि यह सरकार उस प्रान्त की है, यह सरकार अमीरों की है, यह सरकार गरीबों की है। गरीबी का नारा देकर एक परिवार की चार-चार पीढ़ियां चुनाव लड़ रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार न किसी धर्म की है, न किसी प्रान्त की है, यह सरकार सभी की है, सभी धर्मों की है, सभी प्रान्तों की है और सारे समाज की है। हमारी सरकार में जहां हम एक तरफ बुलेट ट्रेन लेकर आए, वहीं दूसरी तरफ हमने गांवों में बिजली का तार भी पहुंचाया। जहां एक तरफ हमने डिजिटल इंडिया का नारा दिया, वहीं दूसरी तरफ परम्परागत कृषि के विकास का भी नारा दिया। एक तरफ हमने नौजवानों के लिए स्किल इंडिया का नारा दिया, उनको तैयार किया और दूसरी तरफ हमने अपने बुजुर्गों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई। एक तरफ हमने स्मार्ट सिटीज पर काम किया, तो दूसरी तरफ दिल्ली में 1731 अनाधिकृत कालोनियों को पास किया। एक तरफ हम श्रीराम मन्दिर बनाने पर जोर देते हैं तो दूसरी तरफ हर गरीब के घर में शौचालय हो, इस पर भी जोर देते हैं। जहां एक तरफ हमने राष्ट्रवाद की बात की, वहीं दूसरी तरफ भारत को विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। एक तरफ हमने दलित और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दस साल के लिए बढ़ा दिया, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक रूप से जरूरतमन्द लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया।

दीन दयाल उपाध्याय जी ने हमें अन्त्योदय का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की भी सेवा करनी है। मुझे खुशी है कि हमारा नया देश एक गरीब-पिछड़े वर्ग से आए हुए व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनाता है, हमारा देश एक गरीब-पिछड़े वर्ग से आए हुए व्यक्ति अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाता है। हमारा देश गरीब-अनुसूचित जाति से आने वाले श्री राम नाथ कोविन्द जी को राष्ट्रपति बनाता है, ऐसा है मेरा देश। जब मैं 2014 में सांसद बना, मेरे घर पर बहुत सारे लोग आते थे, आपके घर पर भी जाते होंगे, यह परम्परा कांग्रेस द्वारा शुरू की गई थी कि हमारे लिए लेटर लिख दीजिए, हमें 'पद्म श्री' मिलेगा। यह हमारा देश है, जहां पत्र से नहीं, चरित्र से 'पद्म श्री' मिलना शुरू हुआ है।

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।" अर्थात कर्म करेजा फल की चिन्ता मत करो। यह हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसको पूर्ण करके दिखाया। एक जगदीश लाल आहूजा जी, 84 साल के व्यक्ति, जिनको लंगर बाबा के नाम से जाना जाता है, वह रोज 500 मरीजों को खाना खिलाते हैं, तब उनको पद्मश्री मिलता है। हमारे जावेद अहमद जी, जो खुद दिव्यांग हैं, जब वह दिव्यांग बच्चों की सेवा करते हैं, तब उनको पद्मश्री मिलता है। हमारी तुलसी गौड़ा जी, जो बूढ़ी मां हैं, हमारी अमूल्य हैं, उनको पौधों का इतना ज्ञान है कि वह जंगल में जाती हैं और जो अमूल्य पौधे-जड़ी-बूटियां हैं, उन जड़ी-बूटियों को लेकर आती हैं और हमारे मरीजों का ध्यान रखती हैं, जिनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, उनको हमारे प्रधान मंत्री जी ट्राईबल एरिया से खोजकर ले आते हैं। उनको पद्मश्री देते हैं। आज यह पद्मश्री दिल्ली में नहीं मिलता। आज यह पद्मश्री प्रधान मंत्री जी एक-एक गरीब व्यक्ति की प्रतिभाओं को खोजकर, फिर राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत करते हैं। ऐसे पद्मश्री मिलता है।

किसी भी सरकार के काम का मापदंड यह होता है कि यदि उसका देखने का तरीका सीधा और सटीक हो तो उसने कितनी समस्याओं का समाधान किया? आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने भारत की ऐसी-ऐसी समस्याओं का समाधान किया है जो देश में दशकों से थीं। अगर इस सरकार की सबसे बड़ी कोई खासियत है तो वह है इस सरकार की निर्णायकता, इस सरकार की फैसले लेने की क्षमता और वह चाहे हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हों या हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हों।

आज मैं स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे देश को जीएसटी जैसा रिफॉर्म दिया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, आप बड़े प्रोफैसर हैं। मैं बिना किताब पढ़े बता दूं कि नियम 352 में क्या है। नियम 352 में यह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर किन-किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। यही है न?

...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Can he use the President's name for the purpose of influencing the debate? ...(*Interruptions*) प्रेसीडेंट किसको पद्श्री देता है, क्या यह यहां का चर्चा का विषय है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इस पर अपनी रूलिंग दे दूं ताकि परमानेंट हो जाए। अब मैं पढ़ दूं- राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति अभिभाषण में जोड़ना है। ठीक है?

...(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं अपने पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को भी याद करना चाहता हूं और हमारे इस केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ मंत्रियों को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इन पांच सालों में एक से एक बड़े और कड़े फैसले लेकर हमारी समस्याओं का निवारण किया क्योंकि हम, हमारी सरकार कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। मैं यहां पर वह दशक और वह भयानक मंजर याद दिलाना चाहता हूं- वर्ष 1980 और 1990 के दशक में कश्मीर में क्या हुआ था। सरदार पटेल जी कहा करते थे "एक भारत, श्रेष्ठ भारत।" डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने "दो विधान, दो निशान, दो प्रधान।" यह खत्म होना चाहिए। इसके लिए अपनी शहादत दे दी। डॉ. अम्बेडकर जी ने सामाजिक न्याय का दरवाजा हर समाज के लिए खुला होना चाहिए, यह बात कही। आज अगर इन तीनों महापुरुषों की बात को किसी ने साकार किया है तो वह हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर किया है। यह बहुत बड़ी समस्या थी। कश्मीर के 40,000 वर्ष 1980 के बाद से आज तक मर चुके हैं। उनका कत्लेआम किया गया। 400 कश्मीरी पंडितों को, उनके सिर पर गोली मारकर, उनको धर्म-परिवर्तन करने के लिए कहा गया। अपनी बीबी बच्चों को, वहीं पर कश्मीर में छोड़कर, उनको परदेश भागने के लिए कहा गया। बहुत सारे लोग देश में सोचते होंगे और जो हमारी कुछ नई पीढ़ी है, शायद वह भी सोचती होगी कि अगर धारा 370 नहीं हटती तो क्या फर्क पड़ता? अगर आर्टिकल 35 ए नहीं हटता तो क्या फर्क पड़ता ? मैं बताना चाहता हूं, आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं।

14.00 hrs

यह मेरे देश को फर्क पड़ता है। जब मेरा देश अपना बजट प्रस्तुत करता है, तो उसमें कश्मीर में एम्स हॉस्पिटल देता है, आईआईएम देता है, आईआईटी देता है, 24 हजार लोगों को घर देता है। यह मेरे देश को फर्क पड़ता है।...(व्यवधान) चार लोगों के इंटरनेट कनेक्शंस कटे, चार लोगों को कमरे में

बंद कर दिया, उन्हें कौन-सी खेती करनी थी, उन्हें कौन-सा अपनी जमीन की बुआई करनी थी, उन्हें कौन-सा बाहर निकल कर हल चलाना था? आज भी वे बिरयानी खा रहे हैं, आज भी मजे कर रहे हैं। उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आज हमारी सरकार ने उन चार लोगों के बारे में नहीं सोचा, बल्कि लाखों कश्मीरियों के बारे में सोचा, इसलिए आप चिल्लाते रहे कि खून-खराबा हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन आज तक एक भी सिविलियन की मौत नहीं हुई। वहां पर हमारी सरकार का कठोर परिश्रम है।

हमारे देश में ट्रिपल तलाक हो, कोई व्हाट्सएप्प पर ट्रिपल तलाक दे देता था, कोई ई-मेल पर ट्रिपल तलाक दे देता था। किसी का खाना गर्म नहीं हुआ तो उसने ट्रिपल तलाक दे दिया, किसी को गर्म रोटी नहीं मिली तो उसने ट्रिपल तलाक दे दिया और वे सारे लोग समर्थन करते रहे। इस देश की जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, जब हमारे प्रधान मंत्री जी उनको न्याय देना चाहते हैं तो आपको उसमें भी तकलीफ होती है। बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, जहां यह नहीं है। पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, सऊदी अरब में ट्रिपल तलाक नहीं है, यूएई में ट्रिपल तलाक नहीं है। जब हम ने अपने देश में ट्रिपल तलाक की व्यवस्था पर प्रहार किया तो आज हज में हमारी महिलाओं की संख्या बढ़ी है। आज वे भी हज करने जा रही हैं।

गरीबी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या रही है, जिसको खत्म करने के लिए न जाने कितनी सरकारें इन्होंने बना डालीं। अगर किसी ने गरीबी के खिलाफ आवाज उठाई है तो वह हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री जी हैं। कभी किसी ने सोचा था कि नाई, मोची और रेहड़ीवाले, जैसे लोगों को इस देश में पेंशन मिलेगी? पेंशन सरकारी लोगों को मिलती थी। हमारी सरकार ने छोटे व्यापारियों, किसानों और असंगठित क्षेत्र में 40 करोड़ से ज्यादा काम करने वाले लोगों को पेंशन देकर, आज उनका बुढ़ापा ठीक किया है। हमारी सरकार ने 2 करोड़ गरीब लोगों को घर दिया है। हमारी सरकार ने

गरीबों के घरों में 2 करोड़, 30 लाख शौचालय बनवाए हैं। 100 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच गई है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपये किसानों के खातों में जा रहे हैं। इससे इनको दर्द होता है, क्योंकि जब ये योजना लेकर आते थे तो इनके पूर्व प्रधान मंत्री कहते थे कि केवल 15 प्रतिशत पहुंचेगा, बाकी 85 प्रतिशत किनकी जेब में जाता था? हमारे प्रधान मंत्री जी ने 38 करोड़ बैंक्स के खाते वर्ष 2014 से ही खोलना शुरू कर दिया था। तब उनका ध्येय स्पष्ट था कि कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसीलिए हमारी पांच सालों की सरकार में कोई एक रुपये का भी घोटाला नहीं बता सकता और जिसने यह बताने की कोशिश की है, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट से डांट खा कर यहां पर आ कर बैठना पड़ा। 50 करोड़ गरीबों को इलाज की सुविधा आयुष्मान योजना में, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, ढ़ाई करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शंस, साढ़े पांच करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत लोन मिल चुके हैं। जब हम ये देते हैं तो यह नहीं कहते हैं कि वे कौन-से धर्म के हैं, हम यह नहीं देखते हैं कि वे कौन-सी जाति के हैं, हम यह नहीं देखते हैं कि हमारे माननीय सांसद वहां से चुन कर आ रहे हैं या नहीं, हमारी सरकार ये सभी काम धर्म, जाति और पक्षपात के बिना करती है। इस देश की संस्कृति हमारा गौरव है। इस देश में मेरे समेत कितने हजारों, लाखों, करोड़ों युवा नारा लगाते थे कि 'सौगंध राम की खाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे'। संविधान में भगवान श्री राम का चित्र है। इस देश के लोगों की नागरिकता तो नहीं जाएगी, मगर देश के कुछ चंद लोगों ने हमारे भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर प्रश्न उठाए हैं। मैं सर्वोच्च न्यायालय को बधाई देता हूं, अपने प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने करोड़ों लोगों की सौगंध को पूरा कर दिया।

आपने हमारी सौगन्ध को पूरा कर दिया। हमारी सरकार आसमान को छूता हुआ भगवान राम लला का मन्दिर बनाने जा रही है। क्या हमें गर्व नहीं होना चाहिए? सैकड़ों वर्षों का इंतजार खत्म हो गया।

बच्चा पूछता है मम्मी से, मम्मी ये इतने आसान काम थे, जो छ: महीने में हो गये, हमने क्यों नहीं किया? मम्मी कहती है, हमें वोट बैंक प्रिय था। हम वोट बैंक के लिए लड़ते थे। जीएसटी इसलिए नहीं लाए, क्योंकि वोट बैंक भाग जाता, 370 इसलिए नहीं हटाया, क्योंकि वोट बैंक भाग जाता। क्या भगवान श्रीराम का मन्दिर एक वोट बैंक का मोहताज होगा, एक धर्म का मोहताज होगा, राजनीति का मोहताज होगा? आज मुझे फख्र है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहाँ पर राम का मन्दिर बनाने को कहा, वहाँ पर उसने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी जमीन देने का काम किया।

मेरी सरकार का विचार सर्वधर्म समभाव का है। हम यह सिर्फ कहते नहीं हैं, हमने इसे अमल करके दिखाया है। अगर भगवान राम के मन्दिर के लिए संघर्ष किया, तो हमने सऊदी अरब में बात करके भारत के हज यात्रियों के लिए कोटा भी बढ़ाया, जो आज सर्वाधिक दो लाख है। अगर हमारे देश में योगी जी की सरकार में ऐतिहासिक कुम्भ मेले का आयोजन हुआ, तो वहीं हमने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव को भी धूमधाम से मनाया। अगर हमारी सरकार में करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर काम होना शुरू हुआ, तो वहीं सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज टाउन और स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया। पारसियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी 'जियो पारसी' योजना लाकर हमारी सरकार ने काम किया। जो सरकार केवल वोट बैंक को देखती थी, आज उन माइनोरिटी लोगों के लिए 'हुनर हाट' की योजना लाकर हमने लाखों रोजगार पैदा किये।

मैं आपके समक्ष एक बात बहुत ही दु:ख के साथ रखना चाहता हूँ। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि दिल्ली में क्या हो रहा है। जहाँ हमारी भारत सरकार हर धर्म का ख्याल रख रही है, एक साल पहले दिल्ली की सरकार एक कानून लेकर आई और कहा कि दिल्ली की मस्जिदों के सभी इमामों को 18 हजार रुपये की सैलरी दी जाएगी और उसके सहायक को 16 हजार रुपये की सैलरी दी जाएगी। एक साल से दिल्ली सरकार जनता के टैक्स के पैसे से दिल्ली की मस्जिदों के इमामों और

उनके सहायकों को प्रतिमाह 18 हजार रुपये और 16 हजार रुपये की सैलरी दे रही है। मगर वह मन्दिर के पुजारी को भूल जाती है, गुरुद्वारे के ग्रंथी को भूल जाती है। क्या यह वोट बैंक की राजनीति नहीं है? …(व्यवधान) ये हमको सिखा रहे हैं। …(व्यवधान)

भारत की अर्थव्यवस्था को पाँच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का हमने जो सपना देखा है, उसके लिए हमारी सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। चाहे आईबीसी, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर लॉ, जीएसटी, रेरा, बैंकों का मर्जर हो, इन्हीं फैसलों के कारण हमारी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग बढ़ी है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग 142 से 63 हो गई, रिजोल्विंग इनसॉल्वेंसी में 108 से 52 हो गई, ग्लोबल इनोवेशन में 74 से 52 हो गई, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमने 10 पॉइंट इम्प्रूव किया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल टूरिज्म रैंकिंग में हम 52 से 34 पर आ चुके हैं।

हमारी सरकार ने स्टार्ट अप इंडिया, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कम्प्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शुरू किए। इन सब क्षेत्रों में हमारी सरकार ने अभी तक लगभग 27 हजार स्टार्ट अप्स रजिस्टर किये हैं।

यह देश तभी विकास कर सकता है, जब हमारी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो। चाहे हमारे पड़ोसी देशों का मामला हो, चाहे हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, आज हमारी सरकार के फैसलों का ही नतीजा है कि नक्सलवाद पिछले पाँच वर्षों में कम हुआ है। वर्ष 2016 में जहाँ नक्सलवाद की 1048 घटनाएँ हुईं, वहीं वर्ष 2019 में घटकर ऐसी घटनाओं की संख्या 339 पर आ गई।

हम नॉर्थ-ईस्ट इनसर्जेंसी की बात करें तो अभी हाल ही में कई ऐतिहासिक समझौते हुए है। जैसे बोडो समझौता हुआ, ब्रू-रियांग समझौता हुआ। नागालैण्ड में भी हमारा पीस प्रोसेस चल रहा है। यह अखंड भारत की कल्पना है।

अध्यक्ष जी, मेरा वर्ष 1977 का जन्म है। वर्ष 1984 में मैं सात वर्ष का था। मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि सड़कों पर आग लगाई जा रही है। हजारों सिखों का कत्ल-ए-आम किया जा रहा है। सबको उनके गले में टायर डालकर मारा जा रहा है। मैं बड़े गौरव से कह सकता हूं कि मेरी सरकार ने एसआईटी बनाई। उसने पुराने केस खुलवाए और आज सिखों के जो वे वर्ष 1984 के कातिल हैं, मेरी सरकार के कार्यकाल में आज वे जेल की हवा खा रहे हैं। वे आज सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं।

अध्यक्ष जी, मैं देश की राजधानी से आता हूं। दिल्ली एक ऐसा शहर है, जहां हमारे किसी भी जिले का शायद ही कोई व्यक्ति हो, जो दिल्ली में न रहता हो। इसलिए, हम इसे मिनी इंडिया कहते हैं, मगर जब दिल्ली की सरकार अपनी जिम्म्दारियां भूल जाती है तो वहीं भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को देखा और उसको पूरा करने का निर्णय लिया। एयर-पॉल्युशन हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। जब आप दिल्ली में आते हैं तो आप भी उसको देखते हैं, आपको भी खांसी होती है। दिल्ली को भी खांसी हो रही है। पहले एक को होती थी, आज पूरी दिल्ली को रही है।

अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने बजट में प्रायॉरिटी बेसेज़ पर नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान लागू कर के उस पर कदम उठाया है। हमारी सरकार ने दिल्ली में ईस्टर्न-वेस्टर्न पैरिफेरल रोड बनाकर, जो हजारों ट्रक्स वहां से आते थे, उनको बाहर निकालने का काम किया है, जिससे पॉल्युशन खत्म हुआ। हमारी सरकार ने 'सफर एयर क्वॉलिटी इन्डेक्स' बनाकर और उज्ज्वला योजना में हजारों-लाखों देश और पूरी दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त में गैस का कनेक्शन देकर उनके शरीर में जो सारी बीमारियां होती थी और दिल्ली में जो धुंआ होता था, उसको भी खत्म करने का काम किया है।

दिल्ली में 1,731 अनधिकृत कॉलोनी, जिन्हें आज तक 40 सालों में किसी ने पास नहीं किया, मैंने कहा शुरू में आप सारी समस्याएं खड़ी करते थे, हम उनका समाधान कर रहे हैं। मुझे याद है वर्ष 2008 का दिल्ली का चुनाव। उस समय शीला दीक्षित जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी जी के हाथों से दिल्ली के कॉलोनी वासियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स बंटवा दिए। उसके बाद दोबारा सरकार बन गई। 20 सालों में दिल्ली में एक भी कॉलोनी पास नहीं हुई। मैं आज फख्र के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली के लोग, जो आपके संसदीय क्षेत्र से भी आते हैं, आज तक उनके ऊपर जो यह तलवार लटकी रहती थी, उसको हटाने का अगर किसी ने काम किया तो हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया।

उन्होंने धर्म नहीं देखा कि किस का घर पास हो रहा है, उन्होंने हर धर्म, जाति के लोगों के लिए यह काम किया। एक बहुत बड़ा उपहार उन्होंने कॉलोनी वासियों को दिया, जब उन्होंने कैपिटल गेन्स टैक्स को, जो किसी गरीब आदमी ने 1 लाख रुपये का घर खरीदा और अगर आज उसकी कीमत 30-40 लाख रुपये हो गई है उसके ऊपर जो 30 परसेंट का कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, वह भी मेरी सरकार ने माफ कर के एक-एक गरीब, एक-एक मकान वाले को पांच लाख रुपये का उपहार दिया, उसका यह टैक्स माफ किया। पिछले पांच सालों में दिल्ली में जहां पर मेट्रो फेज़-4 को दिल्ली सरकार ढाई सालों तक अटका कर बैठा रही, वहीं मेरी सरकार ने 116 किलोमीटर के मेट्रो के फेज़-4 को मंजूरी देने का काम किया।

जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, तब इसी संसद में, यहां पर जो उस समय के सदस्य थे, उनको याद होगा कि दिल्ली का बजट देश की संसद में पढ़ा गया था। उस समय वित्त मंत्री जी, हमारे आदरणीय अरुण जेटली जी ने कहा कि मैं दिल्ली सरकार को 1,200 करोड़ रुपये देता हूं, जिससे वह 1,400 नई बसें खरीदे। दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि वे 1,200 करोड़ रुपये बैंक में पड़े-पड़े

दिल्ली सरकार के पास आज 1,800 करोड़ रुपये हो गए हैं। इन पांच सालों में जो 5,000 बसें थीं, आज वे घटकर 3,700 हो गई हैं।

दिल्ली सरकार पांच साल में केवल 200 बसें खरीद पाई, जिनका टेण्डर मई, 2019 में किया था। बसों की संख्या बढ़ने के बजाय, घट गई। पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आप जाकर देखिए कि यमुना की क्या हालत है। गुजरात में साबरमती नदी के ऊपर रिवर फ्रंट हमारी सरकार ने बनाया, उस समय मुख्य मंत्री रहे आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बनाया। हम ऐसा ही रिवर फ्रंट दिल्ली में भी यमुना नदी के ऊपर बनाएंगे, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। जहां कांग्रेस की सरकार ने यमुना की सफाई में 1200 करोड़ रुपये खर्च किए, आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई में 500 करोड़ रुपये खर्च किए, मगर आज आप वहां जाकर देखिए कि कोई आदमी डुबकी नहीं लगा सकता है। दिल्ली का मुख्य मंत्री कहता है कि मैं सबको वहां ले जाकर डुबकी दिलाऊंगा, पांच साल से बोल रहा है, लेकिन आज तक कभी उसने खुद भी यमुना में डुबकी नहीं मारी।

देश की सरकार ने कहा कि 2024 तक इस देश के प्रत्येक नागरिक को हम साफ पानी की सुविधा देंगे। मुझे दुख होता है कि शीला दीक्षित जी के समय दिल्ली में 400 टैंकर चलते थे, लेकिन आज दिल्ली में 500 टैंकर चलते हैं। दिल्ली में सीवर लाईन नहीं है, कॉलोनीज में पानी की लाईन नहीं है। यह भारत की राजधानी है। हमने इंडेक्स में देखा, जिन 21 राज्यों का सर्वे हुआ था, उनमें सर्वाधिक जहरीला पानी दिल्ली में पाया गया। दिल्ली के लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, मगर किसी को चिंता नहीं है। उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने कहा कि 2024 तक हम देश में, जब वह देश बोलते हैं तो उसमें दिल्ली भी आती है, तो दिल्ली को भी हम 2024 तक हर घर में नल से जल देंगे और स्वच्छ जल देंगे, यह हमारी सरकार ने कहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि लोग हमारे ऊपर बोल रहे हैं। क्या-क्या प्रधान मंत्री जी को बोला गया है। दिल्ली का मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री जी को जो बोलता है, मैं उनके ठीक शब्द बता रहा हूं, *... ** कुछ लोग कहते हैं कि मोदी राष्ट्रवादी है, मोदी देशभक्त है, मगर मोदी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है"। ऐसा दिल्ली का मुख्य मंत्री कहता है। जिस पार्टी को जनादेश मिला, जिसको देश की जनता ने 303 सीट जिताकर भेजा है, दिल्ली का मुख्य मंत्री उस प्रधान मंत्री के बारे में कहता है, जो प्रधान मंत्री अपनी दिवाली सियाचिन में जवानों के साथ मनाता है, वह प्रधान मंत्री जिसके नाम से हमारे पड़ोसी देश कांप जाते हैं, देश में घुसकर हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। उस प्रधान मंत्री के बारे में दिल्ली का *...** क्या इससे बड़ा देशद्रोह कोई हो सकता है? जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जब हमारे देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो दिल्ली का मुख्य मंत्री सबूत मांगता है कि कहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई। मैं अपनी सरकार और भारतीय सेना को कहना चाहता हूं कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, वे लोग अपना नाम लिस्ट में लिखवा दो, अगली सर्जिकल स्ट्राइक में वहां आपको प्लेन में भेजेंगे, वहीं पर कुर्सियां लगाकर आपको बैठाएंगे। ...(व्यवधान)

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Sir, there is a point of order. He cannot say that. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी सीट पर जाकर बोलें।

...(व्यवधान)

सुश्री महुआ मोइत्रा: सर, *... **

---

* Not recorded.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: दिल्ली में कैसी क्रांति हो रही है? दिल्ली में पांच साल में एक भी नया स्कूल नहीं बना है। दिल्ली की सरकार ने वादा किया था कि हम एक हजार स्कूल बनाएंगे, मगर एक भी नया स्कूल नहीं बना। दिल्ली की सरकार ने वादा किया था कि हम 20 नए कॉलेज बनाएंगे, लेकिन एक भी नया कॉलेज नहीं बना। दिल्ली की सरकार ने कहा था कि हम नए अस्पताल बनाएंगे, लेकिन एक भी नया अस्पताल नहीं बना। दिल्ली के मुख्य मंत्री जिस सिग्नेचर ब्रिज को दिखाते हैं, वह 1996 की हमारी सरकार में शुरू हुआ था। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपनी सीट से बोला करें और कभी भी आसन पर आज के बाद सवाल न उठाया करें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठा करें और जब मैं बोलने की इजाज़त देता हूं, तभी आपको बोलने की इजाज़त है।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: एक भी फ्लाई ओवर दिल्ली में नया नहीं बना है, जिसका शिलान्यास दिल्ली के मुख्य मंत्री ने किया हो। यह पांच साल सरकार चली है। ढाई साल तक दिल्ली के हमारे मेट्रो फेज 4 के प्रोजेक्ट को रोक कर रखा गया। दिल्ली में शीला दीक्षित जी पांच साल में विज्ञापन पर 126 करोड़ रुपये खर्च करती थीं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1400 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च किए हैं। आज दिल्ली का विकास केवल दिल्ली के अखबारों में या टेलिविजन की एड में या दिल्ली के मुख्य मंत्री के मुंह से ही हुआ है। दिल्ली का विकास दिल्ली वालों को दिखाई नहीं देता है, जिसको उन्होंने अपने हाथों से छुआ हो या अपनी आंखों से देखा हो। वह विकास दिखाई नहीं देता है। जो जेएनयू में इस देश के टुकड़े-टुकड़े करने के नारे लगाते हैं, उस टुकड़े-टुकड़े गैंग पर केस चलाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास पिछले डेढ़ साल से फाइल रखी हुई है, लेकिन दिल्ली का मुख्य

मंत्री उन पर केस चलाने की परमिशन नहीं देता है। यह हमारे भारत देश की राजधानी है। देश में हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू की, लेकिन दिल्ली में वह लागू नहीं हुई। प्रधान मंत्री आवास योजना को देश में लागू किया गया, लेकिन दिल्ली में वह लागू नहीं हुई। ग्रीन सैस के रूप में 1174 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार ने इकट्ठा किए, उसमें से केवल 272 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। 272 करोड़ रुपये में से भी 80 करोड़ रुपये अपने झूठे विज्ञापनों पर खर्च किए हैं। निर्भया फण्ड के तहत हमारी भारत सरकार ने देश में सर्वाधिक फण्ड अगर किसी को दिया है तो दिल्ली सरकार को दिया है, लेकिन दुख होता है कि 390 करोड़ रुपये उनको दिया गया लेकिन उसमें से केवल पांच प्रतिशत ही खर्च किया गया है। 95 प्रतिशत अभी तक खर्च नहीं किया गया है। 15700 टीचर्स के पद खाली हैं। 6 हजार टीचर्स पिछले पांच साल में कम हो गए हैं। हमारी 900 बसें कम हो गयी हैं। झुग्गी-झौंपड़ी वालों को झूठे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अभी प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि जहां झुग्गी है वहीं आवास देंगे, जहां झुग्गी है, वहीं मकान देंगे। अभी डीडीए ने सबका सर्वे करना शुरू किया है। हमारी सरकार बनते ही प्रधान मंत्री जी दिल्ली की हर झुग्गी को पक्का मकान देने का काम करेंगे। देहात के लिए कोई योजना नहीं लेकर आए। घेवरा मोड़ पर सौ एकड़ जमीन है, वहां कॉलेज नहीं बना पाए। देहात में सेक्शन 33 और सेक्शन 81 को अभी तक खत्म नहीं किया है।

महोदय, मैं आपसे केवल दस मिनट और चाहूंगा। दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। दिल्ली के शाहीन बाग में क्या हो रहा है? आज वहां सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। वहां जो लोग प्रोटेस्ट में बैठे हैं, वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मार देंगे, हमें जिहाद चाहिए। हमें जिन्ना वाली आजादी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वहां कह रहे हैं कि असम को देश से अलग कर देंगे, कश्मीर को देश से अलग कर देंगे। मैं इस देश को बताना

चाहता हूं कि यह ... * की सरकार नहीं है, यह श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार है। हम सीएए को कभी वापस नहीं लेंगे। यह हमारे देश की अखंडता का प्रश्न है। वहां मीडिया को मारा जा रहा है। वहां पुलिस के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री कहता है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं। मैं जब शाहीन बाग के खिलाफ बोलता हूं तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट करते हैं, मुझे बैन करवा देते हैं। मैं शाहीन बाग के खिलाफ हूं, मगर वे लोग शाहीन बाग के समर्थन में खड़े हैं। यह दिल्ली की जनता तय करेगी। भारत सरकार के हमारे मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने दिल्ली में 55 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सड़कें दिल्ली के लिए बनाने का काम किया है। आज हम देखते हैं, धौला कुआं से एयरपोर्ट तक, दिल्ली से गाजियाबाद की सड़क, द्वारका एक्सप्रेस वे, मुम्बई एक्सप्रेस वे और इस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफिरल रोड की सौगात हमारी भारत सरकार ने दी है।

दिल्ली में 26,000 करोड़ रुपयों से इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है। नेशनल वॉर म्यूजियम के लिए आज तक किसी को चिंता नहीं हुई थी, वह हमारी सरकार ने बनाया है। माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने उसके चार म्यूजियम हमारे देश के शहीदों को समर्पित कर दिए हैं। हमने 'उज्ज्वला योजना' के तहत ढाई लाख महिलाओं को गैस के कनेक्शन दिए हैं। हमने कौशल विकास केन्द्रों में हमारे तीन लाख नौजवानों को प्रशिक्षण दिया है। हमने दिव्यांग योजना में दिल्ली के 40,000 से भी ज्यादा दिव्यांग लोगों को उपकण दिए हैं। हम भारत वंदना पार्क बना रहे हैं, यह देश का सबसे बड़ा पार्क है। हमने कच्ची कालोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिया है। जहां झुग्गी वहीं मकान। मेरे लोक सभा क्षेत्र नज़फगढ़ में 100 बेडों का अस्पताल 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहा है। हमारी भारत सरकार ने दिल्ली को यह सौगात दी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अभी यहां पर

* Not recorded.

सीएए के प्रोटेस्ट में बड़े नारे लग रहे थे। इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने बोला था। I quote:

"Minorities in Bangladesh are facing persecution and it is our moral obligation to grant citizenship in a more liberal manner."

यहां पर हमारे सहयोगी गोगोई जी के पिताजी असम के मुख्य मंत्री थे। उन्होंने इस देश की सरकार से कहा था। I quote:

"I seek refugee status for people who migrated to India from Bangladesh following persecution. This in no way violates Assam Accord."

ऐसा कांग्रेस पार्टी बोलती आई है। हमारे जो हिन्दू भाई-बहन बाहर से प्रताड़ित होकर आ रहे थे, उनके फेवर में कांग्रेस के लोग बोलते आए हैं। हमारी सृष्टि में पंच तत्व होते हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। कांग्रेस की सरकार ने पिछले 55 सालों में ऐसा कोई तत्व नहीं है, जिसमें घोटाला न किया हो, ऐसा कोई तत्व नहीं है, जिसमें भ्रष्टाचार न किया हो। इस दुनिया में दो चीजें गिनना नामुमकिन है, एक तो आसमान में तारे और दूसरा कांग्रेस पार्टी के घोटाले।...(व्यवधान)

महोदय, बहुत ही दुख होता है कि विपक्ष हमारी सरकार का ऐसे विरोध करती है। वह यूएन में जाकर विरोध करते हैं। पाकिस्तान के मंत्री यूएन में जाकर हमारे भारत देश के किसी नेता की बात को क्वोट करके बोलते हैं। क्या उनको यह समझ में नहीं आता है, वह ऐसा करके हमारे देश के ऊपर अपने पक्ष को कितना कमजोर कर रहे हैं? वह हमारे देश की अखंडता को कितना कमजोर कर रहे हैं? पाकिस्तान का एक मंत्री ट्वीट करता है और कहता है कि मोदी जी को दिल्ली का चुनाव हराना है। वे

यह ट्वीट करते हैं। क्या आज पाकिस्तान यह फैसला लेगा कि वह हमारे देश के किसी भी चुनाव को कैसे प्रभावित करे और हमारे मोदी जी को कैसे हराए? मोदी मैडनेस है, इसीलिए वर्ष 2014 में देश के लोगों ने मोदी मैडनेस में हमारी सरकार बनाई थी। देश में मोदी मैडनेस है, इसीलिए वर्ष 2019 में देश के लोगों ने 303 सीटें देकर मोदी मैडनेस में हमारी सरकार फिर से बनाई है।

मैं, आखिरी में यह कहना चाहता हूं कि वे बहुत विद्वान हैं। मैं उनके जैसा विद्वान नहीं हूं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। मगर आप आज में जिओ, जो हो चुका है, आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? आप कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। जो होने वाला है, वर्ष 2024 में भी मोदी जी की सरकार बनेगी। आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए, आप आज में जिओ। दादा, आप खुश होइए कि राम जी का मंदिर बन रहा है। सभी मुंह से बोलिए, जय श्रीराम, सारे पाप धुल जाएंगे। आपके जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे, जय श्रीराम बोल दीजिए।...(व्यवधान) मैं विपक्ष से यह कहना चाहता हूं कि जयश्री राम बोलिए।...(व्यवधान) जय श्रीराम कोई धर्म नहीं है। जय श्रीराम हमारी संस्कृति का प्रतीक है। विपक्ष एक होकर बोलो, जय श्रीराम। दादा, मुंह से जय श्रीराम बोलिए।...(व्यवधान) सारे पाप धुल जाएंगे। जय श्रीराम बोल दीजिए।...(व्यवधान) महोदय, मैं बस अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप मेरी तरफ इंगित करके बोलिए। आप डायरेक्ट मत बोलिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: महोदय, मैं आखिरी में केवल इतनी ही गुज़ारिश करना चाहता हूं कि सरकार आएगी**,** सरकार जाएगी, हो सकता है कि आपकी कुछ और प्राथमिकता हो और हमारी कुछ और प्राथमिकता हो। मगर हमें साथ मिलकर चलना है। हमें मिलकर इस देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना है। हमें मिलकर हमारे देश के शहीदों के सपनों का भारत बनाना है। इसलिए, मैं आखिरी में दो पंक्ति बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा –

"अभी तो असली मंज़िल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है।
अभी तो तोली है, मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है"।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अपना समर्थन देता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। महोदय, आज मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, जो श्री प्रवेश सिंह वर्मा जी के माध्यम से प्रस्तावित किया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

14.31 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

सभापति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने, आजादी से ले कर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने वाले और विकसित करने वाले जिन राष्ट्रीय नेताओं ने योगदान दिया है, उनका आदर के साथ उल्लेख करने का काम किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया और आजादी की लड़ाई में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई, जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त, 1947 को हम आजाद हुए। बाद के दिनों में बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर जी ने आजाद भारत को संविधान दिया था। आगे अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैकड़ों देशी रियासतों को एक कर के भारत की मजबूती की नींव रखी थी। पंडित दीन दयाल जी ने अंत्योदय के विचार का दर्शन रखा। समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने समतामूलक समाज की स्थापना की परिकल्पना की। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन तमाम महापुरुषों के विचारों को, आदर्शों को हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मसात किया है। पिछले पांच वर्षों में उसको प्रतिपादित करने का भी काम किया है।

सभापति महोदया, मैं आपका और इस सदन का ध्यान वर्ष 1967 की तरफ ले जाना चाहता हूँ । जब उस समय डॉ. लोहिया ने गैर-कांग्रेसवाद का नारा दिया था और पंडित दीन दयाल जी से उनकी निकटता थी । इन दोनों ने विचार-विमर्श कर के पूरे देश में कांग्रेस के विकल्प की शुरूआत की थी । इसका व्यापक असर हुआ । सन् 1967 के विधान सभा चुनावों में उत्तर भारत में पूरे तौर पर कांग्रेस का सफाया हो गया । डॉ. राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ और अन्य दलों की आठ राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी । उनके सहयोगी पंडित दीन दयाल जी पूरे तौर से इस विचार के, गैर-कांग्रेसवाद के समर्थन में खड़े रहे ।

आज जब केन्द्र सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो उनका सपना था, माननीय नरेन्द्र मोदी जी अगुवाई में डॉ. लोहिया और पंडित दीनदयाल जी की जो परिकल्पना थी, वह पूर्णत: चरितार्थ हो गई है । मगर मुझे दुर्भाग्यवश और पीड़ा के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जिन पार्टियों ने, जिन लोगों ने गैर कांग्रेसवाद के समर्थन में खड़ा होने का काम किया था, आज दुर्भाग्यवश वे तमाम पार्टियाँ कांग्रेस के साथ खड़ा होने का काम कर रही हैं ।

महोदया, मैं आग्रह करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 में हिन्दुस्तान की जनता ने देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया । आज़ादी के वर्षों बाद वह पीड़ित समाज, जो सामाजिक न्याय की धारा में चलने वाला गरीब था, पिछड़ा था, दलित था, अल्पसंख्यक था, आदिवासी था, आज़ादी के बाद भी उनके हालात में सुधार नहीं था । कांग्रेस पार्टी ने लगातार पचास वर्षों से अधिक तक राज करने का काम किया । मगर आज के दिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के दोनों कार्यकाल मिला लीजिए तो कुल मिलाकर 5 वर्ष 8 महीने होने जा रहे हैं । मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार का कार्यकाल, जो पूरे 5 साल 8 महीने चला है, हर 100 दिन में देश

के अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों के लिए निष्ठापूर्वक और ईमानदारी पूर्वक नरेन्द्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार ने विकास के आयाम से जोड़ने का काम किया है।

हमारे साथी प्रवेश जी बोल रहे थे, जब हमारी सरकार वर्ष 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में बनी, उस समय देश के 10 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय नहीं थे। 6 लाख गाँव खुले में शौच से मुक्त नहीं थे। प्रधान मंत्री आवास के तहत गरीबों के पास 2 करोड़ पक्के मकान नहीं थे। 8 करोड़ महिलाओं के पास गैस के कनैक्शन नहीं थे। 38 करोड़ गरीबों के पास बैंक के खाते नहीं थे। ढाई करोड़ से अधिक घरों में बिजली के कनैक्शन नहीं थे। 18 हजार गाँवों में बिजली नहीं थी। 50 करोड़ लोगों को पाँच लाख तक मुफ्त के इलाज की सुविधा की व्यवस्था नहीं थी। स्किल इंडिया अभियान, स्टार्ट अप और नेशनल प्रोमोशन स्कीम के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास के साथ उन्हें स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना के तहत 5 करोड़ 54 लाख से ज्यादा उद्यमियों को 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का लोन दिया गया था। 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा का कवच नहीं था, एक लाख 34 हजार ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर और ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं थी। देश के ग्रामीण इलाकों में तीन लाख कॉमन सर्विस सेंटर नहीं थे, 8 करोड़ 78 लाख किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 43 हजार करोड़ रुपये का लाभ नहीं मिला था। प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत 1 लाख 70 हजार किलोमीटर की सड़कें नहीं बनी थीं। देश के किसानों को 22 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड जारी नहीं किए गए थे, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लागत मूल्य का डेढ़ गुना मूल्य नहीं दिया गया था। हमारी सरकार ने देश के 112 ऐसे जिलों का चयन किया है, जो अत्यंत पिछड़े थे। महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत इन जिलों को आगे करने का काम किया जा रहा है। मेरे बिहार में भी 13 ऐसे जिले हैं, जो आज़ादी के बाद से बहुत ही पिछड़े रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी का जो विजन है, उन सब को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष योजना का कार्यक्रम भी चलाया है।

अभी वर्तमान बजट में भी वे सब जो आकांक्षी जिले हैं, वहाँ एक हॉस्पिटल बनाने का भी काम किया जा रहा है, मैं यह कहना चाहता था कि देश के कौन लोग थे, जो इन समूची योजनाओं से लाभ नहीं उठा रहे थे।

ये वही लोग थे, जिन्होंने देश की आजादी में अपना जीवन खपाने का काम किया था। ये देश के वही गरीब, किसान, छात्र, नौजवान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग थे, जो टुकुर-टुकुर देख रहे थे कि उसके पास यह विकास की रोशनी कब आएगी और मैं समझता हूँ कि इस विकास की किरण को हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उनके दरवाजे तक पहुँचाने का काम किया है। हम कह सकते हैं कि आज हमारी सरकार ने गांधी, अम्बेडकर और लोहिया के सपनों को साकार करते हुए पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय के, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। देश का गरीब चाहे वह किसी जाति, धर्म का हो, वह अपने-अपने गाँव में पक्की सड़क पर, शौचालय सहित पक्के मकान में एलईडी की रोशनी में जीवन गुजारने का काम कर रहा है। वह गैस के चूल्हे पर खाना बनाने का काम कर रहा है। वह पॉकेट में एटीएम लेकर चलने का काम कर रहा है। वह आयुष्मान हेल्थ कार्ड लेकर चलने का काम कर रहा है। इसके साथ-साथ वह इंटरनेट वाला मोबाइल लेकर प्रधान मंत्री जी का भाषण सुनने का भी काम कर रहा है। ये सब काम वह कर रहा है। यह बदलाव हमारे यशस्वी, लोकप्रिय, जनप्रिय प्रधान मंत्री जी ने किया है। वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय ही हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह कमिटमेंट किया था। सेन्ट्रल हॉल की उस पहली मीटिंग में जब उन्होंने हम सब लोगों को ऐड्रेस करने का काम किया था, तो उस समय ही उनका कमिटमेंट था कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता गाँव, गरीब और किसान है। ये सारी योजनाएं, जिनका जिक्र मैंने किया है, गाँव, गरीब और किसान को फोकस करके पूरे हिन्दुस्तान के वंचित लोगों तक इन सारी योजनाओं को पहुँचाने का काम किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम लोगों ने एक कार्यक्रम के माध्यम से 'आयुष्मान भारत योजना' के लाभार्थियों का एक सम्मेलन किया

था। मैं अपने क्षेत्र की जनता का एक छोटा सा उदाहरण कोट करना चाहता हूँ, उससे आपको यह दर्शन दिख जाएगा कि इन योजनाओं के माध्यम से कौन लोग लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। जब मैंने उन लाभार्थियों से उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम फातिमा खातून, अरविन्द सिंह, रविदास, जयमंगल रविदास, ललन मांझी, नरेश पासवान, बद्री ठाकुर, अयोध्या साव, मुन्ना ततवां, अंबिका पंडित, रोहित शर्मा, राजेन्द्र चौधरी, मोहम्मद सलाउद्दीन और रामलगन यादव बताया।

महोदया, इन नामों से ही आपको बात समझ में आ जाएगी कि किन लोगों के लिए यह सरकार काम करने का काम कर रही है। सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि सरकार भेदभाव करती है। हमारी सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है। हम 'सबका साथ-सबका विकास' के माध्यम से देश के तमाम 130 करोड़ लोगों के लिए काम करते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने देश की 130 करोड़ जनता के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम करने का काम किया है। यह मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद कई ऐसे घर थे, कई ऐसे परिवार थे, जिनका अपना पक्का मकान नहीं था, उनके पास शौचालय नहीं था। आज आजादी के 70 वर्ष से अधिक बीत गए, मगर शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। हमारी सरकार, हमारे प्रधान मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2024 तक हिन्दुस्तान के 15 करोड़ घरों में, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराने का काम करेंगे, हर घर में जीवन मिशन के साथ पानी पहुँचाने का काम करेंगे। इसके लिए 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपये की राशि का उपबंध करने का काम किया गया है। मैं समझता हूँ कि देश के जो गरीब लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, दलित, आदिवासी लोग हैं, महिला, नौजवान, अल्पसंख्यक लोग हैं, उन सबको इसका लाभ मिलने वाला है। यही नहीं आज के दिन महिलाओं की आर्थिक रूप से मजबूती के लिए, आजीविका मिशन को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर 6 करोड़ 60 लाख से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है और इन महिलाओं को कम ब्याज पर लोन देने का काम किया गया है। इसका व्यापक असर पड़

रहा है। मैं उस मंत्रालय का कुछ दिन तक मंत्री था, मुझे इसका अहसास है और मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के एक गाँव में गया था और वहाँ मैंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात करने का काम किया।

एक महिला, जो उस ग्रुप की लीडर थीं, मैंने उनसे पूछा कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने पर आपको कैसा अहसास हो रहा है? इसकी सक्सेस स्टोरी यह है कि उन्होंने कहा - "मेरा पति बीमार रहता है, वह विकलांग है। मेरी तीन-तीन बच्चियां हैं। मेरे पास इतनी राशि नहीं थी। मैं तो भीख मांगती थी। पर, जब से मैंने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का काम किया है, तब से मैं इसके माध्यम से इतने पैसे कमा रही हूं कि अपने पति का इलाज़ करा रही हूं और अपनी तीनों बच्चियों को अच्छे ढंग से पढ़ाने का काम कर रही हूं। इससे मेरा जीवन सुखमय हो गया है।"

महोदया, यह तो मैंने एक छोटा-सा उदाहरण दिया है। हिन्दुस्तान में लाखों ऐसी महिलाएं हैं, जिन्होंने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ कर अपने जीवन को खुशहाल करने का काम किया है। यह सरकार का विजन है।

महोदया, मेरे संसदीय जीवन के लगभग तीस वर्ष हो गए। मैं एक बहुत ही साधारण किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी दूध बेचने का काम करते थे। बहुत लम्बे अर्से से मैंने संघर्ष करके निश्चित तौर पर अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाने का काम किया है। आज उस पक्ष की तरफ जो बैठे हुए लोग हैं, कभी मैं वहां वही हुआ करता था। मैं उसी विचारधारा का था। मगर, मैंने करीब से इन्हें देखा है। इनका जो मन है, इनकी जो सोच है, इनके जो विचार हैं, वे जनता के लिए नहीं हैं। हाल के दिनों में, छ: वर्ष पहले ही मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बना और भारतीय जनता पार्टी ने हमें जो सम्मान दिया, उसे मैं शायद कभी भूल नहीं सकता हूं। मेरी तो राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। जिस दल में मैं था, जिस दल को मैंने सींचा था, संवारा था, वहां से मुझे निकाल कर फेंकने का काम किया

गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे गले से लगाने का काम किया और केवल गले से ही नहीं लगाया, सांसद भी बनाया। मेरे 34 सालों के सार्वजनिक कार्यकाल में, जहां मैं पहले राष्ट्रीय जनता दल में था, वहां अपनी जवानी गंवाने का काम किया, पूरी निष्ठा पूर्वक मैंने अपनी जवानी गंवाने का काम किया, उसको मजबूत करने का काम किया और बस एक मिनट में अपने स्वार्थ के लिए मुझे वहां से हटाने का काम किया गया। मगर, इस भारतीय जनता पार्टी में, मैं बिल्कुल नया आया था। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि पहले कभी मैं मंत्री नहीं बना था, मगर मुझे जितना सम्मान प्रधान मंत्री जी ने दिया, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे जैसे एक दूध बेचने वाले के बेटे को उन्होंने केन्द्र में मंत्री बनाने का काम किया। यह तभी हो सकता है जब एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधान मंत्री बनता है तो दूध बेचने वाले के बेटे को सम्मान देकर अपने कैबिनेट में रखने का काम कर सकता है। यही है भारतीय जनता पार्टी, यह है इसकी सोच।

मैं तो इन लोगों को, इनकी रग-रग को पहचानता हूं। उस पक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं, मैंने उनके साथ लम्बा समय बिताया है, उनका सहयोग किया है। मैं इन्हें जानता हूं। ये देश की जनता के लिए नहीं हैं, ये अपने लिए हैं, सत्ता के लिए हैं और अपने लिए ही जीते हैं और अपने लिए ही मरते हैं और ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं।

महोदया, आज पूरे देश के पैमाने पर हंगामा मचाया जा रहा है, सी.ए.ए. के मामले पर हंगामा मचाया जा रहा है। कानूनी प्रावधानों के तहत सी.ए.ए. लागू हुआ और उसे इसी संसद ने पास किया, इसी लोक सभा और राज्य सभा ने पास किया। आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान की किताब को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अम्बेडकर जी की मूर्ति लेकर, राष्ट्रीय झंडा लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर वहां क्या हो रहा है? वहां गुमराह किया जा रहा है। भारत को

आज़ाद हुए 70 वर्षों से अधिक हो गए। इस भारत की आज़ादी के लिए हिन्दुस्तान के नौजवानों ने अपनी शहादत दी थी। इसमें चार से छ: लाख लोगों ने अपनी बलि दी थी। न जाने कितनी माँ-बहनों के माँगों का सिन्दूर मिट गया था, न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा था, यातनाएं सहनी पड़ी थीं, तब जाकर देश आज़ाद हुआ था। बहुत मुश्किल से यह देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के इतने लम्बे अर्से के बाद भी, न जाने कितनी शहादत देने के बाद भी आज आज़ाद देश में आज़ादी की मांग की जा रही है, राष्ट्रीय झण्डे को जलाने का काम किया जा रहा है, 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' कहने का काम किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं, ये कौन ताकतें हैं? क्या इससे राष्ट्र बचेगा? ऐसे लोगों के साथ जाकर काँग्रेस पार्टी के नेता उन्हें प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

महोदया, देश कैसे बचेगा? मैं कहना चाहता हूं कि इससे देश बचने वाला नहीं है। आज़ाद भारत में आज़ादी का नारा और इस आज़ाद भारत में 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग भी सिर उठाने का काम कर रहे हैं।

ये टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले कौन लोग हैं? इन पर निगाह रखनी पड़ेगी। 'पाकिस्तान जिंदाबाद' कहने वाले ये कौन लोग हैं? राष्ट्रीय झंडा तथा भारत माता को गाली देने वाले ये लोग कौन हैं? मैं कह सकता हूं कि ये लोग भारतवंशी नहीं हो सकते हैं। यह कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है। इससे मुझे पीड़ा हो रही है। इससे देश के लोगों को पीड़ा हो रही है। मैं इन सभी चीजों को देख रहा हूं और समझ रहा हूं। मेरा सार्वजनिक जीवन एक लंबे समय का हो गया है। वोट बैंक के लिए इस तरह की घटिया राजनीति मैंने कभी नहीं देखी। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों को पोलिटिक्ल पार्टी के लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं।

मैं कह देना चाहता हूं कि यह भारतवर्ष आजाद हो चुका है। यह भारतवर्ष वर्ष 2020 का भारतवर्ष है। यह वर्ष 1947 का भारतवर्ष नहीं है। अब भारत के टुकड़े नहीं होंगे। जो टुकड़े करने वाले होंगे, उनके टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि देश की रक्षा करने वाला एक वीर सपूत भारतवंशी नरेन्द्र मोदी है जिसकी रगों में भारत की राष्ट्रीयता के प्रति खून बह रहा है। हम अपनी जान दे देंगे, परंतु भारत के अब टुकड़े नहीं होने देंगे, मैं कहना चाहता हूं। ऐसे करोड़ों लोग खड़े हैं, इन टुकड़े-टुकड़े करने वालों के टुकड़े-टुकड़े करने का काम करेंगे।

महोदया, मैं बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं। मुझे आप लोगों के बारे में मालूम है। मैं आपके साथ बहुत सालों तक रहा हूं। मुझे मालूम है कि आपकी सोच क्या है। मुझे मालूम है कि आप वोट बैंक की राजनीति कैसे करते हैं। मुझे मालूम है कि आपको देश की चिंता नहीं है। इसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। मैंने आपके साथ वर्षों गुजारने का काम किया है। जब मैं वहां था तो मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी, पता नहीं कौन-सी पार्टी है। ...(व्यवधान) संघ के बारे में भी ऐसा कहा जाता था। जब इन लोगों को छोड़कर मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तो मैंने राहत महसूस की। यह वह भारतीय जनता पार्टी है जो सब के लिए सोचती है, सब के लिए जीती और मरती है। यह भारतीय जनता पार्टी है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। देश के 130 करोड़ लोगों के लिए जीती है। यह राष्ट्रवाद तथा भारतमाता को मजबूत करने के लिए जीने का काम करती है। इसे मैंने करीब से देखने का काम किया है।

महोदया, आज यही लोग, उन लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, जो इस देश के अकलियत के लोग हैं। मैं इस मंच के माध्यम से अकलियत के भाइयों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार कभी आपका नुकसान नहीं चाहती है। अगर नुकसान करने का काम किया होता तो पिछले पांच साल से हमारी सरकार है, हमने कोई विभेद करने का काम

नहीं किया। अगर हमने पानी दिया तो सब के लिए दिया, बिजली दी तो सब के लिए दी, सड़क दी तो सब के लिए दी, रोजी-रोजगार दिया तो सब के लिए दिया, आवास दिया तो सबके लिए दिया, गैस का कनेक्शन दिया तो सब के लिए दिया, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपये तक की राशि दी तो सब के लिए दी। हमने कोई भेदभाव करने का काम नहीं किया। मगर आप तमाम लोगों को बेचैनी हो रही है। आप तमाम लोगों को बेचैनी और परेशानी हो रही है। आप तमाम लोगों को अपनी वोट की राजनीति के लिए दिग्भम्रित कर रहे हैं। मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैं बहुत लंबे अर्से तक आपके साथ रहा हूं और आपकी सेवा की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इनको छोड़ो और भारतीय जनता पार्टी के नरेन्द्र मोदी जी पर विश्वास करो। वह आपके जीवन को ऊंचा उठाने का काम करेंगे ।

आज सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है। जब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी तो उस समय मैं सांसद था। सच्चर कमीशन में बताया गया कि अकलियत समुदाय की हालत कितनी खराब है। यह हमारे प्रधान मंत्री जी के जेहन में है। आपको गरीबी से निकालने के लिए, आपके रोजी-रोजगार के लिए हमारे अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट ने बहुत कुछ करने का काम किया है, बहुत सारी योजनाएं चलाने का काम किया है। आप उनके चक्कर में क्यों पड़े हो, जो वोट बैंक के सौदागर हैं। इन सौदागरों के पीछे आप मत पड़ो। ये तमाम शक्तियां आपको बर्बाद करना चाहती है और समाज से काटना चाहती है । आपका जो नाम है, उसे अपना इस्तेमाल करके अपना चेहरा चमकाना चाहती है।

यह देश ऐसे चलने वाला नहीं है। नरेन्द्र मोदी जी को देश की जनता ने चुना है और सीधे चुना है। देश में चार ही प्रधान मंत्री हुए, जिनको भारत की जनता ने सीधे चुनने का काम किया। पहले थे नेहरू जी, दूसरी थीं इंदिरा जी, तीसरे थे अटल जी और चौथे हैं मोदी जी, जिनको डायरेक्ट जनता ने चुना। जिनको जनता डायरेक्ट दो-दो बार से चुन रही है और पिछली बार से अधिक वोट से जिताकर

चुनने का काम कर रही है, तो मैं समझ सकता हूं कांग्रेस पार्टी के मित्रों और विपक्ष में बैठे हुए मित्रों के कलेजे पर सांप लोट रहा है, इनको परेशानी हो रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। हिंदुस्तान की जनता का जब तक आशीर्वाद रहेगा, मोदी बनते रहेंगे, मोदी बनते रहेंगे, मोदी बनते रहेंगे और 130 करोड़ जनता की समस्या का समाधान करते रहेंगे।...(व्यवधान) आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : राम कृपाल जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री राम कृपाल यादव: राष्ट्रपति का अभिभाषण मुझे मालूम है। आप मत सिखाइए कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है?

माननीय सभापति : आप डिसट्रैक्ट मत होइए, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदया, मैं आपसे पीड़ा के साथ आग्रह कर रहा था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कितना बड़ा काम किया? तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप था, इससे निजात किसने दिलाई? हमारे प्रधान मंत्री जी ने दिलाई। मुस्लिम महिलाएं जो आजाद भारत में रहकर भी आजादी की सांस नहीं ले रही थीं, उनको आजादी पहुंचाने का काम हमारे देश के जनप्रिय, लोकप्रिय नेता प्रधान मंत्री जी ने, जिनको पीड़ा थी, देश के हर वर्ग, हर महिला के लिए पीड़ा थी, महिलाओं को सशक्त करने के लिए तो योजना चला ही रहे हैं, खास तौर पर जो मुस्लिम महिलाएं थीं, जिनको प्रताड़ना सहनी पड़ती थी, उनको भी मुक्ति दिलाने का काम हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया। इन लोगों को कष्ट होना स्वाभाविक है, चूंकि इनके न चाहने के बाद भी देश की जो संसद है, उसने इसे पास करने का काम किया।

मोदी जी 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, किसी को अलग नहीं करते है। जैसा कि मैंने बताया, जितनी योजनायें लागू होती हैं, वे सभी के लिए होती हैं। हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने देश के नैरेटिव को चेंज करने का काम किया है और वोट बैंक की घटिया राजनीति से बाहर निकल करके गरीबों का विकास करने का काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि इनको पीड़ा होगी। हमारे मोदी जी वर्ष 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन ले जाना चाहते हैं। जब देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, हम किसको फायदा पहुंचायेंगे, देश के अंदर सामाजिक न्याय के अंतर्गत आने वाले जो गरीब लोग हैं, उनको इस अर्थव्यवस्था से फायदा मिलने वाला है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसी बजट में एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने की व्यवस्था है। इससे इनफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उससे रोजगार भी मिलेगा।

संविधान विरोधी कुछ ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं विदेशी ताकतों का भी इसमें हाथ है। मैं आग्रह करूंगा कि जो अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, देश के विकास में बाधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कहीं न कहीं विदेशी ताकतों का भी हाथ है और इस एंगल से भी जांच करने की आवश्यकता है। मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि इस एंगल से भी जांच की जाए। आज देश का माहौल खराब करने का जो काम किया जा रहा है, वह कौन सी ताकत है, इसमें कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं हो रही है?

मैं विवेकानंद जी को क्वोट करना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, "यदि आप मुझको पसंद करते हो, तो आपके दिल में मैं हूं। यदि आप मुझसे नफरत करते हो, तो मैं आपके मन में हूं।"

15.00 hrs

हर परिस्थिति में मैं अपनी शारीरिक व आत्मिक सीमा में हूं । अगर सविधान को एक सीमा मानें तो पसंद और नापसंद दोनों परिस्थिति में हम लोगों को एक सीमा में रहना चाहिए, ऐसा ज्ञानी स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था। देश के पुरखों को शिक्षा दी थी और हम सभी लोगों को इस बात को ग्रहण करना चाहिए। आप मोदी जी का भले जितना विरोध कर लीजिए, मोदी जी का अगर चेहरा पसंद नहीं आता है तो विरोध कीजिए। लेकिन, यह जीवंत लोकतंत्र है। यह जरूरी नहीं है कि आप सभी लोग हमारी सरकार का समर्थन करेंगे परंतु मोदी जी की आड़ में देश का विरोध मत कीजिए, देश के संविधान का विरोध मत कीजिए। ध्यान रखिए, सरकार आएगी, जाएगी, इसलिए देश को जीवंत रखने का काम कीजिए। देश बचेगा तो पार्टियां बचेगी लेकिन अगर देश टूट जाएगा जिसकी तरफ आप लोगों का समर्थन प्राप्त है, जो देश तोड़ने वाली ताकतें हैं, उसे कहीं न कहीं आप लोगों का संरक्षण प्राप्त है। वोट बैंक की राजनीति में इतना अंधा मत हो जाएइ कि मोदी जी का इतना भयानक विरोध करने का काम कीजिए। इतना नीचे मत गिर जाएं। संघीय व्यवस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देश के अंदर राज्यों में कहा जा रहा है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, सीएए के कानून को नहीं मानेंगे, देश कैसे चलेगा, कैसे चलेगा संविधान, कैसे बचेगा लोकतंत्र? अगर देश का संविधान कहता है कि लोक सभा और राज्य सभा से प्रस्ताव पास होता है, हमारे संविधान का आर्टिकल 264 ए कहता है कि केन्द्र सरकार के कानून को मानने को बाध्य है। राज्य सरकार कह रही है कि नहीं मानेंगे। यह कैसे चलेगा, संविधान कैसे बचेगा? हां, राज्य और केन्द्र की सीमाएं अपने-अपने ढंग से बाध्य हैं। अगर राज्य कोई काम करता है तो केन्द्र सरकार मानेगी, राज्य सरकार संविधान के आधार पर काम करता है। अगर केन्द्र सरकार कोई काम करता है तो राज्य को मानना होगा। अभी तक जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे संघवाद पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यह हमारे सिद्धांत और सोच के लिए घातक होगा।

महोदया, हर पार्टी का अपना मेनिफेस्टो होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई पार्टियां मेनिफेस्टो रखती हैं लेकिन उसको भूल जाने का काम करती हैं। हमारी पार्टी और हमारे नेता मैनिफेस्टो में जो कहते हैं उसे पूरा करने का काम करते हैं। हम जो सारा काम कर रहे हैं, मैनिफेस्टो के माध्यम से हमने देश की जनता को वादा किया था और उसी मैनिफेस्टो के आधार पर पूरा करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उस पर किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। चूंकि हम पूरे तौर पर अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर काम कर रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी की विशेषता है, कई ऐसी योजनाएं थीं, जो वर्षों से लटकी हुई थी, आपमें इतना साहस नही थी कि उन योजनाओं को पूरा कर सकें, जो कठिनाई और समस्या थी। उसको दूर करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम करती है, यही मोदी गवर्नमेंट की खासियत है। हमने उसके लिए प्रयास करने का काम किया है।

इस देश में जो योजनाएं अटकी हुई थीं, लटकी हुई थीं। मोदी जी ने पूरे तौर पर ख्याल रखने का काम किया। उसी कड़ी में देश के पुराने कोढ़ खत्म किए हैं और उसके लिए प्रयास करने का काम किया है। अभी हम लोग गलीचे और कालीन पर बैठ कर समझ रहे थे कि बहुत ही आरामदेह है, हम उसी पर बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि साफ-सुथरी है, लेकिन जब कालीन उठाया तो पता चला कि उस पर काफी धूल जमी है। हमारी सरकार प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में उस धूल को साफ करने का काम कर रही है। आप दिल थाम कर बैठिए, जब तक धूल साफ नहीं हो जाती तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम इस धूल की सफाई करके ही आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि कुछ लोग सच्चाई से मुंह फेरने का काम कर रहे हैं। सच्चाई से कब तक मुंह फेरिएगा, कुछ होने वाला नहीं है, आप देश में माहौल को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं।

हम नहीं चाहते हैं कि आम लोगों तक जीवन के विकास की रोशनी, जो माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा पहुंचाई जा रही है, उसमें कोई बाधक बने। हमें विश्वास है कि हम जिस रफ्तार के साथ काम कर

रहे हैं, अगर उसमें कोई बाधा आएगी तो हम उस बाधा को दूर करेंगे। मैं समझता हूं कि उस बाधा को दूर करके, देश की जनता के लिए हमें जो मैन्डेट मिला है, उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर सब लोगों को पीड़ा हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन उस परेशानी से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे ओजस्वी माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी, जो भारत माता के वीर सपूत हैं, ने जो कहा है, मैं उस कविता का अंश बोलना चाहता हूं –

सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की,
मैं देश को नहीं मिटने दूंगा, मैं देश को नहीं झुकने दूंगा।

माननीय प्रधान मंत्री जी इसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि वोट बैंक की राजनीति छोड़िए। देश में जिस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, आप सब इसमें कहीं न कहीं पार्टी बने हुए हैं। विपक्ष में बैठी सभी पार्टियां, सब लोग अपने वोट बैंक की चिंता मत कीजिए, देश की चिंता कीजिए। माननीय प्रधान मंत्री जी जिस प्रतिबद्धता के साथ देश के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, गरीबों के विकास के लिए काम करे हैं, सब लोग मिलजुलकर उसमें सकारात्मक सहयोग करें। विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप सरकार के कदम का सकारात्मक सहयोग करें।

मैं पुन: महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अभिभाषण एक साल का डाक्यूमेंट है, उसमें हर चीज को टच करने का काम किया गया है। एक साल तक हमारी सरकार कैसे काम करेगी, उसकी संक्षिप्त टिप्पणी दी गई है। मैं पुन: आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के कन्सट्रक्टिव कामों में देश को ऊंचाई तक पहुंचाने में सकारात्मक सहयोग कीजिए। हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि पांच विदेशी

राष्ट्रों ने उन्हें सम्मानित किया है। हमें माननीय प्रधान मंत्री जी पर गर्व हो रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश ऊंचाई पर पहुंच रहा है।

मैं आप सबसे पुन: अपील करता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन कीजिए और देश को सकारात्मक सहयोग देकर आगे बढ़ाएं। पिछड़े दलित वर्ग के लोगों, सताए हुए पीड़ितों के काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश हो रही है, माननीय प्रधान मंत्री जी ने नए राष्ट्र निर्माण के लिए, न्यु इंडिया के लिए जो सोच रखी है, आप सब उसमें सकारात्मक सहयोग करें।

इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सभापति जी ने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी पार्टी और पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-
>
> 'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2020 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।"

15.09 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

Amendments to Motion of Thanks on the President's Address

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members whose amendments to the Motion of Thanks have been circulated may, if they desire to move their amendments, send slips at the Table within 15 minutes, indicating the serial numbers of the amendments they would like to move. Only those amendments, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of amendments treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case Members find any discrepancy in their list, they may kindly bring it to the notice of the officers at the Table immediately.

———————

15.10 hrs (Shri A. Raja *in the Chair*)

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, the Address of the President has been quite disappointing. I do not have to say that because one can very well go through it and find that it does not address any of the problems that the country faces now. That is why I am saying that it is quite disappointing.

It seems that the ruling party does not at all bother about development or the problems that the country is facing. At times, the Government in power comes out with sensational communal ideas to divide the country. They think that they can always fool the people and escape with that.

If we witness the election scenario in Delhi, we can see that all other Parties, be it the Aam Aadmi Party or the Congress Party, are talking about development of the country or the problems being faced by the people, like, poverty, water, etc. What is BJP trying to do in this scenario? They are trying their level-best to make the campaign as communal as possible and to achieve this, they are going to the extent of even giving a call to shoot people. Responsible leaders, people occupying high offices, are all making such calls. Why are they doing all this? It is to make the elections in Delhi as communal as possible and derive benefit out of that. That is what their whole idea is. Delhi election is the best example to show what they are doing in the whole of the country.

In every Session of the Parliament, the Government comes out with some kind of a legislation. Of course, everybody knows that they always target the minority community in the country. By doing so, they are trying to divide the country as much as possible. They are doing it very thoughtfully with the main purpose to divide the country. This is the only idea they have. The ruling BJP Government think that it can always escape with this idea.

When we go through the President's Address, we can very well see that it does not address any issue at all. What is the state of the country? During UPA Government, our GDP was growing. During ten years of UPA Government, our country was growing. Our image at the international level was growing. We had a very ideal position all over the world. What has been India's position in the last five years? GDP has come down. Growth has stopped. Inflation has gone up. The value of rupee has gone down. Unemployment is at its maximum. Poverty is also growing. This Address of the President does not talk about any of the issues. They always think that they do not have to address any of the issues that the country faces. At the time of election, they always do something to make the situation communal.

The mandate given to them is to uphold the Constitution. On the contrary, the slogan that we hear all over the country now is to save the Constitution. What is our position internationally with regard to the Democracy Index? As per EIU,

Economist Intelligence Unit, India's position has slipped down. Earlier we had a very good position and we were supposed to be a model country.

But now, our position is going down. Now, we are internationally known for our intolerance. We are going down in the Democracy Index. It is a shame on us. India's image in the international arena is fading. Even the member countries of European Union are concerned about the Indian issue. Have they discussed it? Such a thing was not happening in the past. The European Union has expressed its concerns on the state of affairs facing this country. The international Media like *The Washington Post, The New York Times and The Economist* have started writing against us. Even the standard newspapers in India like *The Times of India*, have also expressed their concerns and have started writing against the situation now prevailing in the country. *The Times of India* has written that it may lead to a civil-war like situation if things go on like this. Finally, what will happen? Everybody is very much concerned.

Sir, our hon. Prime Minister talks about 'New India', a 'New India' that we promised to the youngsters. Is it full of hatred, anarchy, joblessness and things like that? The responsible people holding high positions, as I have said earlier, are making very unfortunate speeches. Not a single top leader of the BJP has condemned the barbaric speech that has been given in Delhi to shoot people and the followers of the BJP are carrying it out. Every day there is a shooting now.

There is no UAPA against any of these people who did it. There is no arrest. So, they are encouraging it. They are making this situation very bad in the country.

Hon. Chairperson, Sir, there are issues like CAA, NRC, and NPR. They are not bothered about the agitations that are going on. Agitations are going on. Even the political parties which supported them earlier are not supporting them now. Those who have voted in this House are very much concerned about that now. In the All-party Meeting, they were called recently. I do not think that any Party other than the BJP has supported that law. Some of them are keeping quiet. But even their partners are not happy with that. …(*Interruptions*) I will complete within one minute. Many of the hon. Chief Ministers have said that they would not implement it and that the Government is not bothered about the federal system. Again, you are saying that you will go ahead with that. Why are you so stubborn about that? You should listen to the political parties which have supported you. They have changed their attitudes. You should listen to the hon. Chief Ministers. They are saying that they are not going to implement the law in their States. So, the federal system itself is at risk.

The situation which prevails in this country is very serious. I do not think that the BJP will be able to get away with all this. They will not be able to divide the country on religious basis always. A day will come when you will face serious consequences. I am sure about that.

TEXT OF AMENDMENTS

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Hon. Chairperson, Sir, first of all, this is a very important discussion. We are discussing about the Motion of Thanks on the President's Address. But just a few minutes ago, I was talking to a senior MP, Shri N.K. Premachandran Ji who said that in the previous Lok Sabhas when such an important discussion used to take place, then the House would be full because the President's Address reflects the state of the country and the nation.

In order to hear what the Ruling Party has to say, everybody used to sit in Lok Sabha. But today what we are seeing are empty chairs and may be a few disinterested looks. There is a lack of seriousness that we are seeing right from the Treasury Benches. Where are the Cabinet Ministers? There are no Cabinet Ministers…(*Interruptions*). The Minister of Parliamentary Affairs is not here…(*Interruptions*).

HON. CHAIRPERSON: Mr. Premachandran, earlier Mr. Pandey, the Cabinet Minister was there. He has just gone to take a glass of water. Meanwhile, the other Cabinet Minister is here.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Pandey took permission from me.

SHRI GAURAV GOGOI: Hon. Chairperson, the entire country is protesting on the streets. They are protesting in the Capital of India…(*Interruptions*).

HON. CHAIRPERSON: Earlier, Mr. Mahendra Nath Pandey was here. He just took my permission to have a glass of water. Now another Minister is here. You continue please.

SHRI GAURAV GOGOI: Hon. Chairperson, it is not just the presence of one or two Ministers. But the attitude of the Ruling Party can be seen in their absence in the Treasury Benches. They have a disdain for the people of India…(*Interruptions*).

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): I would like to put the record straight. Hon. Pandey Ji was here. Even prior to that, Shri Rajnath Ji was here. Mr. Pandey had gone for a glass of water with your permission. Now I am here.

SHRI GAURAV GOGOI: When the Members from the Opposition are speaking, the Ministers left.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Mahendra Nath Pandey personally took my permission for a few minutes just to take a glass of water. I must be very categorical from the Chair. Other Ministers of State are here. Now the Government has given an undertaking that the Ministers would be there. Now please continue your speech. Your point has been well taken.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, when the Opposition initiates a discussion like this, it is the convention of the House that even the Prime Ministers used to be present. It is quite unfortunate that most of the Union Cabinet Ministers are absent. We do accept that one or two Cabinet Ministers are present. But what is the seriousness for the discussion on Presidential Address. We are expressing our thanks to the hon. President for making this Address. I know that there is no violation of rules.

SHRI PRALHAD JOSHI: You did not allow that. What is your seriousness about that?

HON. CHAIRPERSON: Mr. Gogoi, you please continue.

SHRI GAURAV GOGOI : Hon. Chairperson, we know the true state of the nation. I feel proud that today Indian people are out on the streets defending the values of the Constitution. That is democracy. We are not afraid because of what one or two Ministers have to say. They can make all kinds of remarks about shooting and about who is a traitor. We are not afraid. The people of India have voted them in and people of India can vote them out also. We are not afraid but what matters is the value of democracy. What matters is the value of Constitution. The Ruling Party has this confusion that just because they have won an election, democracy is over. Now for five years, they can rule like dictator; they can pass laws which are against the Constitution; and they can make speeches. It is rather

unfortunate. I know यह चुभता है, लेकिन बहुत गलत बात है कि आज आपके मंत्री लोगों को यह बोल रहे हैं कि देश के दुश्मन देश के लोग हैं।

Today is the first time when a ruling party is telling its party workers that the enemies of India are the people themselves. For you, the students of India are your enemies. For you, the women of India are your enemies. …(*Interruptions*). For me, they are my fellow brothers and citizens. I feel proud of them that they are reading the Constitution; they are talking about democracy; they are talking about the values of democracy; they are talking about freedom; they are talking about the values of Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose. This is democracy. Democracy is not when you win or lose an election. इलेक्शन आएंगे, जाएंगे । Democracy is when people of India understand the true meaning of freedom and the values on which independent India was founded and that is what is happening today. I am proud of that. …(*Interruptions*).

Today, we have seen so many disturbing scenes of police entering into university campuses, beating up students, beating up professors. A professor of JNU has got a gash on her wound and yet the famed Delhi police cannot nab the culprits. How is that possible? Surely, I do not doubt the Delhi police. I am proud of the Delhi police. Delhi police is a modern professional force. They are responsible for the law and order, for the safety of our citizens. They have protected us in the past on numerous terrorist attacks. But what I doubt is that

there is a political master giving them instructions …(*Interruptions*). That is why, after the incident in JNU, we have not seen anybody apprehended. The same police which has taken the law into their hands and they have protected our citizens, today in front of the Delhi police, people are shooting. People are shooting right in front of the police and nothing is happening. My question to you is, who is pulling the trigger? Is it the boy who held the gun? I do not think so. It is not the boy who held the gun, who pulled the trigger. The person who pulled the trigger are the Ministers provoking that boy. These are the Ministers who make inflammatory speeches, Ministers who should be booked under Section 153, Ministers who should not be allowed to contest elections by the Election Commission, if the Election Commission directs the police to file an FIR under Section 153. It is them. I also do not blame only the Ministers. It is not them because the Ministers are also acting under the instruction of a political master. I know some of the Ministers, they are fair gentlemen. But there is a political master sitting right at the top who is giving his tacit approval, who is giving his silent approval to his MPs to go and make inflammatory statements.

Today, we have heard inflammatory statements being made about Mahatma Gandhi. We have heard on the floor of the House inflammatory statements being made about Nathuram Godse. None of this will happen unless there is a tacit approval from the top. Why has no action been taken against the Union Minister? Why has no action been taken against an MP? Today, we felt

the pain. The Parliamentary Affairs Minister talked about the decorum of the House. We felt pain when we had to walk out when the leading speaker, when the first speaker of the BJP stood up to speak because this shows the attitude of the BJP. A person who is banned from campaigning by the Election Commission has been supported by the BJP to be the first speaker. …(*Interruptions*). If the Election Commission has deemed that the people of India, people of Delhi should not listen to that individual, then why should the Parliament listen to that person's speech? …(*Interruptions*). That just shows the attitude of BJP towards the Election Commission and the norms of what governance and democracy means.

My submission is that today we as Parliamentarians must be responsible. Have we stooped to this depth that for wining an election, we can forget about smart city, digital India, jobs, GDP, roads, electricity etc.? Are all these problems solved? Is everybody getting Rs. 15 lakh in their accounts? Is the problem of poverty gone? Is the problem of electricity over? Is the problem of unemployment gone? Is the problem of caste based injustice gone? Is the problem of inequality gone? If these problems are gone, then talk about all the issues that you want to talk about. I feel sorry about it. The first boy's name who was picked up by the police for shooting was Rambhakt Gopal. In today's India, the true Raavans are poverty, inequality, corruption, and unemployment.

Had Ram Bhakt Gopal taken on these Ravans, I would have supported him. But, unfortunately, the minds of many such young people are being polluted by ideology based on hate and communal poison. That is why Congress Party and other Parties are saying that today we have to save the ideas of India, save the ideas of Constitution and save the ideas of freedom. We can have a double-digit GDP, but if India does not remain India, then who are we? Does progress only mean that we have made roads, created electricity and given water? No doubt, your Government has done this job but that is incremental. It is not as if toilets were not built before, it was not as if roads were not being built before and it was not as if bank accounts were not created before. Governance is a continuing process and development is a continuing process. If you want to make more roads and give more jobs, I have no qualms with you. We will talk about who did more. Let us have a competition about who built more roads, who gave more jobs, who lifted people out of poverty and who created a glowing image of India. Let us have a discussion about who the real enemies of the people of India are. It is unemployment and it is inequality. People of small and rural towns are saying that here there is somebody who is driving a Mercedes and somebody is going to a big private school and they have a college degree but a young person cannot support his own family because he is not earning a good income. That is the problem that we are facing today.

Let us get away from the politics of poison and hate and let us get into the politics of hope. That is what has taken India forward. It was hope that won India her freedom and not hate. It was hope that took India forward from Independence through the troubled times of the Green Revolution, through the troubled times of the cold war and through the troubled times of the great recession in 2008. It is always hope that will take a nation forward. You, with your hate, are taking India back. Please take us forward. That is my only sincere request to you.

At the end, today there has been a fair amount of infrastructure which has been created. There has been a fair amount of health infrastructure being created. There are hospitals, schools and colleges. Health and education infrastructure are there but what people want is a good economy. This Government has got a good mandate. I agree that, in 2019, this Government has got a good mandate in Lok Sabha. And this is the Budget that you gave us! What is the point of getting such a big mandate if you cannot deliver a Budget that takes India out of the economic troubles that we are in? You released a Budget. Will the Budget reverse the highest unemployment in the last four decades? The highest unemployment was in the last four decades. Please remember that the next time you say that देश के दुश्मन वे महिला हैं या वे छात्र हैं, the highest unemployment is the real enemy. The lowest GDP was in the last six years. Will this Budget reverse the lowest GDP in the six years? It does not look so. Will this Budget

reverse private investment looking at the way private investment was going down? You have reduced corporate tax rate to 22 per cent. It is 15 per cent for new manufacturing companies. How much private investment has taken place? Your entire economy and vision are empty and devoid and you are full of just pure rhetoric. You are famous for giving something with one hand and taking away something from the other hand. You are giving relief by corporate tax but farmers are not getting any relief. Why are farmers of India not getting a loan waiver? Why are the farmers of India not getting massive investments with the kind of benefits that you are giving to the corporate sector?

We will only help our Indian economy grow if we invest in rural India, if we invest in our farmers and if we invest in our small shops and small traders. If we neglect rural India and if you think that if the Prime Minister is meeting the top 15 industrialists, the problems of Indian economy is solved, then you are living in a fool's world. You are living in a fool's paradise. Those 15 top industrialists that the Prime Minster is meeting will not solve India's economic problems. The farmers of India, the labourers and farmers of India, the teachers of India and the civil society of India are the ones who can solve the problems of India's economy and that is past. If you look at the time when India was growing in double digits during the UPA-I and UPA-II, you would see how rural India was growing. Please see the per capita consumption in rural India. Rural India was sending its kids to

school; they were buying new vehicles; and they were expanding the capacity of their farms. It is only when rural India grows, the rest of India grows.

But I do not know why the Government has failed to see this. They keep on being distracted by what is coming on the headlines. Headline management can only take you so far but the problems will not go away. We come here for five years. For five years, our responsibility is to develop a good Government. That is our Number one responsibility. If we do not fulfil our Number one responsibility, then there is no point of that power. With great power comes great responsibility. I must say that you have wasted the first five years of 2014, and on the path that you have set out, you are going to waste the next five years. I compliment that while you are wasting your time in power, the people of India are telling us that we must protect ourselves, we must live in harmony, we must live in collective peace, we must solve the real problems. My faith is that in the end, neither you nor I, but it is the people of India who will lead the way forward. Let me again tell you that you might give us any threats. आप कितनी भी गोली मार लो, कितने भी भाषण दे लो, कितनी भी धमकी दे दो, भारत के लोग डरने वाले नहीं हैं। आप यह समझ लो कि न भारत की महिलाएँ डरेंगी, न भारत के युवा डरेंगे, न भारत के किसान डरेंगे और न भारत के श्रमिक डरेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Hon. Chairperson, I rise to thank the hon. President who has delivered the President's Address on the 31st of last month. Sir, I would like to mention and record in this august House that today is the 51st Death Anniversary of Dr. C.N. Annadurai who has relentlessly fought for equality before law, and also for the cause of social justice. He was the one who founded the DMK 70 years ago in which I have got the opportunity of serving the public and my Party for the past 63 years, for the cause of social justice, secularism, and to promote self-respect in this country with the pillars of dignity, decorum and duty.

Sir, when I see you in the exalted Chair of this august House, I can only feel sorry that today, Anna is no more, and at the same time, but Dr. Kalaignar Karunanidhi, who has brought you up to this level, is also no more. But their footsteps are followed by Dr. M.K. Stalin. Dr. Stalin is here to safeguard the principles and policies of the then Leaders Dr. Anna and Dr. Kalaignar Karunanidhi.

Sir, when the President addresses both the Houses of Parliament, he has to read the Address submitted by the Government of India. We know that. That is what he has done but he has not gone through it thoroughly whether the things which have been inside the President's Address are true or not. He has not testified it. In Tamil, there is one Kural:

"Epporul Yaaryaarvai Ketpinum Apporul
Meipporul Kaanpa Tharivu"

It means, 'whatever is said by diverse people, to discern the truth in everything is wisdom'. But this Address was delivered by the hon. President. He stated that by 2022, the income of farmers will be doubled. Where is the chance for doubling the farmers' income? The GDP of agriculture is only two per cent. Even in the Budget, they have not invested much in agriculture. They are investing only Rs. 1.80 lakh crore in the agriculture sector. In my district, we are not getting crop loan and crop insurance even today. The farmers are not having proper irrigation infrastructure. Moreover, there were three cyclones in our area. Remedial measures have not been extended so far in respect of all these three cyclones. The farmers are making a hue and cry about it. Every time, during the harvest season, they are not getting remunerative price for their produce. The Government is not providing proper market for the farmers' produce. In such a scenario, how can they double the income of farmers? This Government made a big claim about Swaminathan Report. They made loud voices. Have they ever adopted Dr. M.S. Swaminathan's Report? It is all there only on paper. They have not made any attempt to implement Swaminathan's Report.

Sir, when Anna spoke in the Rajya Sabha in front of stalwarts like Nehruji, Atal Bihari Vajpayeeji, Morarjibhai, Bhupesh Gupta and others, he pleaded for

unity and he has totally condemned uniformity. What is happening today? The actors have changed, but the stage is the same. That is what I want to mention here today. For the past six decades, whichever Government comes and goes, actors have changed, but the stage is the same and the Indian Union is the same. People are not getting solace. The oppressed people are not getting social justice even today. They are exploited and there is no relief for them. We could see only some semblance of social justice in the Constitution because of the forefathers who fought for social justice.

First of all, I would like to thank the President because he has mentioned *Thirukkural* during his Address written by Saint Thiruvalluvar of Tamil Nadu. I can say only this much, not beyond that. But as I said earlier, he has not identified whatever is stated in the President's Address is true or not.

Sir, on the 15th of January, on the Pongal day when people are celebrating Sankaranthi and when people are celebrating the harvest festival in Tamil Nadu, one of the hon. Minister's office has issued a Tender Notice. What was that Tender Notice all about? The Tender Notice was inviting Expression of Interest for Petroleum Blocks in the Cauvery Delta districts of Thanjavur, Tiruchirappalli, Pudukkottai, Nagappattinam, Tiruvarur and Cuddalore.

Is it correct on the part of the Government? I want to know this from all my friends who are from the ruling party. You touch your heart and tell whether the

petroleum blocks could be bid for oil exploration in the delta area. We are already suffering for want of Cauvery water for so many years. The Delta farmers are suffering. More than 44 lakh labourers are getting their daily bread from agriculture. Around 40 million tons of grains are being produced there. The farming communities, having 4000 years old tradition, are living there. Around 122 lakh people are living in these six districts. Now, this bolt from the blue has come on 15.01.2020. Is it fair on the part of this Government? They have offered 274 blocks to the private agencies. They are going to explore the oil out of these 274 blocks. If the oil is there, will they go ahead? What is their expectation?

I would like to know whether any cost-benefit ratio has been identified. It is not even one per cent. I was the Petroleum Minister in 1996. I know what it is. Even in the Bay of Bengal the oil exploration has not materialised. What are you going to achieve? You are simply fooling and threatening the people. It is because you, my friends, have been disappointed during the elections. You have been deserted during the elections. The delta farmers have deserted BJP that is why they are trying to desert the whole delta area of Thanjavur, Trichy, Cuddalore, Thiruvarur, Pudukkottai and other areas. The farmers never get crop loans. There is no improvement in the irrigation system. They are not getting any proper relief during flood which has affected them consecutively. There are cyclones and sometimes drought also. These things should be taken into account before they decide anything. Of course, the last date for the bidding of the

hydrocarbon blocks, which you have already announced on 15.01.2020, is due on 16.03.2020. So, some better sense should prevail on my friends and in case of going ahead with the bidding of the blocks which are intended for petroleum exploration in the delta area of Cauvery. I can only remind you of Julius Caesar: “Oh my friends, beware the ides of March”. I can just quote the Shakespeare and that is all.

Now, I am coming to CAA, NPR, NRC and other things. There is a Tirukkural:

> “Pirupokkum Ellaa Uyirkkum Sirappovva
> Seydhozhil Vetrumai Yaan”

It means, by birth, all are equal.

There is another Tamil verse which the Prime Minister used to tell in all his conferences: "Yaadhum Oore Yaavarum Kelir". It means, all are our kith and kin and all are our places. The same thing is written in the entrance of the Parliament in Sanskrit.

Some of my friends have shown it which was engraved on the roof of the Parliament entrance where our hon. Prime Minister bowed down his head and touched the steps on 22nd May, 2014 if I remember correctly. Am I correct Mr. Ravi?

In Sanskrit, *Vasudhaiva Kutumbakam* is there. I do not know what for my friend hon. Prime Minister has bowed down and touched with his forehead on the steps of Parliament. I will come to that particular issue later, not now, because if I say anything, you will disturb me.

My dear sir, during Dr. Kalaignar Karunanidhi's period from 2006 to 2011, Periyar Samathuvapuram has been established in 145 places in Tamil Nadu as equality villages, 100 houses will be there. All the people irrespective of caste, creed, religion, place of birth or whatever it may be, the people belonging to Tamil Nadu will live together. He wanted every person to have a harmonious relationship with every other person. My leader was a high-thinking person. He used to think tall whereas my friends here are very tiny and pygmy in thinking things. He has created 145 places. Now, we expect the same thing from you.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, kindly check if pygmy is a unparliamentary word. I have great regard for him. Pygmy is unparliamentary word. It should not go on record.

HON. CHAIRPERSON: Okay, I will check.

SHRI T. R. BAALU : Pygmy is about smaller things. Nothing else. It is not unparliamentary. Nothing wrong in saying that.

What is the compulsion for bringing CAA? I do not think there is any iota of compulsion to bring CAA. You have got established law. You have got Census Act, 1948. You have got Citizenship Act, 1955. Under 1955 Act, you have got 2003 Rules. Is it not there? Keeping all these things, you brought one more enactment during the last year that is in 2019. What is purpose of bringing that CAA? You want to discriminate people. That is what my charges are.

Anyhow, whatever it is, according to the Universal Declaration Article 2 and Article15, it is for you to give asylum to each and every body world over whoever comes, whichever caste he belongs, whichever creed he belongs, whichever religion he belongs., you have to accommodate. There is no other way for you. You have signed it. You are one of the signatories of the Universal Declaration. Where is the chance for you to go away from it? If anybody comes here to get asylum, it is for you to provide that with a great dignity and honour. But here, what have you done? You are not giving relief to Christians of Bhutan, Rohingyas of Myanmar, Gurung and Sherpas of Nepal, Hindu Tamils and Christians, Muslims of Sri Lanka, Buddhists of Tibet. These people cannot enter. But at the same time, all other people can enter. That is not the problem for us. You have to accommodate everybody.

Under 1955 Act, you have already created NPR. NPR is there.

In the Census, the data collected are kept confidential whereas in the NPR, whatever you have collected is wide open to the world. You are extending everything not only to the nation but to the world. Is it not necessary for me to protect my personal data which is being explicitly made known to everybody? Who are you to expose my personal data to everybody through the people whom I do not like? You are just publicising everything. It is done under the NPR. That is why, we hate the NPR. Not only that, up to 2010 and even now, even today, you have got no right to release it. You have got no rule at all in 2003 and beyond 2003 to extend the parameters.

Already 12 parameters exist in NPR even today. But for extending another eight parameters to make it 20, till today you have not published or advertised any amendment beyond the 2003 parameters. But you have to amend the rule. You have not amended the rule so far. So, you have got no right. But sample survey has been done by you by extending the parameters like asking for parents' birthplace, Aadhaar, mobile number, passport number, voter ID, mother tongue, driving licence, etc. Do you have any rules for this, Mr. Ravi Shankar Prasad? I do not think you have got any amended rules so far. So, it is all *ultra vires.* Mr. Chairman, Sir, you are a lawyer. Is it not *ultra vires*?

What is Universal Declaration? Mr. Ravi Shankar Prasad is very clever. He can answer anything. He is a senior lawyer. He can make a mole into a mountain

and a mountain into a mole. But I can read article 2 of the Universal Declaration of Human Rights.

> "Everyone is entitled to all the rights and freedom set forth in this Declaration without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, etc."

What is article 15 of the Universal Declaration?

> "Everyone has a right to nationality. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality."

Hence, according to the Universal Declaration of Human Rights and according to article 14 of our own Constitution, you are bound to extend it. Whichever nationality the particular person wants, you have to extend it.

Mr. Ravi Shankar Prasad and to my friend, I can only say that the BJP has 303 seats, and along with your friends, you have 353 seats. I can only say your success has been attained with 37.36 per cent of votes. Along with your friends, you have got 45 per cent votes. The Opposition, which was having no clue at all, has failed but it got 55 per cent. We, who have got 55 per cent, are sitting in the Opposition but you, who have got only 45 per cent, are sitting in the ruling side. It is a miracle of democracy. I could say that this is a miracle of democracy and there is nothing else I could say. Your success lies with the weakness of the

Opposition. I can only find fault with the Opposition. They were not united. Otherwise, you would not sit there.

16.00 hrs

That is why, I can only tell my friends of ruling Party 'Kindly go slow; do not be in a hurry.' I can tell this to you as a friend of all of you. I am very close to you. I was very close to you. I have been brought up not only by my leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, but I have also been guided by great Vajpayeeji - I have worked under him - with great love and affection.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: We deeply appreciate that comment.

SHRI T. R. BAALU : I told you that I would tell you the reason later. The reason for the Prime Minister bowing on the steps of the Parliament House, I believe, is that he was repenting for the sins committed by his own friends, by the BJP at various times in the past and also for the future process of CAA, NPR and NRC.

16.01 hrs (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

This is what I wanted to mention at that time. I am mentioning it now. So, with this, I can only tell my friends to go slow and also try to accommodate everybody in the world. We are all kith and kin. As Kanian Poongundranaar said, "*Yaadhum Oore Yaavarum Kelir"*. This means that all are our places and all are our friends – kith and kin.

Thank you very much.

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Madam, I rise today to oppose the motion and in support of the amendments moved by our Party.

More importantly, I rise against the betrayal of the body polity that this Government has been responsible for. I sincerely hope that the Treasury Benches will have the patience to hear me out. Even if they lack that instinct for self-preservation, that will actually make them listen. So, if they have got express instructions today or the express intent today to shout me down, I say to them to do so at their own peril because people of India today are on the streets and their voices are beyond their power to silence.

As a Member of the Opposition, I have the unquestionable right to tell you that as a Government, you lack humility. You secured approximately 37 per cent of the 67 per cent of votes cast out of a pool of 900 million voters. That is only about 230 million people. You got only 23 crore votes out of 1.3 billion citizens. So, despite the fact that you might have had the largest majority in several decades, do not arrogate to yourself an extra-constitutional authority over every citizen and do not go beyond the tenets of democracy.

Today, I rise to speak of betrayal. This betrayal is not just to myself. I was not part of the 31 per cent who voted for you in 2014 and I was not part of the 37 per cent who voted for you in 2019. This is not about people like me. I was sceptical about you, your ideology, and your rhetoric right from the word go. In a

sense, you owe me little, but the truth is that you have betrayed the very citizens who did vote for you.

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): How can a Minister read a newspaper here?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I am not reading it.

SUSHRI MAHUA MOITRA: The truth is that you have betrayed the very citizens who voted for you. You did not come to power on the vote of the Hindu-right alone; you came to power because a very large section of ordinary people, the aspirational middle of the road voters cast aside whatever reservations they might have had about your past and believed you when you said *sabka sath, sabka vikas* which they took to mean development for a united India. They believed in your alternative narrative of merit, of transparency, of a world without nepotism, and the entitlement of the *bhavalok*. It is this section of people, these middle of the road voters that you owe your historic mandate to. These were not the hardcore believers the *Sanghis* as it were, but they still believed you and they still voted for you. But you have betrayed the young voter who was eagerly looking forward to his first job. You betrayed the small businessmen by your foolish decision of demonetisation, killing his market, and ruining his business for no fathomable reason.

You betrayed thousands of tribal people in Gujarat whose land you took to build a statue and to whom now you have given jobs as toilet cleaners. You have betrayed them by questioning the citizenship of the very citizens who voted you to power. It is your middle-of-the-road voters who today cannot recognize the India that they are living in. They cannot recognise the images they see on their television screens. They cannot identify the hate-filled venomous invective that they see members of the Ruling Party spew out publicly.

A week ago a meeting of holocaust survivors was convened in Poland to commemorate the 75th liberation of the dreaded Auschwitz Camp. Only 200 people are still surviving. The one resounding message, perhaps the last in their life time, that they gave to the rest of the world was this: “Auschwitz did not fall from the skies. Auschwitz happened because people were indifferent to the plight of others who professed a different faith from them.” All holocaust memorials today serve as one reminder, not that it happened but it could happen again. We need to remember that it happened not only because of those who pressed the switch of the gas chamber but also of those who sat back and watched when their neighbours were first marked out systematically and then dragged from their homes. The NPR, the NRC and the CAA are all tools in this Machiavellian design to first mark out, then disenfranchise, and finally annihilate. This is your biggest betrayal of those who voted for you. Nobody wanted to be part of this ‘US’ versus ‘THEM’ debate.

My friends who voted for you in 2014 are horrified at what is happening in their name under your watch. As every election comes and goes, your members demonise dissent, exhorting your supporters to shoot people who stand up to you.

Today, you have let a person who was banned by the Election Commission from speaking for 36 hours to come to the floor of the House and present the manifesto of the Ruling Party for the Delhi Assembly elections. You have the executive authority to do so. But your Government remember depends on a higher authority, moral authority. You speak of Ram and Yudhishtar and you speak of Dharmputras. You speak of dharma. Have you forgotten that? You build false narratives where our *dadis* become your terrorists, and our children become desh drohis. But today the citizens are finally standing up to these bullies and they echo Ram Prasad Bismil's words. These are not my words.

देखना है ज़ोर कितना बाज़ु-ए-कातिल में है,
सर जो उठा एक बार, वह झुकते नहीं ललकार से,
हाथ जो उठा, वह कटते नहीं तलवार से ।

You have betrayed your mandate. You have broken your promise to put the economy first and to put development first. My words will be incomplete if I do not highlight the abysmal state of the economy, of the arcane jugglery that this Government practises, where the Finance Minister is fearful of putting out the real GDP growth target. The Finance Minister, on the floor of the House, says that

nominal GDP target is 10 per cent. In the month of December, the Consumer Price Index was at 6.70 per cent. Does that mean that the real GDP growth rate today is 3.30 per cent? That is what the Government is saying.

Remember, when there is no integrity in statistics, little else remains. Between 2011-12 and 2017-18, per capita consumption, according to the National Sample Survey, dropped in real terms. This is unprecedented in modern times. Moreover, all of that drop, according to the same data, happened after 2014. This data was first made public, but then as the bad news started to go around the Government suppressed the 2017-18 NSS Survey, complaining that it was unreliable. There was no credible explanation given though this very data had been used to tom-tom poverty reduction in the past.

There is perhaps even worse news. The GDP numbers are disputed partly because of disagreements about the right measure of inflation. A bigger problem may be that our way to compute the GDP of the informal sector is crude and backward looking. So, we overestimate the GDP when the informal sector is shrinking.

You have a tendency to rubbish every economic expert who does not agree with you. But your very own Chief Economic Advisor, whom you selected, has gone now on record to say that all the more reliable measures of macro statistics, such as growth in exports, import and credit, investment, vehicle sales are mostly

negative. This is more similar to a recession year like 1991 than the moderate growth year that you say we are having.

Then there are unemployment numbers, high and growing which the Government denies. If we are really in a crisis the Government is doing this country a huge disservice by trying to suppress data and denying the correctness of the data that exists.

You have betrayed the ideals of transparency and a better governance that you claim you were wedded to and your betrayal has gone much further than that. You have betrayed the history of this Republic; you have denounced the very ideals on which we fought and gained our freedom which is so peaceful and non-violent descent.

You have tried time and again to rewrite the past and create a grotesque singular version of India with false history. But as Agha Shahid Ali said, "my memory comes in the way of your history."

Three things - a majoritarian Government, a subservient Media and a *…* * Judiciary – anyone alone cannot destroy a nation, as we know it. But a combination of all three can prove deadly….(*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए। मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

* Not recorded.

SUSHRI MAHUA MOITRA : We are not …* today because we point this out. We are *paheredars*, guardians of our soil and our Constitution.

'जिन्हें नाज है हिंद पर, वे कहाँ हैं?

कहाँ हैं - यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं।' …(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदया, माननीय सदस्या हम लोगों की आलोचना करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने कमेंट में '…** जूडिशिएरी' शब्द का प्रयोग किया है। जूडिशिएरी के बारे में यह शब्द बहस में उचित नहीं है, इसे निकाला जाए।

माननीय सभापति : यह शब्द उचित नहीं है, उसे निकाला जाएगा। इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, … ** शब्द भी अनपार्लियामेन्टरी है।

श्री प्रहलाद जोशी: महोदया, … ** शब्द को भी कार्यवाही से निकाला जाए।

माननीय सभापति : जितने भी अनपार्लियामेन्टरी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उन सबको कार्यवाही से निकाल दीजिएगा।

---

* Not recorded.

** Expunged as ordered by the Chair.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Madam, for letting me talk on the Motion of Thanks to the President's Address. To start with, I would like to reiterate that our Party is opposed to NRC and even NPR. Our Government has issued a G.O. where they have removed objections by the minority community and that G.O. is going to be enforced in our State. So, we request the Government to reconsider the questionnaire in NPR also so that there is no insecurity in the minority community.

We had supported CAA. It was perceived to be meant for people of only three countries – Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. But I would like to bring to the notice of the House and the Government that every day, we see people in the streets even in my constituency, in my State. So, the Government has to address this. The Government has to see that there is no insecurity in the minority community. I hope the Government acts on this.

Madam, coming to our issues, Andhra Pradesh is a new State. It is a new baby. We have been requesting for the past six years from when the AP Reorganisation Act had been passed. We have been requesting that we need support. We were born with unviable finances. So, we have been asking for special category status. It was promised on this very floor of the House. We have been asking for implementing all the points in the AP Reorganisation Act. We request the Government to act on this.

Earlier we heard that special category status could not be given because of 14th Finance Commission. We totally oppose this. The 15th Finance Commission, in its report, clearly stated that there is no link between the 15th Finance Commission and special category status and it is only an executive decision. So, we demand special category status. We have lost count of how many times we have demanded special category status and in how many ways, we have demanded it. So, we request the Government to act on this.

We also request the Government to act on Revenue Deficit Grant. It was promised that whatever revenue deficit for the new State is there in the first year, it will be reimbursed. The C&AG has pegged revenue deficit of Rs.22,900 crore. So far, it has not been fulfilled.

We also request the Government to release the Backward District Development Fund which was promised to us. It has been pending for more than two years. There are four backward districts of Rayalaseema and three in Uttarananda. We are demanding that funds be released at an earlier date.

Madam, the most important project for our State is Polavaram.

The work on Polavaram project is going on at a brisk pace, and it is going to be completed in one year's time. We request the Central Government to release funds in time, and release it in every 15 days because for the past six months Rs. 5,000 crore has been pending to our State for the Polavaram project,

but till today the funds have not been released. Only a part amount has been released, and our Government -- in spite of all the financial stress -- has ended up paying Rs. 500 crore only as interest for it. So, we would request the Government to take note of this issue, and I would also request the hon. Prime Minister to take note of this issue. We have seen earlier Prime Ministers like Pandit Jawaharlal Nehru who did the Srisailam Dam. We want hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, to take credit for doing the Polavaram project in time and helping the State of Andhra Pradesh.

In the AP Reorganisation Act Kadapa Steel Plant was supposed to get support from the Central Government. Kadapa is a backward area, and we do not have enough jobs there. It is a dry area. So, we would request the Government to keep its word and help in setting up the Kadapa Steel Plant. Further, a Ramayapatnam Port was promised. M/s. RITES has come out with a Techno-Economic Feasibility Report where it is mentioned that it is viable. We would request the Government to come forward for it. One area or State cannot be excluded, and without supporting a State we cannot dream or aspire to be a $ 5 trillion economy.

In the recent All-Party Meeting, my friends from Telugu Desam have raised two issues, namely, about scrapping of projects and the issue of Capital. I would like to clear the air about these two issues. These are State issues, but since they

have raised it 'n' number of times and they have been talking about these issues, I would like the House also to understand as to what is happening in Andhra Pradesh.

Our Government is under severe financial stress. The new Government, which has been formed under the leadership of Shri Y. S. Jaganmohan Reddy was inherited with Rs. 40,000 crore pending bills plus Rs. 20,000 crore additional bills that were pending. But in spite of the huge financial stress, our Government decided that it does not want to scrap any project, but only wanted to re-negotiate and re-tender the projects.

I would like to recall hon. Prime Minister's words when he came to Andhra Pradesh. He commented on our former Chief Minister when he was in Andhra Pradesh stating that : "They have turned Polavaram project into an ATM for corruption, and there was corruption in the Capital". This is proved by the fact that there was reverse-tendering in the Rs. 5,000 crore project for Polavaram and Rs. 800 crore was saved in one single project. Just six months before elections Rs. 70,000 crore worth of projects were tendered by the former CM, and all the tenders were given at five per cent excess rates. This clearly shows that it is a cartel, and now after re-tendering we are saving close to 10-15 per cent in each and every tender.

I would like to give one example. In Veligonda, there was a tunnel work that happened. The same contractor had got the work at five per cent excess, bid for 15 per cent less after we re-tendered after a month. So, where did this money go? Why has it not been done before? This is our question.

As regards affordable housing, in TIDCO, the Central Government sponsors one portion, the State Government provides one portion, and the third portion is borne by the beneficiaries. It was tendered at Rs. 2,200. Our State Government has retendered for seven lakh units, and today we are saving Rs. 400 per SFT. This means that all the seven lakh households are getting a saving of Rs. 1 lakh per household. This is a substantial amount for poor people. This is what our CM is trying to do. He is taking forward everything in a transparent manner. In fact, it is the first State in India to put a Judicial Commission to vet all tenders. Each and every tender is transparent, and any tender above Rs. 1 crore will go for a reverse-auction, which will give substantial savings for the Government.

I would also like to bring to the notice of the House that in our Capital area there were tenders for temporary buildings. If you go anywhere in India, the construction cost is Rs. 1,500 per SFT, but if you see in our Capital Amravati, temporary buildings with land free and sand free were given at Rs. 11,000 per SFT.

So, Madam, we have to question such scams because it is the public money and we are here to protect the interest of the public.

Secondly, there was one more thing that the PPAs have been scrapped. I would like to make it very clear on the floor of the House that no PPAs were scrapped. Only 41 PPAs which the former Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu, concluded just before the elections at Rs. 4.83 paise were done. Madam, at the same corresponding time, in the neighbouring States, the unit of power was only for Rs. 3 and below that also. Where is Rs. 4.83 and where is Rs. 3 and below? This is what we have questioned. Now, it is in the purview of judiciary. Whatever decision comes, we are going to respect that. Even now, we are taking power from all the PPAs but we are awaiting the decision of the court and we will adhere to that. No PPAs have been scrapped.

In addition, regarding renewable energy, I would like to bring it to the notice of the House that I am proud to say that, under our new Chief Minister, Government of Singapore and Abu Dhabi Investment Authority have come forward to make the world's biggest integrated renewable energy project in Andhra Pradesh. It is worth Rs. 25,000 crore and the Government of Singapore is happy to invest in that and our Chief Minister is going to inaugurate that project very soon. Such is the development our CM is focusing on. Basically, I know that

this is a State subject but since there were allegations made in the All Party Meeting, we have to make things clear here.

Regarding our capital, I would like to bring it to your notice that Amravati was declared the capital but before that, the former Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu said that, close to Vjayawada, there is a place called Tiruvuru. He officially said that the capital is going to come up at Tiruvuru. Then in three months' time, he made his people buy land in a place called Amravati between Guntur and Vijayawada. They bought so much land and now the preliminary investigation is showing that more than 4,000 acres of land has been bought by Telugu Desam Party leaders in that area. Madam, as a CM, if he is fooling people saying that the capital is coming at Tiruvuru, then buying land and making a big scam is a breach of oath. Then he says that Tiruvuru is not the capital, the capital is going to be Amravati. This is a big scam. Now, a preliminary investigation shows that 4,000 plus acres of land has been identified to be with Telugu Desam Party people.

The whole House should take cognisance of the fact that 780 people below poverty line have spent crores of rupees to buy the land. How can a person who is below poverty line buy land worth crores of rupees? They do not even come under income tax assessment. Today, I read in the news that ED has come into place and CID has reported to ED that 780 people have been identified with false

certificates and money was swindled from the people. They have bought land there. Madam, we also demand a CBI inquiry from the Government so that these scams be brought out.

Earlier, before the elections, our former Chief Minister went throughout the country saying that we will finish off Modi ji and finish off BJP. We do not mind which party he supports. Earlier, he said that they would make Rahul Gandhi ji the Prime Minister but, today, I will tell you that there was a request in the Speaker's Office that they do not even want to sit with the Congress Party. They are sitting behind us. This is the thing. I request the House to take note of the Telugu Desam Party. I do not mind the Telugu Desam Party leaders shouting behind me because, Madam, they have been assigned with a task to save Shri Chandrababu Naidu from his scams. This is the reason they will be shouting. They will be propagating all lies. Whatever facts are there, we are ready to bring them out. We request the blessings from the House for a young Chief Minister who is performing so well and who is weeding out corruption. I wish everybody's blessing is there for our CM. Thank you.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मैं अपने, और अपनी पार्टी के विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विचार रखे और इस देश को बलशाली भारत बनाने का सपना दिखाया, निर्धार किया। मेरे हाथ में पिछले वर्ष का भी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है। वही योजना, वही स्कीमें, वही घोषणा, लेकिन उसके अमल में कुछ फर्क नहीं पड़ा।...(व्यवधान) मैं बताता हूं, जरा सुनिए।...(व्यवधान)

खासकर पहले पेज में मुद्रा योजना का उन्होंने उल्लेख किया, उज्ज्वला गैस का उल्लेख किया और प्रधान मंत्री ऐसी कई अलग-अलग योजनाओं का उल्लेख किया। अपने देश में सेंसस के हिसाब से साढ़े 12 करोड़ बिलो पॉवर्टी लेवल के घर हैं। स्वाभाविक है कि महामहिम प्रधान मंत्री के सपने से जो उज्ज्वला गैस मिली, वह साढ़े 12 करोड़ लोगों के घरों तक जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रपति जी के भाषण के अनुसार सिर्फ 8 करोड़ लोगों के घरों तक गई। आज उज्ज्वला गैस योजना पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, क्योंकि 3,200 रुपये में उज्ज्वला गैस देते थे, 1,600 और 1,600 रुपये। 1,600 रुपये उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही थी, वह देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। हमारे अकेले महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले के 20 हजार लोग आज भी वेटिंग में हैं, उनको उज्ज्वला गैस नहीं मिल रही है। यही स्थिति पूरे देश की है।...(व्यवधान) सिर्फ घोषणा करने से भारत देश सम्पन्न नहीं होगा। सही तरीके से उसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अगर लोगों के हित में काम करना हो, तो घोषणा कम और अमल ज्यादा करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से पिछले तीन साल से वह नहीं हो रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की जो सच्चाई है, वह मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं।

माननीय राष्ट्रपति जी ने 370 और 35(ए) का उल्लेख किया। सभापति महोदया, आज भी मैं वही दु:ख से कहना चाहता हूं, उस समय हमने 370 को सपोर्ट किया था, 35(ए) का भी समर्थन किया था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 370 जाने के बाद या 35(ए) लागू होने के बाद उस जगह कश्मीर में कितने भारतीय जाकर अपना व्यवसाय चालू करने में सफल हो चुके हैं।...(व्यवधान) यह जानने का हमारा हक है ।...(व्यवधान) बताना आपका कर्तव्य है ।...(व्यवधान) लेकिन कुछ नहीं हुआ ।...(व्यवधान) कश्मीर में इतना हुआ, उतना हुआ, यह होना ही चाहिए। अखंड भारत हमारे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे जी का सपना है, सरकार वल्लभभाई पटेल जी का सपना है, जिसे पूरा करने का वादा उन्होंने किया, इसके लिए शिवसेना ने समर्थन किया। लेकिन असलियत यह है कि 370 इम्प्लीमेंट करके वहां कश्मीरियों की भलाई नहीं होगी, किसी पार्टी की भलाई हो सकती है। हम चाहते हैं कि कश्मीर अखंड हिंदुस्तान का भाग हो, उनका भी विकास होना चाहिए। आज वह करने की जरूरत है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने देश में 400 से ज्यादा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का एक वादा यहां किया है। यह एक अच्छी बात है। आज देश के करोड़ों आदिवासी लोग जिस तरीके से अपने वहां रह रहे हैं, उनको आरोग्य की समस्या है, खाने की समस्या है, उनके पास उज्ज्वला गैस का कनेक्शन अभी तक गया नहीं है। ऐसे 400 जो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल हैं, कौन-कौन से जिले में उन्हें इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है? हम यह भी जानना चाहते हैं।

सभापति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बाहर से जो अपने देश में जो शरणार्थी आए हैं, उनको संरक्षण देने का यहां वादा किया है।

माननीय प्रधान मंत्री जी पिछले लोक सभा के शीतकालीन सत्र में सीएए लाए थे और शिवसेना ने देश हित में इसका समर्थन किया था। लेकिन आज मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि जब हमने सवाल उठाया था कि सीएए के माध्यम से इस देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कितने लोग आए हैं, उनका आंकड़ा बताइए? देश के किस राज्य में उनका पुनर्वास किया, उसका आंकड़ा बताइए? तो वे बता नहीं सके, यह बताने की जिम्मेदारी थी। भारत में शरणार्थी आए हैं तो बताना चाहिए, एक करोड़ शरणार्थी आए हैं, बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, लेकिन आखिरी तक उत्तर नहीं दिया, उत्तर देने का कष्ट तो करें। हमारा सवाल गलत है तो बोलिए, हम जानना चाहते हैं कि अपने देश में कितने शरणार्थियों को आधार दिया, लेकिन आपके पास उत्तर नहीं है इसलिए बता नहीं सकते। अभी एनआरसी लाना चाहते हैं, एनपीआर लाना चाहते हैं।

मैं पूछता हूं कि क्या इस देश की सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं? आज देश के सामने एनआरसी समस्या नहीं है? आज देश के सामने एनपीआर समस्या नहीं है बल्कि देश के सामने बेरोजगारी समस्या है। आज देश के सामने किसानों को बीमा की राशि देने और बढ़ती हुई महंगाई समस्या है। आज देश के सामने महिला और बालकों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसे कैसे रोका जाए, ये समस्याएं हैं।

पिछले एक वर्ष में इस देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उद्योग नहीं आ रहा है। गुजरात और राजस्थान के कई उद्योगपति देश छोड़ कर प्रदेश में गए। आज पांच सात प्रमुख क्षेत्र से 3.64 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, वस्त्र उद्योग में 3.5 करोड़, बीएसएनएल और एमटीएनएल में 92 हजार, ज्वेलरी में पांच लाख जो सूरत में है, कंस्ट्रक्शन में 27 लाख, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो सबसे बढ़िया सेक्टर है, आज दो करोड़ तीस लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। एविएशन सेक्टर में बीस हजार लोग बेरोजगार हो चुके हैं, एयरलाइन्स कंपनी बंद हो चुकी है, एयर इंडिया का भी क्या भरोसा

मुझे मालूम नहीं? लेकिन बैंकिंग में 3.15 लाख यानी सवा तीन करोड़ लोग बैकिंग सेक्टर में बेरोजगार हुए हैं। आज इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं जानना चाहता हूं कि बेरोजगारी कम करने और नए निर्माण के लिए इस देश के प्रधान मंत्री जी के सामने क्या सपना है? उसे हम जानना चाहते हैं, लेकिन इनके पास उत्तर नहीं है। ये एनआरसी के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं, जो समस्या देश के सामने नहीं है, पिछले 71 साल में आजाद हिन्दुस्तानियों में सारे देशवासी एक साथ रह रहे हैं, उनके सामने एनआरसी लाकर क्या करना चाहते हैं?

महोदया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में एनआरसी लाने की कोशिश करें तो 35 करोड़ हिन्दुस्तानी को डिटेन्शन कैम्प में रखना पड़ेगा, बेरोजगारी से लोगों का ध्यान दूर करके, सारी समस्याओं की अनदेखी करके एनआरसी के माध्यम से देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शिवसेना प्रमुख माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी ने बताया कि एनआरसी देश की समस्या नहीं है। जो देश की समस्या है, उसकी तरफ देखो और काम करो।

अगर जबरदस्ती एनआरसी लाने की कोशिश करेंगे तो शिव सेना उसका विरोध करेगी, लोग इसका विरोध करेंगे। ...(व्यवधान) जो सच्चाई है, उसे सुनो।...(व्यवधान) आपको सच्चाई सुननी पड़ेगी। ...(व्यवधान)

सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि किसानों का उत्पादन दुगुना करना चाहिए। सही बात है, दुगुना तो होना ही चाहिए। ...(व्यवधान) "प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना" एक महत्वपूर्ण योजना है। हमने इसकी सराहना की थी, लेकिन आंकड़ा कितना झूठा है, मैं बताता हूं। भारत की सेंसेस के माध्यम से साढ़े बारह करोड़ अल्प भू धारक हैं और दो करोड़ बढ़ने वाले हैं, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना का फायदा आठ करोड़ लोगों को हुआ है। मेरे पास रिकॉर्ड है, अक्टूबर 2019 तक सिर्फ तीन करोड़ लोगों को "प्रधान

मंत्री किसान सम्मान योजना" का फायदा मिला है।...(व्यवधान) यह पार्लियामेंटरी कमेटी का एविडेंस है, आप जब चाहे तो देख सकते हैं।...(व्यवधान) पहले हफ्ते में 7 करोड़ 2 लाख लोगों को फायदा मिला, 2000 रुपए मिले। दूसरे हफ्ते में सिर्फ 5 करोड़ 92 लाख लोगों को और तीसरे हफ्ते में 3 करोड़ 33 लाख लोगों को फायदा मिला।...(व्यवधान) क्या जादुगरी हो गई? क्या गरीबी कम हो गई? क्या झटपट इतना जादू घूमा और सारे भारत के गरीब भाग गए?...(व्यवधान)

सभापति जी, योजना अच्छी है, लेकिन सबके लिए होना चाहिए। तिजौरी में पैसे कम पड़े तो योजना लाभार्थियों को कांटछांट करके आंकड़ा कम किया गया ऐसा भविष्य में नहीं करना चाहिए। यह नए भारत का ऐलान नहीं हो सकता है, लेकिन लोगों को गुमराह करने का ऐलान हो सकता है। ...(व्यवधान)

सभापति जी, मैं समझ सकता हूं, हमने पिछली बार महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की सराहना की थी। अब यह भाषा इनको पसंद नहीं आ रही है।...(व्यवधान) दोस्तों को दुश्मन बनाने का काम जो करते हैं, उनको सच्चाई नहीं सुननी है।...(व्यवधान)

महामहिम राष्ट्रपति जी ने भारत के सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी का उल्लेख किया।...(व्यवधान) मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं। बाल गंगाधर तिलक जी ने उस वक्त किसानों के बारे में कहा था और अब आप बाल गंगाधर तिलक जी के नाम से कृषि के क्षेत्र में नई योजनाएं लाना चाहते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो कहा था, मैं मराठी में बताना चाहता हूं।...(व्यवधान) जो वीर सावरकर को कोई जानता है तो शिव सेना ही जानती है, आप नहीं जान सकते।...(व्यवधान) अगर हिम्मत है तो वीर सावरकर जी को भारत रत्न का पुरस्कार दे दो।...(व्यवधान) हिंदुत्व के बारे में आप हमें नहीं सिखा सकते।...(व्यवधान) हिंदुत्व का नारा – "गर्व से कहो हम हिन्दू हैं", यह बात हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी ने कही

थी। ...(व्यवधान) हम भी आज उसी तरह से कह रहे हैं। हिंदुत्व के बारे में शिव सेना की तरफ टेढ़ी नजर से देखने का कष्ट मत कीजिए।...(व्यवधान)

बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठी में कहा था किसानों की बदहाली मतलब देश की बदहाली। बाल गंगाधर जी के नाम से तीन योजनाएं शुरू की हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने उस वक्त भारत सरकार को कहा था, अंग्रेजों को कहा था कि किसानों के लिए आपका रवैया कैसा होना चाहिए। मैं आपको मराठी में पढ़कर बताता हूं।...(व्यवधान)

अभी मेरे पास 25 मिनट हैं, मैं अपनी पार्टी से अकेला बोलने वाला हूं। 12 घंटे का डिकसशन है, साहब ने बताया है।...(व्यवधान)

तिलक जी ने कहा था कि "किसानों की बदहाली से देश भी बदहाल हो जाएगा", राष्ट्र की अवस्था निकृष्ट होगी।

तिलक जी ने कहा था कि अगर किसानों की हालत खराब होती है तो पूरे देश की हालत खराब हो सकती है। इसी बहाने मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि चाहे उनका इनकम दोगुना करने की व्यवस्था हो, आप ढाई करोड़ लोगों को रेसिडेन्सियल कनेक्शन दे चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देश के करोड़ों लोगों को कृषि के लिए जो एग्रीकल्चर कनेक्शन मिलना चाहिए, वह आज नहीं मिल रहा है। सारे कनेक्शन सोलर से नहीं मिलने सकते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 175 गीगा वाट बिजली निर्माण करने की घोषणा की थी। 175 गीगा वाट तो छोड़िए हम लोग 5000 मेगावाट के लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच सके हैं। यह असफलता क्यों मिल रही है? उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति जी ने जे.ए.एम- जन-धन, आधार और मोबाइल से डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के बारे में बताया है, वह तो शुरू से है। लेकिन, मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे

बताएं कि आज देश में बीएसएनएल की क्या हालत है? कनेक्टिविटी नहीं है। आज भी देश के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों लोग बैंक के बाहर जाकर बैठकर कह रहे हैं कि कुछ दे दो। मंत्री महोदय, मेरी प्रार्थना है, यदि आप सुनेंगे तो अच्छा होगा। आज देश में बीएसएनएल पूरी तरह से बंद हो चुका है। ...(व्यवधान) वे यूनियन का काम करते थे। आप बताइए कि क्या आप सारी गवर्नमेंट स्कीमें डीबीटी के माध्यम से अमल करना चाहते हैं? ...(व्यवधान) इसके माध्यम से 92000 लोगों ने वीआरएस ले लिया। आप अब भी तो बीएसएनएल को संजीवनी दे दीजिए।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : मैं ... *

माननीय सभापति: यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्री विनायक भाउराव राऊत: यह असलियत है। यह आप भी जानती हैं, आप भी ग्रामीण इलाके से आती हैं। क्या इस देश में बीएसएनएल का नाम लेने के लिए कुछ है?

माननीय सभापति: अरविंद सावंत जी का भाषण रेकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्री अरविंद सावंत : ... *

माननीय सभापति: आपने बिना परमिशन बोला है, मुझसे परमिशन नहीं ली है। परमिशन लेकर नहीं बोलेंगे तो रेकॉर्ड में क्यों रखेंगे?

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री विनायक भाउराव राऊत: मैं विनती करना चाहता हूं, अगर आप इस देश के प्रधान मंत्री जी की सारी योजनाएं किसानों के डायरेक्ट एकाउंट में भेजना चाहते हैं तो क्या आपकी बीएसएनएल की

* Not recorded.

कनेक्टिविटी देने की जिम्मेदारी नहीं है? बाकी के डिपार्टमेंट भी बीएसएनएल के माध्यम से हों, लेकिन आज बीएसएनएल है कहां? बीएसएनएल को संजीवनी देने की आवश्यकता है। अगर नहीं देते हैं तो इसे बंद कर दीजिए और सारा 'जिओ' को दे दीजिए।

माननीय सभापति: वहां की सरकार अपना काम करे, यहां सरकार अपना काम कर रही है। ऊपर बताने का मतलब है कि आपके ऊपर बैठे हुए हैं, जो सरकार है, वह करे।

श्री विनायक भाउराव राऊत: इस सभा गृह में जिओ का कनेक्शन आता है, लेकिन बीएसएनएल का कनेक्शन नहीं आता है। इसका क्या मतलब है? सब कुछ जिओ को, कर लो दुनिया मुट्ठी में, आज वही हालत है।

आज जीएसटी के बारे में सुबह श्री नामा नागेश्वर राव साहब बताना चाहते थे। हम लोगों ने जीएसटी का समर्थन किया है, लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं है। इसलिए, महाराष्ट्र राज्य को आज तक 15000 करोड़ रुपये नहीं दिया है। तेलंगाना में भाजपा की सरकार नहीं है, आंध्र प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए उन्हें जीएसटी का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि पहले पांच वर्ष में जीएसटी के रेवेन्यु वसूल करने में जो भी कटौती होगी, वह राज्य सरकार को देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। लेकिन, दुर्भाग्य से आज भी जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, क्या आप उनके ऊपर अन्याय करेंगे?

क्या वे देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वहां आपका एकाधिकार है? एकाधिकार वहां भी है, लेकिन हमने नहीं किया। यह हमारा हक है कि जो भी राज्य का हिस्सा हो, वह हमें मिलना ही चाहिए। चाहे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना हो। सभापति महोदया, पीएमजीएसवाई एक महत्वपूर्ण व अच्छी योजना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेय जी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। पिछले बजट में पीएमजीएसवाई योजना के लिए फेज़ थ्री में लगभग चालीस हजार करोड़ रुपये की घोषणा हुई

थी। मैं आज आपसे जानना चाहता हूं कि क्या पीएमजीएसवाई योजना का फेज़ थ्री चालू हुआ? अभी तक नहीं हुआ है। ...(व्यवधान) आप देखिए मैं एक बार फिर बोलता हूं। इसका मतलब यह हो सकता है कि जिस राज्य में भाजपा की सरकार अभी तक नहीं है, वहां पर पीएमजीएसवाई योजना नहीं गई है। यह इंसाफ नहीं है बल्कि अन्याय है। ...(व्यवधान) सभापति महोदया, मुझे दो मिनट दीजिए। ...(व्यवधान) सभापति महोदया, मुझे एक मिनट तो दीजिए। मैंने यह मांग मेरे देश के लोगों के लिए की है। अगर राज्य सरकार को फेज़ थ्री का अमाउंट दिया है तो माननीय प्रधान मंत्री जी हमें अपने रिप्लाई में बता दें कि उन्होंने महाराष्ट्र के लिए कितना दिया, तेलंगाना के लिए कितना दिया और आंध्र प्रदेश के लिए कितना दिया। अगर बता देंगे तो हम खुश होकर उनका आभार मानेंगे। सभापति महोदया, मैं अपने भाषण को समाप्त करते हुए एक ही बात कहूंगा कि प्रधान मंत्री आवास योजना की डी लिस्ट आज तक भी इंप्लीमेंट नहीं हुई है।

माननीय सभापति: माननीय सांसद महोदय, पिनाकी मिश्रा जी आप बोलिए।

श्री विनायक भाउराव राऊत: सभापति महोदया, मुझे आधा मिनट दीजिए। सभापति महोदया, प्रधान मंत्री आवास योजना एक अच्छी योजना है। मैं उसके लिए प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन जो बैलेंस है, उसके लिए तो मंजूरी देनी चाहिए। सभापति महोदया, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Madam, Chairperson, I rise to speak on behalf of my Party, Biju Janata Dal, on the Address by the hon. President of India to the joint session of Parliament and to convey our gratitude to the hon. President for having given his very important address to Parliament. The Address by the hon. President to Parliament is always significant for what it states and is equally significant for what it omits to state. Therefore, I will have the opportunity perhaps here to deal with both aspects when I speak further.

At paragraph 10, the hon. President had stated:

> "The people of the country have given this mandate to my Government for the making of a new India where every region develops, no region is left behind, where the benefits of modern technology reach the farthest end of society."

Then again at paragraph 71, the hon. President states that "in a federal country like India it is imperative for fast paced development that States compete with each other in development schemes; and also share experiences with each other. My Government has therefore been consistently emphasizing competitive cooperative federalism."

We, the Biju Janata Dal, are a regional Party looking after the interests of the State of Odisha and 4.5 crore people of Odisha. Hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik Ji, has been re-elected for the fifth time. It is an unprecedented

fifth election which he has won in Odisha. I think the people of Odisha definitely look up to him as somebody who has the interest of Odisha at heart and therefore, who is capable of protecting the interest of Odisha. But when the hon. President speaks about competitive cooperative federalism, it must be in the context of a level playing field. There has to be a level playing field, otherwise unequals can never be equals and unequals can never fight on the same field.

The Indian Constitution has been described by the constitutional experts, which we read in college, as a federal polity with a unitary bias. Some periods in our democracy, for instance, the seventies and eighties, saw muscular central governments come about. In these phases the country actually became a unitary form with a very mild federal flavour.

Today again there is a muscular Government and therefore the States must be very vigilant that this does not again become a unitary Government with a mild federal flavour. Be that as it may, I would like to point out to the House that the hon. President has not mentioned something very significant. Why do I say it is a non-level playing field? Odisha has now been buffeted by almost five severe or super severe cyclones in the last eight years. We have had Phailin, we have had Hudhud, we have had Titli, we have had Fani and now we recently had Bulbul. Five cyclones in eight years and each cyclone with a capacity to take the State back almost 15-20 years. How does that place us at par with other States

which do not have these kinds of natural calamities hitting them? We have been prised internationally. The Navin Patnaik Government has been repeatedly praised internationally by all sorts of organizations like United Nations, World Health Organization for the barest minimum casualities in these five cyclones. The casualties can actually be counted on fingertips. But the damage that has been done to property and infrastructure is incalculable. Therefore, when the Central Government looks to distribution of largesse to States, it should keep this in mind and therefore the hon. Chief Minister has repeatedly requested that a special focus, a targeted focus be given to calamity hit States like Odisha which is something that the hon. President's Address does not find mention. The special focus would entitle us to a 80 per cent to 20 per cent or to 90 per cent to 10 per cent ratio and that would help us recover much faster than we are able to recover today when these kind of cyclones and natural calamities hit us. It is either drought or cyclone which hit Odisha repeatedly year after year.

I have to further state with a degree of sadness that profligate States seem to be benefitting under our system rather than States like Odisha which had developed a very stringent system both in terms of financial prudence and in terms of population control. This is a very sad situation. Kindly see that the original 14th Finance Commission devolution to Odisha was Rs. 48,000 crore. By the time the vote on account of the last Government came, it had come down to Rs. 39,000. By the time, the first budget of this Government came, this has come

down further to Rs. 37,000 crore and today in the present budget, there is an estimate of Rs. 30,000 crore. So, we are coming down from Rs. 48,000 crore to Rs. 30,000 crore. Why does this happen? It is because ours is a revenue surplus State; it is because we do not spend wantonly. Since Naveen Patnaik Ji has taken over since 2000 as Chief Minister, he has kept a very, very tight financial ship and as a result of our financial prudence, we are getting punished. Kindly see that revenue deficit States are getting compensated unfairly; 14 States, by the 15th Finance Commission, are getting revenue deficit grant which a State like Odisha is going to be denied. It is only because of our financial fiscal prudence. The Finance Commission on top of that has now decided that urban local bodies will only give 50 per cent of its grant to million plus cities. We do not have any million plus city because we have also kept a cap on our population. Since we have had such a good record of population control in Odisha, we are therefore going to be doubly punished by not having a million plus city. Therefore, we do not get urban grant on that count and we will only get a rural grant and we will be completely deprived of urban grant. So, this is something that the Central Government must look into very carefully. This is something that the hon. President has again not mentioned and that is what we find is a little unfair to the State. Raut Ji has already spoken about GST compensation. I am sure that the other States are suffering the same way. Odisha has got nothing from September onwards. So, in the last five months, we have got nothing by way of our share of

the GST compensation. Therefore, this is again something which completely cripples us in our efforts to bring our State back to normalcy after cyclone Fani and cyclone Bulbul.

We have repeatedly requested the Central Government for a clean energy cess because we are a State where maximum mining takes place in terms of coal mining, iron ore mining and manganese mining. We are the repository of all industrial activities in the country; we suffer pollution and our people suffer air and water pollution. Therefore, we have been asking to give us a clean energy cess which is a basic fundamental right recognised and enshrined all over the world. We have so far not succeeded on this issue.

We asked for coal royalty revision which is again something which will help us in getting out of financial morass. Our hon. Chief Minister writes to the Central Government every year, for the last eight to ten years, on this issue, be it the past Government or this Government, to please give us a revision in coal royalty as that gives us a sense of financial independence but that is not happening. This is something which the hon. President ought to have taken note of. These are the demands of States like Odisha which are just demands.

Yesterday, I was very sad on one point and this may be referred to in the Budget speech on behalf of our Party. As regards archaeological sites, Odisha is a repository of the Kalinga civilisation which is 2000 years old. There is not a

single site which has been taken up as an archaeological site. Look at a site such as the Konark temple which is a world-famous site! It has the Sun Temple and the most magnificent architecture and scultures. It should have been easily recognised as one of the archaeological sites. That has not been done. We have a 38 per cent tribal population and we do not get a tribal museum. Is that fair?

Most importantly, and I want to emphasise on something which the hon. Chief Minister has again repeatedly requested the Centre. There is a census which is on now. I do not want to get into its merits and demerits now. And our State Chief Minister also does not want to get into them but the difficulty which Odisha has is that we have 25 per cent tribal population and 12 per cent Scheduled Castes population. So, it comes to almost 37 to 40 per cent. We have a very large OBC population but we still do not have an enumeration of what is the population of OBCs. The hon. Chief Minister has therefore repeatedly requested that, in your census, where you say SC, ST and Others, please say SC, ST, OBC and others because this will give the country an idea of the actual number of OBCs. Nobody in the country at the moment knows what are the OBC numbers. And it is not fair because they always get left out in the reservation pro-rata proportion because nobody knows their numbers. Therefore, the hon. Chief minister has repeatedly requested on this issue. I urge the Government in this regard and I think, hon. President ought to have taken note of this. Hence, I urge

the Government to kindly ensure that there is an OBC enumeration which takes place.

I would also like to commend the Government for certain steps that they have taken on the request of the Chief Minister. There is no question of not appreciating it when the Government accedes to certain requests of ours. We have to be grateful for Fani assistance. I have said it on the Floor of the House earlier also that the hon. Prime Minister went to Odisha and immediately gave us a grant which helped us to somewhat recover. Therefore, there is no question that when push has come to shove, the hon. Prime Minister had looked to Odisha with some help. There has also been a seamless transition from the lessee era to the auction era as far as Environment Clearances and the Forest Clearances are concerned. That is something for which we are again grateful because there is no stoppage of production and thus, Odisha does not suffer as far as productivity goes. We are happy that this had happened.

There has been an increased allotment on rural housing. We are grateful for it. Recently, the Prime Minister has personally said that he is going to look into many of the stalled railway projects in the State. We are grateful for it as he has given his personal attention to it because the largest revenue is given by Odisha to the Indian Railways. About Rs. 17,000 crore to Rs. 20,000 crore annually comes from the State of Odisha and that is the largest revenue in the country.

We get a fraction of that back. We get hardly Rs. 2000 crore to Rs. 2500 crores. If you spend even 50 per cent of the Rs. 17,000 crore to Rs. 20,000 crore, the estimate is that the Railways will double their revenue and it will become Rs. 40,000 crore revenue from Odisha. So, this is something that somebody like the hon. Prime Minister will recognise and I am sure that he has recognised that.

As a Member of Parliament from Puri, I have a personal anguish to which I would like to draw the attention of the Minister of Culture. He was present but I think he has left now. The BJP manifesto itself said that Puri would be regarded as or would be encouraged to become the "cultural capital of India". It is one of the four Dhams. It is a place of worship where lakhs and lakhs of people visit every year.

17.00 hrs

A Cultural Capital requires certain ingredients. Therefore, I urge the Central Government to look towards Puri and give special grants because there is a massive drive underway at the moment to make Puri a world class city. Therefore, whatever help the Central Government gives in that regard, would be a welcome step. I think, the hon. Prime Minister would be the first person to do so because he has been to that Temple, the blessings of Lord Jagannath are on him, and the people of Odisha have showered great blessings on the BJP this time by way of the number of MPs that they have sent to Parliament. Therefore, I think, it is

incumbent on the hon. Prime Minister as well as on the BJP to return the favour to Puri by giving grants to Puri, to make it a world-class city so that it becomes the Cultural Capital. My colleague from Kendrapara is also here who is also very anxious that the pending railway projects in Kendrapara district and also in Cuttack district, which are very critical for mining interest of the State and the country as a whole, be given precedence. Therefore, I have no doubt that when we have urged the hon. Prime Minister, he will take note of this.

At the end, Madam Chairperson, I would once again like to thank the hon. President for having taken the trouble, to have given us a complete conspectus of what the Government's aims and ambitions for the coming year are. They are laudable but there is a long distance to travel. …(*Interruptions*)

श्री प्रहलाद जोशी : 98 प्रतिशत प्रीमियम मिला है, जो आपने सुझाव दिया है।…(व्यवधान)

SHRI PINAKI MISRA: That is why, I said that I am grateful to the hon. Prime Minister that he has actually given us the seamless connectivity from the old regime to the new regime, and that is why, it has happened. It is because the industralists have the confidence that there would be no stoppage. So, where there would be praise to be given, we would be the first to give unstinted praise. Our hon. Chief Minister has repeatedly done that. As regards cooperative federalism, we are number one; we are with you. On competitive federalism please give us a level playing field. Odisha can take up the challenge, let me

assure you, to be at par with the rest of the country. We will not be left lagging behind. I once again thank the hon. President for having taken the trouble to address us.

माननीय सभापति: माननीय सांसद, श्री रितेश पाण्डेय जी।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के विचारों को रखने के लिए समय दिया है।

17.03 hrs (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

सरकार का पक्ष रखते हुए आदरणीय महामहिम ने यह कहा कि देश की जनता ने सरकार को जनादेश एक नए भारत के निर्माण के लिए दिया है । एक ऐसा नया भारत जिसमें हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो । यहां मुझे ऋग्वेद का एक सूत्र स्मरण होता है – 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ।' इसी सूत्र का स्मरण करते हुए महात्मा बुद्ध ने जनमानस के कल्याण के लिए अपना उपदेश दिया था और इसी विचार को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक कुशल नेता के रूप में बताया था । आज उसी वैदिक सिद्धांत पर दिन-दहाड़े गोली मारे जाने के नारे लगाए जाते हैं । जहां विभाजनकारी सीएए, एनआरसी और एनपीआर की दूषित विचारधारा के विपरीत देश भर में आक्रोश उठा हुआ है, उसी आक्रोश को दबाने के लिए सरकार पुलिस का घटिया इस्तेमाल करने का काम कर रही है । उदाहरणस्वरूप, आप लखनऊ, उत्तरप्रदेश और दिल्ली को ले लीजिए, जहां पर पुलिस ने महिलाओं, छात्र-छात्राओं और छोटे-छोटे बच्चों को भी पीट कर अलग कर दिया है । उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं और यहां तक कि दिन-दहाड़े गोलियां मार दी गई हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विचारधारा बाबा साहेब अम्बेडकर, माननीय पटेल जी और माननीय गांधी जी की नहीं है । यह विचारधारा पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना की है । जिन्होंने कहा था और मैं कोट करना चाहता हूं कि यह बस एक सपना है कि हिन्दुओं और मुसलमानों की एक सामान्य राष्ट्रीयता बन सकती है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आज सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार सीएए और एनआरसी को लागू करके जिन्ना के सपनों को साकार करना चाहती है । मैं यह पूछना

चाहता हूं कि हमारी संस्कृति कहां गई, कहां गया वसुधैव कुटुम्बकम का विचार, क्या हम उससे दूर तो नहीं हट रहे हैं?

माननीय महामहिम ने सरकार का पक्ष रखते हुए यह भी कहा था कि एक ऐसे नए भारत की स्थापना हो, जिसमें गरीब, दलित, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुविधाएं मिले और आगे बढ़ने के समान अवसर मिले।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब बेरोज़गारी 45 साल में अपनी चरमसीमा पर पहुँच चुकी है, जब आम लोगों की खरीदने की क्षमता में भारी गिरावट आई है, जब हमारे उच्च शिक्षा संस्थान प्रोफेसरों की कमी से ग्रसित हैं, उच्च शिक्षा के संस्थानों में जितनी भी मूलभूत सुविधाएँ हैं, वे घटिया किस्म की हैं। जब हम उनको नहीं सुधार सकते हैं, तो हम किन समान अवसरों की बात कर रहे हैं?

मान्यवर, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र का एक समान मूलमंत्र है कि जब किसी भी देश में आर्थिक मंदी आती है, तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव उस देश के सबसे कमजोर तबके पर पड़ता है। कौन-सा है वह कमजोर तबका? आप जिसे सुनहरे सपने दिखाने का काम करते हैं, वह तबका है- गरीब, अल्पसंख्यक, दलित और महिलाएँ। आप उनसे ...* बोलकर उनकी आँखों में धूल झोंकने का काम नहीं कर सकते।

मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने यह स्पष्ट किया है कि जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं, उन सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है, आज उनको संविदा पर देकर आपने इन्हीं दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हक छीनने का काम किया है। जब उनको इसमें आरक्षण मिलता था, तो वह अपने हक के हिसाब से समाज में और आर्थिक व्यवस्था में बराबर की हिस्सेदारी निभाने का काम करते थे। आज आप उनसे यह हक छीनकर उनके अधिकारों का गला घोंट रहे हैं, आप बाबा साहब के विचारों का गला घोंट रहे हैं।

* Not recorded.

आदरणीय महामहिम ने सरकार का पक्ष रखते हुए यह भी कहा कि एक ऐसे नये भारत की स्थापना होगी, जो चौथी औद्योगिक क्रांति की अग्रिम भूमिका निभाएगी और विश्व-मंच पर नई ऊँचाइयों पर पहुँचने का काम करेगी।

मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि यह एक कटु सत्य है कि भारत इस दौर में पीछे हो चुका है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि पिछले छ: वर्षों में ऐसी कोई भी नीति नहीं बनाई गई है, जिससे हम चौथी औद्योगिक क्रांति में चाइना, अमेरिका और ई.यू. से प्रतिस्पर्धा कर सकें। क्या है यह चौथी औद्योगिक क्रांति? इसके बारे में सरकार बोलती है, लेकिन क्या इसके बारे में हमारा समाज समझता है? यानी चौथी औद्योगिक क्रांति का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, थ्री डी प्रिंटिंग, बायो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कम्प्यूटिंग आदि के बारे में सुनहरे सपने तो दिखा रहे हैं, लेकिन क्या हिन्दुस्तान का कोई भी पीएचडी स्टूडेंट अमेरिका और चाइना के पीएचडी स्टूडेंट के सामने कम्पीटिशन कर सकता है? क्या सरकार यह बता सकती है कि स्टैंडफोर्ड, एमआईटी, सिंघुवा और पीकिंग यूनिवर्सिटी के पीएचडी रिसर्च स्टूडेंट्स ग्रांट के सामने भारत का रिसर्च स्टूडेंट ग्रांट खड़ा होने का भी काम कर सकता है? हरगिज नहीं। हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स की ग्रांट किसी लायक नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आप वैसे भी बड़ी-बड़ी बातें कर सकते हैं चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में, लेकिन मैं आपके सामने यह सच उजागर करना चाहता हूँ कि जब आप बुनियादी औद्योगिक क्षेत्रों को ही नहीं बचा पा रहे हैं, तो इंडस्ट्री 4.0 एक डायवर्जन है। आप फिर से जनता को सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर, झुंझुना बजाकर उनके दिमाग को असली मुद्दों से हटाने का काम कर रहे हैं।

इस देश को बहन कुमारी मायावती जी के विचारों के हिसाब से सीएए और एनआरसी जैसे विभाजनकारी और गैर-संवैधानिक कानून नहीं चाहिए।

देश को एक सकारात्मक, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील नेतृत्व चाहिए। आप याद रखिए कि जनता ने आपको यह जनादेश इंटॉलरेंट इंडिया का खिताब जीतने के लिए नहीं दिया है। जनता ने आपको यह जनादेश अच्छे दिन लाने के लिए दिया था। आप उस पर काम कीजिए। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ, जिसकी आप मुझे आज्ञा दें।

बाँट दिया इस धरती को,
चाँद-सितारों का क्या होगा?
नदियों के कुछ नाम रखे हैं,
बहती धाराओं का क्या होगा?

शिव की गंगा भी पानी है,
आबे-ज़मज़म भी पानी है,
मुल्ला भी पिये, पंडित भी पिये,
अब पानी का मज़हब क्या होगा?

इन फ़िरकापरस्तों से पूछो,
क्या सूरज अलग बनाओगे?
एक हवा में साँस है सबकी,
क्या हवा भी नयी चलाओगे?

नस्लों का करे जो बँटवारा,
रहबर वो कौम का ढोंगी है,
क्या खुदा ने मन्दिर तोड़ा था
या राम ने मस्जिद तोड़ी है?

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): सर, माननीय राष्ट्रपति जी का जो भाषण है, मैं उसके बिलकुल भी हक में नहीं हूं, क्योंकि इसमें पंजाब के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। पंजाब, जिसने हमेशा ही, चाहे अनाज हो, चाहे आर्मी हो, हर तरफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। आज पंजाब के किसान की कर्जा माफी के लिए राष्ट्रपति जी के इस एड्रेस में कुछ भी नहीं था।

सर, मुझे यहां आए तकरीबन एक साल हो गया है और हर बार एक ही बात सुनने को मिलती है, यह तीसरा सैशन है, कि हम किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, उसकी आय दोगुनी कर देंगे, मगर राष्ट्रपति जी के इस आम भाषण में एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी, दोगुनी तो दूर की बात है, जिससे यह पता चले कि 5-10 परसेंट आमदनी बढ़ सके। पंजाब में समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी ऐपिडेमिक है। वहां कैंसर के पीड़ितों की गिनती काफी बढ़ चुकी है। हमारे सभी जो पंजाब के एमपीज़ हैं, चाहे वे इस तरफ से हों या उस तरफ से हों, ये सभी अपने-अपने टाइम पर, अपने-अपने तरीके से वहां कैंसर इन्स्टीट्यूट की मांग करते रहे हैं, मगर मुझे अफसोस है कि पंजाब के लिए वह भी हमें नसीब नहीं है, जो हमारी सेहत के लिए सबसे जरूरी है।

सर, पंजाब में रेलवे के तीन प्रोजेक्ट्स काफी दिनों से अटके पड़े हैं। मुझे बहुत आशा थी कि इस बार उन प्रोजेक्ट्स का कुछ न कुछ होगा। पट्टी-फिरोज़पुर रेलवे लाइन, ब्यास-कादियां रेलवे लाइन और भटिंडा-चण्डीगढ़ की जो टू-लेनिंग थी, उसका कोई ज़िक्र तक नहीं किया गया। यह हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि वर्ष 1947 में भारत-पाकिस्तान का जो पार्टिशन हुआ था, वह सबसे बड़ी वॉयलेंट मास माइग्रेशन थी। उसमें तकरीबन एक लाख लोग मारे गए और कई लाख पाकिस्तान छोड़कर इधर आए और इधर से उधर गए। अफसोस की बात है कि अब आप नए एनपीआर में मांग रहे हैं कि अपनी फैमिली के सबूत दो? वे लोग, जो अपना सब कुछ – ज़मीन, जायदाद, घर, सिर्फ एक कपड़े में यहां पहुंचे थे, वे ये सबूत कहां से लाएंगे? …(व्यवधान)

सर, पंजाब के तीन नेबरिंग स्टेट्स हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उसके साथ ही लगता उत्तरांचल है। वहां इन्डस्ट्रीज़ पर टैक्स-रिबेट है, टैक्स-इन्सेन्टिव्स हैं। हमारे यहां से बहुत ज्यादा इन्डस्ट्रीज़ पलायन कर के वहां चली गई हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि आप उनको टैक्स-इन्सेन्टिव्स मत दीजिए, हम कहते हैं कि आप उनको दीजिए, लेकिन पंजाब को मत छोड़िए। आप सारे पंजाब को दीजिए, नहीं तो हमारे जो सरहदी जिले हैं, उनमें हमें ये टैक्स-इन्सेन्टिव्स जरूर चाहिए।

सर, हमारा लुधियाना हौजरी और साइकिल के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। खेलों के सामान के लिए जालंधर, स्टील के लिए बटाला और गोबिंदगढ़ जाना जाता है। पंजाब एक लैण्ड-लॉक्ड स्टेट है। हम यहां से बहुत ज्यादा शिपिंग कहीं नहीं कर सकते हैं। यह हमारा निवेदन है और हमने पहले भी सोचा था कि खालड़ा बॉर्डर से ट्रेड शुरू हो जाएगा, सेंट्रल-एशियन कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ में हमारा सामान जाएगा, पंजाब का किसान खुशहाल होगा और हमारे यहां की इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी-फूलेंगी।

राष्ट्रपति जी के एड्रेस में उन्होंने कहा कि हमने गुरु नानक साहब का 550 वां जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास से मनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 वां जन्मदिवस है, उसको भी मनाएंगे। मुझे अफसोस है कि गुरु नानक साहब के 550 वें पर्व पर एक पैसा भी केन्द्र सरकार की तरफ नहीं दिया गया है और न ही कोई प्रोजेक्ट दिया गया है। आप बजट देख लीजिए, उसमें एक भी पैसा नहीं है। उसमें जो रेफरेंस दिया गया है, वह भी दिल्ली इलैक्शन की वजह से दिया गया है, ताकि यहां का सिख समुदाय इनको वोट दे सके। यह हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो बहुत बढ़िया ऑइल के पी.एस.यूज. थे, जैसे भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और इनके साथ-साथ आज एयर इण्डिया, बी.एस.एन.एल. की हालत भी खराब है। आज इनको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। मेरा एक निवेदन है और मैं एक

उदाहरण भी देना चाहता हूं। मैं 11 दिसम्बर को दिल्ली से 40 मिनट की फ्लाइट में विस्तारा एयरलाइंस से इकॉनोमी क्लास में गया था। उस 40 मिनट की कीमत 22 हजार रुपये थी। यही मैं बी.एस.एन.एल. के लिए कहना चाहता हूं। अगर हमने इनको भी प्राइवेटाइज कर दिया, तो इससे प्राइवेट वाले लोगों को बहुत लूटेंगे। अगर प्राइसेज को कंट्रोल में रखना है तो हमारे पी.एस.यूज. को जिंदा रखना बहुत जरूरी है।

मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि हमें बेरोजगारी से आजादी चाहिए, हमें बीमारी से आजादी चाहिए, हमें अनपढ़ता से आजादी चाहिए। मैं यही विनती करना चाहता हूं कि सामने बैठने वाले लोग यही लक्ष्य बना लें तो अच्छा है।

*SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD) : Chairman Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks on President's Address. Immediately after constitution of the 17th Lok Sabha and when we heard to the President's Address last year, I had witnessed lot of zeal and enthusiasm in this House. BJP came to power with full majority and this is for the first time in the last 30 years since 1984 when Rajiv Gandhi Government had come to power with this kind of majority. The kind of enthusiasm and optimism we had witnessed last year, we have missed that kind of enthusiasm this year and have experienced little bit of disappointment. The people at large had great expectations from this Government and they believed that, some concrete steps would be taken up by this Government to solve the acute and serious problems faced in this country. You had promised the farmers of this country that their income would be doubled. I am not here to criticize anybody but nobody knows who is the Agriculture Minister of this country. I don't want to criticize.

But when Hon. Sharad Pawarji was the Agriculture Minister of this country, he tried his level best for the betterment of agriculture sector. We expected that the loan waiver would be given to the crores of debt-ridden farmers of this country. But nothing has been done in this regard. There is no mention about Swaminathan Committee Report. No roadmap for the developmental activities

* English translation of the speech originally delivered in Marathi

has been given by this Government. Hon. Girish ji Bapat is my friend. Hon. Nitin ji Gadkari is known as a very enthusiastic and active Minister in this Government but he has become inactive in the last one year or so. Road construction projects are stalled in Maharashtra. In my Konkan area, the highway construction work is stopped totally. Even the coastal highway work is stopped and Gadkariji looks completely disappointed. BSNL is completely devastated. Road construction works are stalled. This Government is totally failed in fulfilling the aspirations and expectations of the people. Yesterday I heard the Finance Minister's speech. In our country 6 places are going to be developed as heritage sites. You have come to power by taking the name of Chhatrapati Shivaji Maharaj. But, you are not willing to develop Raigad Fort as per our demand. You only chant the name of Shivaji Maharaj but you are not following his path. This is my earnest demand to the State as well as Union Government that this fort should be included in the UNESCO list of world heritage sites. It will help to attract more history lover tourists towards this fort.

Unemployment is a bigger issue in our country. We have seen what happened in JNU. Students are on streets and they are protesting against Government policies. This is a kind warning given by the unemployed youths. But this Government is not keen on the issue of employment; they are only spreading religious hatred in the name of CAA and NRC. Dr. Babasaheb Ambedkar had warned us through the Constitution of India in this regard. But,

you are neglecting the Constitution. Hence, we have to come forward to save our Constitution.

You have not solved the problems of the country. Instead you have created new issues. Some members in this House tried to stop Vinayak Raut ji from delivering his speech. A new coalition Government has come to power in Maharashtra. But, some people are not happy with it. Under the Chief Ministership of Uddavji Thakre new Government is formed with the guidance of Sharad Pawarji and Sonia Gandhiji. On 1st May, 1960 Gujarat and Maharashtra States were created out from the Bombay province. But you are doing injustice to Maharashtra. Sufficient funds should be given to Maharashtra. Hon. Sharad Pawarji delivered a historic speech at Satare when it was raining and that had changed the entire election scenario in Maharashtra. He is 80 now. He has been in active politics for the last 54 years. He was Member of Parliament for 7 times. He deserves due respect and honour.

Shri CD Deshmukh was the Finance Minister of this country. He founded life Insurance Corporation of India. I hail from his village Roha. Now Government has come with a proposal of disinvestment of LIC. We will oppose it wholeheartedly. I demand that it should be stopped. Lastly,I express my unhappiness over this Presidential Address. Jai hind, Jai Maharashtra.

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा बजट सत्र के शुभारंभ में जो अभिभाषण दिया गया है, मैं उसके धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने जिस तरह से अपने अभिभाषण में देश की वर्तमान सरकार और देश की वर्तमान स्थितियों के बारे में कहा है, वह निश्चित रूप से हम सभी को एक नई रोशनी, एक नया रास्ता दिखाता है। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि यह देश एक बड़ा देश था, जिसकी सांस्कृतिक रूप से बहुत-सी परंपराएं थीं, यह देश पूरी दुनिया में ज्ञान और शिक्षा के मामले में एक अभूतपूर्व स्थान रखता था। आज़ादी की एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद लोगों को यह विश्वास था कि यह देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और स्वतंत्रता के बाद इस देश और देश के लोगों को न केवल अधिकार मिलेंगे, बल्कि एक सशक्त राष्ट्र के रूप में यह देश विकसित होकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा।

माननीय सभापति महोदय, उस समय हमारे पास बहुत अच्छी फिलॉस्फी थी, दर्शन था, जिनका वर्णन महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है। उन्होंने कहा है कि गांधी जी के स्वराज का सपना, डॉक्टर अंबेडकर का समतामूलक समाज बने, लोहिया जी का समाजवाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय और एकात्म मानववाद का दर्शन हमारे समाने था। हमको उसकी छांव में आधुनिक भारत का निर्माण करना था। मैं कहूंगा कि आज़ादी के बाद निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ा है। लेकिन हमारी जो अपेक्षाएं थीं, इस देश के लोगों को जो उम्मीदें थीं, हम उस अनुसार आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कई घटनाएं हुई होंगी। मैं उन घटनाक्रमों में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि जब इस देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय का दर्शन हमारा मूल आधार था। हमको जब भी और जहां कहीं भी प्रदेशों में सरकारें बनाने का अवसर मिला था, या केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि देश के संसाधनों का पहला हक सबसे पीछे खड़े हुए

व्यक्ति के लिए है। गरीब के कल्याण के लिए सरकार बने और उसके साथ-साथ महिला सशक्तीकरण हो, किसानों के लिए काम हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हों और पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़े। हम इन बातों के लिए काम कर रहे थे।

जब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उसने निश्चित रूप से ऐसे बहुत से काम किए थे, जिससे यह देश आगे बढ़ सका है। लेकिन वर्ष 2004 से 2014 तक का जो कार्यकाल था, मैं जिसके बारे में कह सकता हूं और यह कहा भी गया है कि एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने थे, वह इस तरह से बने थे कि जिनके हाथ में सीमित क्षमताएं और सीमित ताकतें थीं। उनका रिमोट कंट्रोल कहीं और था। उसका दुष्परिणाम यह था कि उस दस वर्ष में इस देश में अनेकों-अनेक घोटाले हुए थे। यह देश आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था। उसके परिणामस्वरूप महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और विकास का पहिया थम गया था। देश की सीमाएं असुरक्षित हो गई थीं और पूरी दुनिया में भारत के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा था।

ऐसे समय में वर्ष 2014 का जो लोक सभा का चुनाव हुआ था, वह चुनाव इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पाइंट था। उस समय इस देश के लोगों ने यह तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और उन्होंने आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाई थी। उस सरकार के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। हमारे साथ देश की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थीं और हमारे सामने बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियां खड़ी थीं। उस समय जिस तरह की स्थितियां थीं, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो पहली सभा की थी, उसमें उन्होंने सांसदों के साथ बैठकर यह कहा था कि आप एक चुनाव जीतकर आए हैं और चुनाव जीतने के बाद आपके सामने दो विकल्प हैं। आपके पास एक विकल्प यह है कि आप इस जीत की खुशी मनाइए और आप खुशी मनाने के बाद कुछ दिनों के लिए आराम भी कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा विकल्प है, वह कठिन है। इस देश के लोगों ने

आपको उन्हीं उम्मीदों के साथ चुना है। आप उसमें लगकर और पूरे परिश्रम के साथ कि कैसे हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं, उस पर काम कीजिए। भारतीय जनसंघ का जो दर्शन था, वही दर्शन हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी था। उस समय हमारे देश में ऐसे 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग थे, जिनके पास शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं नहीं थीं।

रोज़गार नहीं था, पीने का पानी नहीं था। घर-मकान पर छत नहीं थी। शौचालय नहीं था। ऐसी स्थितियों में उन्होंने कहा कि यह हमारी पहली चुनौती है। यह सरकार, गरीबों की सरकार होगी। हमारी सरकार ने, जैसे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है, लोगों को पक्के घर, दो करोड़ से ज्यादा घर हमने बना कर दिए हैं। दस करोड़ शौचालय बनाए हैं। अभी हमारे एक साथी, जो पूर्व में हमारी साथी रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि आठ करोड़ गैस के कनेक्शन तो मोदी जी की सरकार ने दिए हैं, लेकिन 20 हजार उनके क्षेत्र में रह गए हैं। वे उसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वे आठ करोड़ कनेक्शन क्या आज तक किसी ने कभी दिए थे? लेकिन इस सरकार ने न केवल गरीबों के कल्याण के लिए उनको मकान, शौचालय, उनके घर-घर तक बिजली पहुंचाना, गांवों की बात छोड़िए, हर घर तक बिजली हमने पहुंचाई है, पीने का साफ पानी पहुंचाया है। हमारा लक्ष्य है कि सन् 2024 तक नल से जल हर घर तक हम पहुंचाएंगे। उन सारे लक्ष्यों को पूरा करते हुए, महिला सशक्तीकरण के लिए हमने काम किया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ। लोगों को पेंशन दी गई। गरीबों का बीमा हुआ। किसानों की आमदनी बढ़े, कम जमीन में ज्यादा फसल का उत्पादन हो। फसल का पूरा दाम मिले। उनकी फसल का अगर नुकसान होता है, तो उसकी आपूर्ति की जाए। इन सब कामों को एक पारदर्शी सरकार कर रही थी। आपने देखा होगा कि जिस तरह से इस देश की सीमाएं सुरक्षित की गईं, देश को नई पीढ़ी का कोई वायुयान नहीं मिला था। हमारे साथियों ने लोक सभा में ही लगातार राफेल को ले कर न जाने कितने प्रश्न उठाए। आज कहां वे खड़े हो गए? कहां स्थितियां आ गईं? इन सब पर विचार

करने की जरूरत है। आज हम ऐसी स्थिति में पांच साल में आए कि हमने इस देश को एक ऐसी, इस तरह की नींव बना कर दी, जिस पर लोगों को लगने लगा कि यह देश वास्तव में आगे बढ़ने की क्षमता और योग्यता रखता है और नरेन्द्र मोदी जी वे नेता हैं, जिनके नेतृत्व में यह देश पूरी दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र की अपनी पहचान को बना सकता है। यही कारण था कि सन् 2019 का जो चुनाव आया, उस चुनाव में महागठबंधन हो गया। लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने जिस तरह से पांच वर्ष तक लगातार इस देश और देश के लोगों की सेवा की थी और पारदर्शी सरकार चलाई थी, मन की बात को लोग बहुत सामान्य रूप से लेते हैं, लेकिन मन की बात कर के उन्होंने इस देश के एक-एक आदमी को इस सरकार से जोड़ दिया था और उसी का परिणाम था कि जब सन् 2019 का चुनाव आया तो लोगों को लगा कि यह हमारी सरकार है और इस सरकार के खिलाफ जब सारे लोग खड़े हो गए हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी की अकेले ताकत नहीं थी, यह पूरा देश महागठबंधन के खिलाफ खड़ा हो गया और भारतीय जनता पार्टी को सन् 2014 से बड़ा बहुमत देने का काम इस देश ने किया। उस समय हमारे प्रधान मंत्री जी ने, जब सन् 2019 के चुनाव का कैंपेन चल रहा था, उस समय उन्होंने साफ-साफ और स्पष्ट कहा था कि हमारा जो पिछला कार्यकाल था, वह लोगों की जरूरतें पूरी करने का कार्यकाल था। सबका साथ सबका विकास कार्यकाल था। लेकिन हमारा जो अगला कार्यकाल होगा, वह लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का कार्यकाल होगा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्यकाल होगा। क्योंकि हम लोग 70 साल से देख रहे थे, चाहे वह धारा 370 हो, अनुच्छेद 35 ए को हटाने की बात हो, चाहे सीएए हो, जो हम लोगों ने अभी संशोधन किया, तीन तलाक का मामला, बंगलादेश की सीमाओं की बात हो, ऐसे सभी काम, ऐसी चुनौतियां थीं, जो बहुत लंबे समय से लंबित थीं, उन पर हमने काम किया। आर्थिक रूप से देश सशक्त हो, उसके लिए बैंक्रप्सी कोड से ले कर फाइनेंस बिल हम लेकर आए हैं। देश की अर्थव्यवस्था, आज हम कह सकते हैं कि एफडीआई के रूप में इस समय विदेशी मुद्रा का भंडार सर्वोच्च सीमा पर है। हमने पिछले छह साल के अंदर रुपये की

अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग बराबर रखी है। यह इस देश की आर्थिक ताकत को दर्शाता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ पूरे देश का सम्मान बढ़ाने का काम भी किया है। प्रधान मंत्री जी को ऐसे-ऐसे देशों ने, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, वहां के देशों ने प्रधान मंत्री जी का सम्मान किया है। उनका सम्मान करना देश का सम्मान है। पूरी दुनिया आज भारत को इस तरह से देख रही है कि यह वह देश है, जिसके नेतृत्व में पूरी दुनिया आगे बढ़ सकती है और यही हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति यही है कि :-

'सर्वे भवन्तु सुखिन:

सर्वे सन्तु निरामय:'

हम तो कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हमने ताकत के जोर पर कभी भी किसी के ऊपर शासन करने की बात नहीं की है। हमने हमेशा कहा है और प्रधान मंत्री जी ने भी यह बात बार-बार दोहराई है कि हम सत्ता में सेवा के लिए नहीं आए हैं, शासन करने के लिए नहीं आए हैं और जिस तरह से इस पिछले सात महीनों के अंदर हमारी सरकार ने काम किए हैं, लोगों के अंदर हताशा और निराशा है। जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, वे लोग हताश हैं। उनकी हताशा और निराशा इस कद्र बढ़ गई है कि जैसे अभी बात कर रहे थे कि संविधान खतरे में है।

आप संविधान की प्रस्तावना लेकर जाते, पढ़ते, बहुत अच्छी बात है। अगर आप संविधान को लेकर कोई आंदोलन करते हैं, धरना-प्रदर्शन करते हैं, यह देश के लिए गर्व का विषय है। अगर आप तिरंगा झंडा लगा कर करते, तो और गर्व का विषय है। गांधी जी और अम्बेडकर जी के चित्र लेकर करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संविधान को समझने की आवश्यकता है। सर, मुझे पाँच मिनट का समय और दे दीजिए। हमारी पार्टी का समय है, उसमें से कम कर लीजिएगा। पाँच मिनट का समय दे दीजिए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : You have already finished your time. Please conclude in two minutes.

श्री अजय मिश्र टेनी : सर, बस पाँच-सात मिनट लगेंगे । संविधान की प्रस्तावना के साथ-साथ हम लोगों को कर्त्तव्यों को भी पढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने जैसे कहा कि आने वाले दस साल इस बात के होंगे कि लोग अधिकारों के साथ-साथ कर्त्तव्यों की भी बात करें। चूँकि इस देश ने यह तय किया है कि वर्ष 2025 तक हम 5 ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। हमने यह तय किया है कि हर व्यक्ति को घर-मकान ऐसी सुविधाएँ देंगे, इसलिए ये चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं कि हम अधिकारों से पहले कर्त्तव्यों की बात करें। जहाँ तक संविधान की बात आती है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि संविधान को सबसे ज्यादा अगर चोट पहुँचाई है तो पिछली सरकारों ने पहुँचाई है। हमने तो सबसे कम संविधान में संशोधन किए हैं। हमने संविधान में संशोधन किया है तो बांग्लादेश की सीमा पर अच्छे तरीके से गाँव विकसित हो सके, नागरिकों को उनके समान अधिकार की सुविधा मिल सके, इसलिए किया। हमने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए संविधान में संशोधन किया। हमने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए संविधान में संशोधन किया । हमने संशोधन किया है- सामान्य जाति के जो 10 प्रतिशत गरीब और पिछड़े लोग हैं, उनके लिए हमने संविधान में संशोधन किया। हमने संविधान में संशोधन किया है- कश्मीर में 370 हटाने के लिए, धारा 35ए हटाने के लिए। हमने कोई भी ऐसा संविधान में संशोधन नहीं किया, जो हमारे फायदे के लिए हो या सरकार के लिए हो। लेकिन मैं यह बात कहना चाहता हूँ, यह इतिहास में दर्ज है कि सबसे ज्यादा बार अगर किसी ने संविधान का दुरुपयोग किया है, तो हमारी पूर्व प्रधान मंत्री थी, माननीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार संविधान में संशोधन किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 संविधान संशोधन करने के साथ-साथ 9वीं अनुसूची को जोड़ा था और उसमें वैसे कानूनों को रखा जाता है, आपको पता होगा कि 9वीं अनुसूची में वह कानून रखे जाते हैं, जिनकी समीक्षा न्यायालय को भी करने का अधिकार नहीं है।

सबसे ज्यादा ऐसे कानून, 124 कानून इंदिरा जी की सरकार के समय में आए। बस दो मिनट का समय दे दीजिए। मैं सीएए के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्री अजय मिश्र टेनी: सर, अभी जैसे हमारे लोग कह रहे हैं। यहाँ पर सीएए का बहुत विरोध कर रहे हैं। सीएए का विरोध करने के केवल तीन आधार बताते हैं। वे यह कहते हैं कि इसमें सारे देशों को क्यों नहीं शामिल किया, इसमें मुस्लिम लोगों को क्यों नहीं शामिल किया? ये कहते हैं कि आपसे कागज माँगा जाएगा। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में नागरिकता बिल, 1955 में आया था और सब देशों का होता है। उसका देश के किसी नागरिक से कोई संबंध नहीं होता है। उसका संबंध उन लोगों से होता है, जो देश में नागरिकता माँगते हैं। इसी कारण पूरी दुनिया के किसी देश में रहने वाला कोई आदमी नागरिकता बिल के माध्यम से इस देश की नागरिकता को माँग सकता है। कागज माँगने की बात है तो जब यह इस देश के लोगों से संबंधित ही नहीं है, तो उसका सवाल ही नहीं उठता। अगर सीएए की बात करें...(व्यवधान)

माननीय सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री अजय मिश्र टेनी: सर, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। अगर सीएए की बात करें तो हमेशा हमने यह देखा है कि किसी भी बिल में जब संशोधन किया जाता है, तो किसी धारा को बढ़ाने या किसी कानून को घटाने के लिए संशोधन होता है। यह गांधी जी का कमिटमेंट था, जवाहरलाल नेहरू जी का कमिटमेंट था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अगर हिन्दू आते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ मिल कर इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जब वह पाकिस्तान में रह गए तो अंग्रेजों से बदतर गुलामी की स्थिति में पहुँच गए। उनका कमिटमेंट था, हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। हमारी सरकार ने बिना वोट बैंक की चिंता किए हुए इस काम को किया है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्री अजय मिश्र टेनी : सर, मैं बस एक लाइन में कनक्लूड कर रहा हूँ। अभी न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट हमारे प्रधान मंत्री जी ने रखा है, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे पूरे सदन की है। अभी बहुत सारे साथियों ने कहा कि उनको आज़ादी इन्हीं सब चीजों से चाहिए। हम भी उनसे सहमत हैं कि जो भी कमियाँ हैं, हमारे देश में इस तरह की घटनाएँ हैं, जो हमारे देश के विकास को अवरुद्ध करती हैं, हमारी-आपकी जिम्मेदारी है। हम सब मिल कर के आगे बढ़ें। जो न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट है, सब शिक्षित हों, सब के पास इलाज की सुविधा हो, अच्छी सड़कें हों, पानी हो, घर हो, रोज़गार हो, आय के संसाधनों के साथ-साथ देश की सीमाएँ सुरक्षित हों और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़े, इसके लिए मैं पुन: राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI S. JAGATHRAKASHAKAN (ARAKKONAM): Mr. Chairman, Sir, thank you.

I would like to start my speech by quoting a famous couplet from Thirukural. It says:

Allarpattu Atradhu Azhudha Kanneranrey
Selvathai theikum padai

It means, “Tears shed by the people who suffer due to authoritative and oppressive treatment by the Government have the strength to dethrone the King.

I had the rich privilege to hear President’s Address in the dawn of new decade with hope and aspiration. But to the disappointment of many, it fails to evoke the masses who have been frustrated by the recent decisions of the Government in promoting religious nationalism instead of safeguarding secular principles. The Address of the President was more like promises listed out in an election manifesto. In his Address, the hon. President highlighted the New India, but our country is witnessing low GDP numbers, shrinking job market, farmer suicides and disappointing foreign policies.

I would like to discuss some of the important issues raised by the hon. President. When the number of patents increased four times, what is the technology development with the help of four time increase in patents? What is the level of income generated to the country as well as the employment opportunities for technical students?

The President has highlighted that a total of 5.54 crore new entrepreneurs have been enrolled in the country under the MUDRA finance scheme facility. In this respect, if each entrepreneur creates one job in India, why is there an employment crisis in Indian job market?

Hon. President highlighted with pride the improvement in the global rankings in the ease of doing business. It is said that our ranking has improved in the Global Innovation Rankings also from 74th to 52nd. Then, what is its impact on technology and what is its impact on innovative products, industrial development, employment market and export performance of India?

His Address mentioned that India has strengthened its foundation in several sectors during the last five to six years and hence people can see a new India. Now, we are looking at a new India which never happened in India and in its economy, particularly in terms of GDP and currency value. The GDP has drastically reduced, unemployment rate has increased, and inflation has increased to a historical level. Is this the new India?

The hon. President, in his Address, often highlighted about the status of Jammu and Kashmir and its issues. The Government should go and elicit the opinion of the people of that region.

In addition to this, according to the World Human Happiness Index, 2019, India Happiness Index Rate is ranked at 140th out of 156 countries, which was at

133rd earlier. Even our neighbouring countries in South-East Asia region are ranked better in the Happiness Index. The parameters for Happiness Index are, GDP, per capita income, social support, freedom to make life choices, perception of corruption, generosity, healthcare, etc. In this respect, the President says that people are safe and happier in India but the world ranking indicates Indians' happiness is not up to the mark. It is said that the Government is committed to transparency and good governance.

The President has emphasised that 60 lakh beneficiaries availed of the pension schemes. In this respect, can the Government, with its transparency, list out the State-wise, district-wise details of beneficiaries? The amount paid to farmers' families under the PM Kisan Samman Nidhi of Rs. 43,000 crore is done as a reactionary measure after the farmers either lost their lives or shifted or migrated towards other livelihood options. When the growth in small cities is 45 per cent to 50 per cent, then what makes the rural youth to migrate towards urban areas? What are the employment opportunities and what is the industrial growth rate in Tier I and II cities? Though sufficient funds have been allocated for higher education and even after appointing more than 7,000 teachers in Kendriya Vidyalaya schools, still the elementary and the higher elementary school students' reading and writing performance is still very poor especially in rural and Government institutions. In addition to this, higher education students' aptitude, analytical and application-oriented skills are drastically reducing.

Hence the educational qualities so far constructed are being diluted. The government introduced the NEET examination and it is common to all Indians. What has been the status of students of Jammu and Kashmir for the past six months without having schools or classes? This is one example. The NEET examination is biased against the Indian students and it is a jolt for the students and parents.

The Government is committed to attain the goal of making India a five trillion USD economy. There is no indication to attain the goal. The Government is hugely dependent on FDI, but FDI is not the only factor. There are other internal factors also which are highly serious in respect of small scale industrial growth. GST issues, demonetisation, improper banking, financial systems, employment issues, agriculture issues – all are able to pull down the economy. The current GDP performance is not matching with the original idea of creating 5 trillion USD economy.

The Government has initiated measures to enhance women's safety by establishing 600 One-Stop Centres and 1000 Fast Track Special Courts to inquire the offences. In this matter, the number of courts is not a remedial measure to sort out this issue. In 2019, the number of sexual harassment cases has been increased by 14 per cent even in the corporate sector, which is a high volume irrespective of the measures taken. It shows that there is a lacuna in the policy

formation. In child abuse cases, everyday there is registration of 133 cases, which means one case for every five minutes. Rape cases registered have increased from 4,335 in 2018 to 5,997 in 2019 which is a drastic increase of 34 per cent. It means around 16 women per day are affected and registered rape cases accordingly. What are the remedial measures?

The Government is proud of opening bank accounts for 38 crore Indian citizens. In this regard, have you given any guarantee to earn a minimum amount to fulfil the needs his day to day life and also whether there are any chances to highlight even after six months or one year the balance in his bank account?

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, Sir. One thing I have to say that our President's Speech was the most disappointing one. It is being said that the CAA was passed to fulfil the dreams of Mahatma Gandhi. In fact, all I want to say is that there must be a limit in defaming Mahatma Gandhi and distorting his dreams and ideals.

Godse killed Gandhi by shooting right to his chest. But before murdering him, Godse himself came to Gandhi, bowed at Gandhi's feet, and then only he made up his mind to shot Gandhi down.

Now, by passing the CAA saying that it is to fulfil the dreams of Gandhi, what really happened is, you have killed the soul of Gandhi too. Actually, you are not fulfilling Gandhiji's dream but fulfilling the dreams of Godse, Savarkar, Golwalkar and B.S. Moonje.

Sir, we all know the dream and thought of Gandhiji. His dream was, 'India's heart is Hindu-Muslim unity'. In his many speeches, he added that this land is for Ram and Rahim. He opposed the division of our country. When it happened, he said: "My heart also parted into two pieces." But your Government has crushed his dream of unity through this law. So, my humble request is that, do not use his name for this shameful Act.

Now, it is time for you to think of your allies. Where do they stand right now? Many of your allies who lent support for passing the CAA in the Parliament,

have now started talking against the CAA. This shows the power of general will of the people. At this moment, people of this country are on the streets, particularly the youth. They stand united in leading the protest against your divisive politics.

17.50 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

Ministers like Shri Anurag Singh Thakur are now spreading the politics of hatred and thereby calling your followers to gun down the people who are protesting against the CAA.

This signifies that you are not yet ready to renounce the politics of violence. So, in a metaphorical sense, you still love to keep Godse's gun with you.

Why are you not ready to include the terrorist organisation named *Sanathan Sanstha* under the UAPA list though it has been proved that this organisation is behind the killing of Dr Kalburgi, Narendra Dabholkar, Govind Pansare and Gowri Lankesh? Again, why do you seem to be hesitant to ban the *Hindu Raksha Dal* despite their claim regarding the masked attack against the JNU students?

You had asked to vote in the name of nationalism, and you used nationalism as a tool for sowing the seeds of communal divide. Now, the entire world has come to know that you have no reverence to the Constitution and that

all you want is to create a Hindu theocratic State by destroying the persisting secular tradition of India.

In *Vicharadhara* (Bunch of Thoughts), your philosopher and ideologue, Madhav Sadashiv Golwalkar, has expressed his thoughts on the Indian Constitution in this manner :

> "Our Constitution too is just a cumbersome and heterogeneous piecing together of various articles from various Constitutions of Western countries. It has absolutely nothing, which can be called our own. Is there a single word of reference in its guiding principles as to what our national mission is and what our keynote in life is? No! Some lame principles from the United Nations Charter or from the Charter of the now defunct League of Nations and some features form the American and British Constitutions have been just brought together in a mere hotchpotch. In other words, there is no reflection of Indian precepts or political philosophy in the Indian Constitution."

Now, the citizens of this country have understood that you still reside in a house made of Golwalkar's abominable thinking. Those who protest against the CAA are actually the ones who love the nation; are the real protectors of the Constitution; and true patriots. You keep on proving that you are not the saviours of the Constitution, but rather the killers of the Constitution.

All that I am going to reiterate here are those things that I have already stated in my previous speech. As I saw hon. Modi ji bowing and respectfully touching the Constitution with his forehead before taking charge as the Prime

Minister, it reminded me of a custom existing in some of the social communities in India related to death, namely, when the dearest ones would die, the relatives of the departed person would come and bow in front of the dead body before the burial ceremony takes place. This is called as 'last kiss'. This is exactly what our PM, Shri Narendra Modi, was seen doing, namely, 'last kiss' to the Constitution. All legislations that his current Government try to pass are in one way or the other capable enough to kill either the spirit of the Constitution or the value of Constitutionalism in this country.

The example that I can draw here in this context is that while the divorce-related laws remain a part of civil procedure for rest of the communities, but for Muslims it becomes an exclusive matter falling under the purview of the criminal procedure. Even though, we already have the Supreme Court ruling pointing out the illegality of *Triple Talaq*, the Modi Government has passed a new law. This new law has a provision that permits either the divorcee or her blood relatives to file criminal case against the husband. Moreover, the same law also has a provision that suggests imprisonment of the husband for three years without granting bail. Here comes the pertinent question. How is the husband -- who has been imprisoned under this new law -- supposed to provide maintenance to the divorcee? It seems that they are trying to put Muslim males into jail by using the family problems arising in the Muslim families.

On the one side, the Modi Government retained the special status of North-Eastern States under Article 371, and on the other side the same Government abrogated Article 370 and took away the special status enjoyed by Jammu and Kashmir. You have not only divided Jammu and Kashmir into two, but also you have put all the people of that State under house arrest.

Further, the Government has shut down the internet facility in Jammu & Kashmir and also created a situation similar to internal emergency. The Government has literally put the State into a socio-political stalemate. All of us know that the Government has passed this Bill in the name of *Desh Prem* to target one community. In fact, they are misusing the political mandate to create a *Hindu Rashtra* in this country. The biggest irony is that they use the same Constitutional Right of the Government to tear down the Constitution of India.

HON. SPEAKER: Please conclude.

ADV. A.M. ARIFF: They are pushing this country on the verge of an organised political anarchy. They are promoting State-sponsored violence. In U.P., so far, nineteen people have lost their lives in various incidents of State-sponsored violence.

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर जी, आपको 6 बजे तक बोलना है । 6 बजे सदन आज स्थगित किया जाएगा ।

…(व्यवधान)

ADV. A.M. ARIFF: Sir, I will take only one minute. Much of this State-sponsored violence is taking place in the States where the BJP is in power. At the same time, the Government is selling off almost all the public sector companies. Their wrong economic policies have brought an unprecedented economic slowdown in this country. Now, they are using this self-created economic slowdown as an excuse to sell off the public sector companies in the country. In Malayalam, there is a proverb "*Purakathumbol Vazha Vettuka*" which means cut the plantation tree where the house is burning.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जब हम कलेक्टिव सदन में थे, तो सुन रहे थे कि किसानों की आय डबल करेंगे। एक बार यह भी सुना कि जितना फसल पर खर्च आता है, उसका डेढ़ गुना करेंगे। गन्ना किसान पूरे देश में हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा हैं। पिछले तीन साल से 1 भी पैसा नहीं बढ़ा है। जब 17वीं लोक सभा का पहला सत्र शुरू हुआ ...(व्यवधान) जब आप बोलते हैं, तो हम नहीं बोलते हैं। मुझे दो मिनट बोलने दीजिए। पहले सत्र में भी हमने गन्ने का मुद्दा रेट फाइनल होने से पहले उठाया। सरकार ने नहीं सुनी, नहीं बढ़ाया। जब फैसला ले लिया, दोबारा से हमने यह मुद्दा उठाया और अभी तक सुना नहीं गया है। 6 जनवरी को, फाइनेंस कमेटी कंसल्टेटिव कमेटी में मैं हूं, मैंने यह मुद्दा उठाया और एग्रीकल्चर को देश की इकोनॉमी से जोड़कर वित्त मंत्री जी को रिक्वैस्ट की, सलाह दी कि किसानों को बचाना बहुत जरूरी है और यह बात वहां रखी। उन्होंने आवश्वासन भी दिया कि हम जरूर इसके बारे में बजट में कुछ सोचेंगे। 9 और 10 में, लॉ एंड जस्टिस में भी मैं हूं, यह मुद्दा हमने वहां भी उठाया। तीन साल की बढ़ी हुई महंगाई, एक बार 8 पाइंट कुछ, 7 पाइंट कुछ और 6 पाइंट कुछ और इस साल की 5 पाइंट बताते हैं, तो 28 पर्सेंट बैठती है। 28 पर्सेंट के हिसाब से, तो 325 रुपये गन्ने का जो रेट है, अगर उसे कैलकुलेट करें तो वह 90 रुपये बैठता है। अगर सरकार ने रेट नहीं बढ़ाया, तो 90 रुपये उलटा घटा दिया। ऐसी स्थिति में किसान की आय डबल कैसे होगी? एक तो यह सोचने की बात है और इस पर गौर करने की बात है।

माननीय अध्यक्ष : आप बता दीजिए कि कैसी बढ़ेगी?

श्री मलूक नागर : मैं बताता हूं। सरकार का फार्मूला है। सारे मंत्री यहां बैठे हैं, मैं फार्मूला देता हूं। हमारे मेरठ के राजेन्द्र अग्रवाल जी हैं, संजीव बालियान जी यहां नहीं हैं, नहीं तो ये भी मेरी बात को सपोर्ट करते। दूसरा, इन्होंने एक फार्मूला निकाला कि जितना खर्च किसान का आएगा, उसका हम डेढ़ गुना

देंगे। क्या सरकार ने सोचा है कि किसान के घर में जितने भी लोग हैं, उनका जो न्यूनतम वेतन है, उसे कैलकुलेट करेंगे, बीज का जो रेट बढ़ा, उसको कैलकुलेट करेंगे, बिजली का जो रेट बढ़ा, उसे कैलकुलेट करेंगे? किसानों के उपकरण पर जो इन्होंने जीएसटी लगाया, 10 पर्सेंट और 10 पर्सेंट, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। समझ नहीं आता, एक तरफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ ले रहे हैं। सीधा जीएसटी हटा दो। क्या उसको कैलकुलेट करेंगे? अगर हम पूरे को कैलकुलेट करें, तो 350 रुपये आज गन्ने की लागत आती है।

18.00 hrs

साढ़े पांच सौ रुपये सरकार कहती है, साढ़े पांच सौ रुपये आता है। आपने पूछा, मैंने बता दिया। साढ़े पांच सौ रुपये अपने हस्तक्षेप से कराकर करवा दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपसे यह नहीं कहा था कि रेट बता दो, कैसे बढ़ाएंगे उसका सुझाव दो।

श्री मलूक नागर: महोदय, प्रवेश वर्मा जी बोल रहे थे। एक घंटे में उन्होंने अच्छी-अच्छी बातें भी बोलीं, जिसमें आज सदन की बात कम थी और दिल्ली के प्रचार की बात ज्यादा थी, लेकिन अच्छी बात बोल दी। वह संविधान की ओरिजिनल कॉपी लेकर आए। उन्होंने श्रीरामचन्द्र भगवान जी की तस्वीर दिखाई और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर दिखाई।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भगवान-भगवान में भी क्यों फर्क करते हैं? अयोध्या के लिए जितना बजट है, मथुरा के लिए हेमा मालिनी जी से पूछें कि क्या उतना ही बजट रखा? हस्तिनापुर मेरे लोक सभा क्षेत्र में है। वहां के लिए संग्रहालय की घोषणा जरूर की गई है लेकिन क्या हस्तिनापुर में भगवान श्रीकृष्ण जी पृथक रूप से रहें, वहां की बात आपको याद नहीं आई? हमने इस मुद्दे को कितनी बार सदन में उठाया, लिखित में भी उठाया, रेलवे कमेटी की मीटिंग में भी उठाया

लेकिन वहां के लिए रेल का कोई प्रोविजन नहीं किया, वहां के लिए क्यों नहीं सोचा? इस बारे में कहना चाह रहे थे। रूलिंग पार्टी की तरफ से जो मुझे टाइम मिला और आपकी तरफ से टाइम मिला, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 04 फरवरी, 2020 को सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, February 04, 2020/ Magha 15, 1941 (Saka).